



वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2019

पलायन, विस्थापन और शिक्षा: संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Sustainable
Development
Goals



Global
Education
Monitoring
Report

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2019

पलायन, विस्थापन और शिक्षा:

संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं

शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा-पत्र और कार्य ढांचे में इस आदेश का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में “एसडीजी 4 पर तथा अन्य एसडीजी में शिक्षा की निगरानी और रिपोर्ट करने की प्रणाली होनी चाहिए” जिसकी जवाबदेही “राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों को लागू करना होगा ताकि संपूर्ण एसडीजी पर बाद में की जाने वाली कार्रवाई एवं समीक्षा के एक भाग के रूप में इससे जुड़े सभी भागीदारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायता की जा सके”। इसे यूनेस्को द्वारा गठित एक स्वतंत्र टीम द्वारा तैयार किया गया है।

इस प्रकाशन में दिए गए पदनाम और प्रस्तुत सामग्री का अर्थ किसी देश, प्रादेशिक सीमा, नगर या क्षेत्र या इसके प्राधिकारियों या इसकी सीमाओं का सीमांकन करने के संबंध में यूनेस्को की ओर से कोई राय, जो कोई भी हो, अभिव्यक्ति करना नहीं है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट दल इस रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के चयन और प्रस्तुति तथा इसमें व्यक्त राय के लिए जिम्मेदार है। यह जरूरी नहीं कि इसमें व्यक्त विचार यूनेस्को के हों, और संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है। रिपोर्ट में व्यक्त विचारों और राय की पूरी जिम्मेदारी इसके निदेशक की है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम

निदेशक : मैनुस एंटोनिनिस

डैनियल अप्रैल, बिलाल बराकैट, मैडलेन बैरी, निकोल बेला, अन्ना क्रिस्टीना डी'एडियो, ग्लेन हर्टेलेडी, सेबेस्टियन हिन, प्रियदर्शनी जोशी, कटारजीना कुबका, केट लिंकिन्स, लीला लोपिस, कासियानी लिथ्रैंगोमाइटिस, अलास्डेयर मैकविल्लियम, अनिसा मेचतर, क्लाउडिन मुकिजवा, युकी मुराकामी, कार्लोस अल्फोन्सो ओब्रेगोन मेलगर, जुडिथ रैंडियानाटोविना, केट रेडमैन, मारिया रोजनोव, अन्ना ईवा रूसजकिविज़, विल स्मिथ, रोसा विडार्ट और लेमा जेक्रया।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है। जीईएम रिपोर्ट का वित्त-पोषण सरकारों, बहु-स्तरीय एजेंसियों और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा किया जाता है और इसके लिए सहायता और सुविधा यूनेस्को द्वारा प्रदान की जाती है।



MINISTRY FOR FOREIGN
AFFAIRS OF FINLAND



यह प्रकाशन ऐट्रिब्यूशन-शेयरएलाइक 3.0 आईजीओ (सीसी-बीवाई-एसए 3.0 आईजीओ) लाइसेंस (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>) के अंतर्गत सभी के लिए उपलब्ध है। इस प्रकाशन की सामग्री का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करने वाला यूनेस्को के सर्व सुलभ संग्रह (<http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en>) के इस्तेमाल की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।

वर्तमान लाइसेंस विशेष रूप से प्रकाशन की पाठ्य सामग्री पर लागू होता है। किसी भी सामग्री के प्रयोग के लिए, जो स्पष्ट रूप से यूनेस्को से संबंधित न हो, के लिए निम्नलिखित से पूर्व अनुमति का अनुरोध किया जाएगा: publication-copyright@unesco.org या यूनेस्को पब्लिशिंग, 7, प्ले डी फोन्टेनोए, 75352 पेरिस 07 एसपी फ्रांस।



अंग्रेजी में मूल शीर्षक: वैश्विक शिक्षा निगरानी मार्च 2019: पलायन, विस्थापन और शिक्षा: संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं।

इस प्रकाशन को इस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है: यूनेस्को 2018. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार 2019: पलायन, विस्थापन और शिक्षा - संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं। पेरिस, यूनेस्को।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

ग्लोबल शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम
द्वारा यूनेस्को, 7, प्लेस डे फोन्टेनोए
75352 पेरिस 07 एसपी, फ्रांस
ई-मेल: gemreport@unesco.org
दूरभाष: +33 145 680741
www.unesco.org/gemreport
<https://gemreportunesco.wordpress.com>

मुद्रण में बाद में पाई गई किसी भूल-चूक को
ऑनलाइन पाठ www.unesco.org/gemreport
में सुधारा जाएगा।

© यूनेस्को, 2018
सर्वाधिकार सुरक्षित
प्रथम संस्करण
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और
सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2018 में प्रकाशित

7, प्लेस डे फोन्टेनोए, 75352
पेरिस 07 एसपी, फ्रांस

यूनेस्को द्वारा टाइपसेट
ग्राफिक डिजाइन एफएचआई 360 द्वारा
लेआउट यूनेस्को द्वारा

नई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

- 2019 पलायन, विस्थापन और शिक्षा: संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं
- 2017/8 शिक्षा में जवाबदेही: अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए
- 2016 लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा: सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

- 2015 सभी के लिए 2000-2015 तक शिक्षा: उपलब्धियां और चुनौतियां
- 2013/4 अध्यापन और शिक्षण: सभी के लिए गुणवत्ता प्राप्त करना।
- 2012 युवा और कौशल: शिक्षा को कार्य से जोड़ना
- 2011 छिपा संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा
- 2010 उपेक्षित वर्गों तक पहुंच बनाना
- 2009 असमानता दूर करना: शासन क्यों जरूरी है
- 2008 2015 तक सभी के लिए शिक्षा : क्या हम इसे पूरा करेंगे?
- 2007 ठोस आधार : शुरुआती बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा
- 2006 जीवन के लिए साक्षरता
- 2005 सभी के लिए शिक्षा: गुणवत्ता की अनिवार्यता
- 2003/4 जेंडर और सभी के लिए शिक्षा: समानता की ओर कदम
- 2002 सभी के लिए शिक्षा: क्या दुनिया सही रास्ते पर है?

आवरण चित्र: रूशदी सराज/यूएनआरडब्ल्यूए
शीर्षक: गाजा में फिलिस्तीन शरणार्थी छात्र दूसरे सेमेस्टर में यूएनआरडब्ल्यूए स्कूलों में अपने पहले दिन हाउसटोनिक डिजाइन नेटवर्क द्वारा इनफोग्राफिक्स

यह सारांश रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्रियां <http://bit.ly/2019gemreport>

से डाउनलोड की जा सकती हैं।



प्रस्तावना

लोग हमेशा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं, कुछ बेहतर अवसरों की तलाश में जाते हैं तो कुछ खतरों से डर कर भाग जाते हैं। इस तरह आने-जाने से शिक्षा पद्धति पर काफी असर पड़ सकता है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2019 का यह संस्करण दुनिया के सभी हिस्सों में इन मुद्दों का गहराई से पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला तरीका है।

यह रिपोर्ट सही समय पर आई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को अंतिम रूप दिया है: सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित पलायन का वैश्विक प्रभाव, और शरणार्थियों पर वैश्विक प्रभाव। इन अभूतपूर्व समझौतों में - चौथे संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य में शामिल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ - प्रवासियों और विस्थापित लोगों की शिक्षा की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह जीईएम रिपोर्ट हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नीति निर्माताओं के लिए एक आवश्यक संदर्भ है।

वर्तमान में, कानून और नीतियां प्रवासी और शरणार्थी बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में असफल रही हैं और उनकी जरूरतों को अनदेखा कर रही हैं। पलायन करने वाले, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग दुनिया के सबसे प्रभावित लोगों में से हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो जैसे-तैसे आजीविका कमाने के लिए मौसम के अनुसार पलायन करते हैं और हिरासत में रहने वाले बच्चे। प्रायः उन्हें स्कूलों में दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित आश्रय और बेहतर भविष्य देने का वादा कर सकते हैं।

प्रवासियों की शिक्षा को अनदेखा करना मानव क्षमता को गंवाना और नज़रअंदाज़ करना है। कभी-कभार मामूली कागजी कार्रवाई, डेटा का अभाव या नौकरशाही और असंगठित प्रणालियों की कमी का खामियाज़ा कई लोगों को बेवजह भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि अत्यधिक प्रतिभाशाली और प्रेरित प्रवासियों और शरणार्थियों की शिक्षा में निवेश किया जाए तो वे न केवल मेजबान देश बल्कि मूल देशों में विकास और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

केवल शिक्षा का प्रावधान करना ही पर्याप्त नहीं है। स्कूल के परिवेश को प्रवासी लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढालने और उनमें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। आप्रवासियों और शरणार्थियों को मेजबान देश की आबादी के साथ एक ही स्कूल में रखना सामाजिक समरसता और सौहार्द्र कायम करने की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहल है। हालांकि, जिस तरीके से और जिस भाषा में पाठ पढ़ाए जाते हैं, और भेदभाव बरता जाता है, वह उनमें दूरियां बढ़ा सकता है।

भली-भांति प्रशिक्षित शिक्षक आप्रवासी और शरणार्थी विद्यार्थियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक कक्षाओं को चलाने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, और इनमें प्रायः मनोवैज्ञानिक आवश्यकता वाले छात्र भी शामिल होते हैं।

एक बेहतर ढंग से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम अहम भूमिका अदा करता है, जो विविधता को बढ़ावा दे, महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करे तथा विषम परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने का साहस दे, और कक्षा की चारदीवारी से परे सकारात्मक सोच पैदा करे। कभी-कभार पाठ्यपुस्तकों में पलायन की पुरानी तस्वीर का चित्रण किया जाता है और उन्हें अपनाने के प्रयासों को कम करके आंका जाता है। कई पाठ्यक्रमों में पलायन करने वालों की जीवन शैली को सही रूप में भी नहीं दर्शाया जाता।

पलायन करने वालों के लिए प्रावधान का विस्तार करने और उन्हें अपनाने के लिए निवेश की जरूरत होती है, जो कई मेजबान देश अकेले पूरा नहीं कर सकते। मानवीय सहायता वर्तमान में बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि यह अक्सर सीमित और अप्रत्याशित होती है। नई शिक्षा इंतजार नहीं कर सकती, निधियां सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों तक पहुंच बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।

इस रिपोर्ट का संदेश स्पष्ट है: प्रवासी लोगों की शिक्षा में निवेश करना, निराशा और अशांति के मार्ग और एकजुटता और शांति के मार्ग के बीच अंतर करना है।

आउट्रे अजौले
यूनेस्को के महानिदेशक

Andrey Aronov



भूमिका

2019 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के एक दल द्वारा किया गया है। इसके चार सदस्य शरणार्थियों के बच्चे हैं। वे इस बात से इनकार नहीं करते कि लोग पलायन - और प्रवासियों को अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका शोध दर्शाता है कि शिक्षा किस हद तक संभावनाओं को पंख लगा सकती है, और सभी के लिए व्यापक अवसर खोल सकती है।

प्रवासियों, शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों के लिए, ज्ञात और अज्ञात होता है। हालांकि, कुछ लोगों इतना जानते हैं कि वे वंचित हैं और वे इससे बचने चाहते हैं; लेकिन वे यह नहीं जानते कि दूसरे छोर पर अवसर उपलब्ध होंगे या नहीं। जबकि मेज़बान समुदायों में, लोगों को यह पता नहीं हो सकता है कि उनके नए पड़ोसी, जिनकी वेशभूषा, रीति-रिवाज भिन्न है, और जिनकी भाषा अलग है, उनका जीवन बदल पाएंगे।

पलायन में व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों हो सकती हैं। समाज अक्सर जन आंदोलनों का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लोगों की अप्रत्याशित संख्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसे आंदोलन नया विभाजन पैदा कर सकते हैं, जबकि कई आंदोलनों से स्रोत और गंतव्य, दोनों देशों को फायदा होता है।

व्यापक रूप से पलायन होने में, हम इच्छा और मजबूती दोनों देखते हैं। कुछ लोग सक्रिय रूप से काम करने और अध्ययन करने के लिए आगे आते हैं जबकि कुछ लोगों को उत्पीड़न और धमकियों के कारण अपनी आजीविका छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेज़बान समुदाय और राजनेता अंततः तर्क दे सकते हैं कि आने वाले लोग वैध हैं या अवैध, वरदान हैं या खतरा, या बहुमूल्य हैं या बोझ हैं।

इनका स्वागत भी होता है और इन्हें अस्वीकार भी किया जाता है। कुछ लोग अपने नए परिवेश में घुल-मिल जाते हैं जबकि कुछ ऐसा नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें खदेड़ना चाहते हैं।

इस प्रकार, दुनिया भर में, हम देखते हैं कि पलायन और विस्थापन एक व्यापक जुनून की तरह उभरा है। फिर भी कुछ निर्णय लेने होंगे। पलायन के लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। हम बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, या दूसरी तरफ पहुंचकर - विश्वास पैदा कर सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं, उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने पलायन और विस्थापन चुनौतियों का स्थायी समाधान निकालने के लिए आसपास के राष्ट्रों को एक मंच पर लाने की दिशा में काम किया है। 2016 में शरणार्थियों और प्रवासियों पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान, मैंने संघर्ष रोकने, मध्यस्थता, सुशासन, कानूनी शासन, और समग्र आर्थिक विकास में निवेश करने की मांग की थी। मैंने असमानता से निपटने के लिए प्रवासियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिलाया था।

यह रिपोर्ट हमें उस अंतिम बिंदु की याद दिलाती है कि शिक्षा प्रदान करना न केवल शासन में बैठे लोगों का नैतिक दायित्व है, बल्कि पलायन होने वाली जनसंख्या की समस्याओं से निपटना भी एक कारगर तरीका है। यह पलायन और विस्थापन से निपटने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, और हमेशा होना चाहिए - यह एक ऐसा विचार है जिसे अमल में लाने का समय अब आ गया है, जैसा कि प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए हुए दो वैश्विक समझौतों में दर्शाया गया है।

जिन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, उनमें उपेक्षा और हताशा उत्पन्न हो सकती है। जब गलत दंग से पढ़ाया जाए, तो शिक्षा इतिहास को विकृत कर सकती है और गलतफहमी का कारण बन सकती है।

लेकिन, जैसा कि रिपोर्ट से हमें कनाडा, चाड, कोलंबिया, आयरलैंड, लेबनान, फिलीपींस, तुर्की और युगांडा में कई उत्साहजनक उदाहरणों का पता चलता है, उनमें शिक्षा भी एक सेतु का कार्य कर सकती है। शिक्षा लोगों की अच्छाई को बाहर ला सकती है, और लीक पर चलने, पूर्वाग्रह, और भेदभाव का मार्ग छोड़कर सकारात्मक सोच, एकजुटता और खुलेपन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह उन लोगों को मदद का हाथ बढ़ा सकती है जो पीड़ित हैं और उन लोगों के लिए बेशुमार अवसर पैदा कर सकती है जिन्हें अवसर की बेहद जरूरत है।

यह रिपोर्ट सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करती है: इसमें सहायता करने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। यह हमें मानवता और पलायन की सदियों पुरानी घटनाओं में झांकने का अवसर प्रदान करती है। मैं आपको इसकी सिफारिशों पर विचार करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

द राइट माननीय हेलेन क्लार्क
अध्यक्ष जीईएम रिपोर्ट सलाहकार बोर्ड

Allen Clarke



पलायन, विस्थापन और शिक्षा

पलायन और विस्थापन की अनेक कहानियां दुनिया भर में सुनने को मिलती हैं। महत्वाकांक्षा, आशा, भय, प्रत्याशा, सरलता, पूर्ति, बलिदान, साहस, दृढ़ता और संकट की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि 'पलायन गरिमा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मानव आकांक्षा की एक अभिव्यक्ति है। यह सामाजिक ताने-बाने का एक हिस्सा है, मानव परिवार के रूप में हमारा हिस्सा है। फिर भी पलायन और विस्थापन 'राज्यों और समाजों के भीतर और उसके बीच विभाजन का एक स्रोत रहा है... हाल के वर्षों में, प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ-साथ हताश लोगों के बड़े आंदोलनों ने प्रवासियों की उम्मीदों पर कुठाराघात किया है।

सतत विकास एजेंडा 2030 में औपचारिक रूप से शामिल सामान्य नियति के लिए साझा जिम्मेदारी का प्रावधान है, लेकिन आधुनिक समाज में पलायन और विस्थापन के प्रति कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया बनी हुई है। इनका अवसरवादियों द्वारा शोषण किया जाता है जो रिश्ता बनाने की बजाय बाधाएं खड़ी करने में लाभ देखते हैं। यहीं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में सभी राष्ट्रों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका अहम हो जाती है।

यह रिपोर्ट विविध कक्षाओं, विद्यालयों, समुदायों, श्रम बाजारों और समाज की वास्तविकता का सामना करने वाले शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों के नज़रिए से पलायन और विस्थापन को देखती है। दुनिया भर में शिक्षा प्रणाली 'समग्र और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने' और 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' की प्रतिबद्धता के लिए एकजुट हैं। सभी छात्रों अपने सपनों को साकार कर सकें, व्यवस्था को उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी जरूरतों को ध्यान में रखने हुए समायोजन करना होगा। उन्हें समाज के प्रति लचीला रवैया अपनाने और पलायन और विस्थापन के अनुकूल बनने की जरूरत है - यह बड़े और छोटे प्रवासी और शरणार्थी आबादी वाले देशों को समान रूप से प्रभावित करने वाली चुनौती है।

इसमें सभी प्रकार के जन आंदोलन शामिल हैं। औसतन, 8 में से 1 व्यक्ति आंतरिक प्रवासी है। इस पलायन का उन लोगों के शैक्षिक अवसरों पर गंभीर असर पड़ सकता है और जो पिछड़ चुके हैं, खासतौर पर उन कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जहां शहरीकरण तेजी से हो रहा है। 30 लोगों में से लगभग 1 व्यक्ति, जिस देश में वे पैदा हुए थे, उससे भिन्न देश में रहते हैं। लगभग दो-तिहाई अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उच्च आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि ज्यादातर काम पर जाते हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास भी उनके वंशजों की शिक्षा को प्रभावित करता है। 80 लोगों में से 1 व्यक्ति संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं के कारण सीमाओं को पार करते हैं। इनमें से, दस में से नौ निम्न आय वाले देशों में रहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शामिल करना महत्वपूर्ण है लेकिन विस्थापन के विशिष्ट संदर्भों द्वारा इसमें शर्तें लगाई जा सकती हैं।

पलायन और विस्थापन, दो-तरफा जटिल रिश्तों के द्वारा शिक्षा पर आधारित होता है जो प्रवासियों को प्रभावित करता है, जो पलायन करते हैं तथा जो प्रवासियों और शरणार्थियों की तरह रहते हैं या उनकी मेजबानी करते हैं (तालिका 1)। जब जीवन चक्र में लोग पलायन के बारे में सोचते हैं या उन पर विचार करते हैं तो यह शिक्षा निवेश, बाधा, अनुभव और परिणाम का एक प्रमुख निर्धारक होता है। शिक्षा के विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों से पलायन करने वाले बच्चों को

तालिका 1:

शिक्षा और पलायन/विस्थापन के बीच संबंधों के कुछ उदाहरण

	शिक्षा पर प्रवासन/विस्थान का प्रभाव	पलायन/विस्थापन पर शिक्षा का प्रभाव
मूल	<ul style="list-style-type: none"> प्रवासन गंदी बस्तियों में प्रावधान उपलब्ध करने की चुनौतियों का कारण बनता है। शिक्षा प्रणालियों को मौसमी या चक्रण पैटर्न में आने-जाने वाली आबादी की जरूरतों को समायोजित करना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> अधिक शिक्षित लोगों के पलायन होने की संभावना अधिक होती है।
पीछे रहने वाले	<ul style="list-style-type: none"> पलायन ग्रामीण क्षेत्रों को वीरान करता है और शिक्षा प्रावधान को चुनौती देता है। भेजा गया धन मूल समुदायों में शिक्षा को प्रभावित करता है। माता-पिता की अनुपस्थिति से बच्चे पिछड़ जाते हैं। पलायन की संभावना शिक्षा में निवेश को हतोत्साहित करती है। नए कार्यक्रम इच्छुक प्रवासियों को तैयार करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षित लोगों के पलायन का प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर असर पड़ता है, उदाहरण के लिए प्रतिभा पलायन।
गंतव्य स्थल	<ul style="list-style-type: none"> आप्रवासियों और उनके बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति और उपलब्धि आमतौर पर मूल निवासी से पिछड़ जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में शरणार्थियों को शामिल करने की जरूरत है। शरणार्थियों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रवासी अधिक योग्य हो सकते हैं, उनके कौशल को पूरी तरह से पहचाना या उपयोग नहीं किया जाता है, और उनकी आजीविका बदल जाती है। उच्च स्तरीय शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण छात्र गतिशीलता को प्रेरित करता है।
मूल निवासी	<ul style="list-style-type: none"> कक्षाओं में विविधता के लिए बेहतर तैयार शिक्षकों, लक्षित कार्यक्रमों को नए प्रवासियों का समर्थन करने और अलगाव को रोकने और डेटा को अलग करने की आवश्यकता होती है। 	<ul style="list-style-type: none"> औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रबुद्ध समाज का निर्माण कर सकती है, पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम कर सकती है।

अवसर मिल सकते हैं जो अन्यथा उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकते थे। साथ ही, प्रवासी छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति और उपलब्धियां अक्सर मूल समुदायों में उनके साथियों से पिछड़ जाती हैं।

पलायन और विस्थापन के लिए उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो पलायन कर जाते हैं और वे जो पीछे छूट जाते हैं। देशों को प्रवासियों और शरणार्थियों को कानूनन शिक्षा का अधिकार देने के लिए इसे अमल में लाना होगा। उन्हें उन लोगों के अनुसार शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, खानाबदोश की तरह रहते हैं या शरणार्थी दर्जा पाने का इंतजार करते हैं। शिक्षा प्रणाली समग्र होनी चाहिए और इससे समानता की प्रतिबद्धता पूरी होनी चाहिए। शिक्षकों को पलायन और विशेषकर विस्थापन से जुड़ी विविधता और दुःख-तकलीफ से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकांश प्रवासियों और शरणार्थियों को अधिक से

“

पलायन और विस्थापन के लिए उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो पलायन कर जाते हैं और वे जो पीछे छूट जाते हैं

”

अधिक योग्य और दक्ष बनाने के लिए उन्हें शैक्षिक योग्यता और उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो दीर्घावधि में उन्हें समृद्ध बनाने में कारगर होगा।

शिक्षा भी पलायन और विस्थापन को काफी अधिक प्रभावित करती है - यह कितनी अधिक हासिल की जाती है और उसे किस रूप में समझा जाता है। शिक्षा बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने तथा पलायन का निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाती है। यह प्रवासियों के दृष्टिकोण, उनकी आकांक्षों और मान्यताओं को प्रभावित करती है, और जिस हद तक वे अपने इरादों के संबंध में भावनाएं विकसित करते हैं। कक्षाओं में व्यापक विविधता में चुनौतियां होती हैं, जिनमें मूल निवासी (विशेषकर गरीब और हाशिए पर) शामिल होते हैं, लेकिन यह अन्य संस्कृतियों और अनुभवों से सीखने का

अवसर भी प्रदान करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम पहले से कहीं अधिक संवेदनशील होना चाहिए।

पलायन और विस्थापन राजनीतिक बहस के ज्वलंत मुद्दे बन रहे हैं, शिक्षा नागरिकों को संबंधित मुद्दों के बारे में गहरी समझ पैदा करने के लिए अहम है। यह जानकारी दे सकता है और समाजों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। विशेष रूप से यह वैश्विक दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी, शिक्षा को सहिष्णुता से परे अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो मतभेद से ऊपर उठकर कार्य कर सके; यह पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद और भेदभाव से लड़ने का एक कारगर तरीका है। यदि इसकी रूपरेखा सही तरह से न बनाई जाए, तो शिक्षा प्रणाली आप्रवासियों और शरणार्थियों में नकारात्मक, आशिक, विशिष्ट या निराशाजनक सोच पैदा कर सकती है।

2019 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट पलायन, विस्थापन और शिक्षा पर वैश्विक साक्ष्य की समीक्षा करती है और इसका लक्ष्य निम्नलिखित सवालों का जवाब देना है:

- जन आंदोलन शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता को किस तरह से प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत प्रवासियों और शरणार्थियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है?
- शिक्षा उन लोगों, जो पलायन कर जाते हैं और जो समुदाय उन्हें प्राप्त करते हैं, के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है?

बॉक्स 1

दुनिया शिक्षा की व्यवस्था करने तथा प्रवासियों, विस्थापितों और मेजबान देशों की आबादी की अन्य जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रही है

स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों, विस्थापितों और मेजबान देशों की आबादी की शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना और एकजुट होकर कार्रवाई करना आवश्यक है। दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सितंबर 2016 में, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों ने जिम्मेदारी-साझाकरण तंत्र को मजबूत बनाने और प्रक्रिया को लागू करने के लिए न्यूयॉर्क घोषणा नामक दो वैश्विक समझौतों पर हस्ताक्षर किए: एक प्रवासियों, और दूसरा, शरणार्थियों के लिए था।

सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित पलायन के लिए वैश्विक समझौते के मसौदे के रूप में इस रिपोर्ट के एजेंडा में अधिकांश मुद्दों के समाधान को शामिल किया गया है। इसमें स्कूल के अंदर और बाहर शिक्षा सहित बुनियादी सेवाओं तक की पहुंच शामिल है। यद्यपि कौशल प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाता है, यह प्रवासियों को एक अवसर के रूप में शिक्षा के बारे में सकारात्मक

संदेश देती है ताकि वे विकास कर सकें। हालांकि, समझौता बाध्यकारी नहीं है और देशों पर छोड़ दिया गया है कि वे प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा करेंगे।

विस्थापित लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लोगों को नए वातावरण में समायोजित करने और लंबे विस्थापन से निपटने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। हालांकि मेजबान देशों में शरणार्थियों के शिक्षा के अधिकार की गारंटी 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दर्जा संबंधी सम्मेलन में दी गई है, शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते का उद्देश्य प्रतिबद्धता को दोहराना है। अंतिम मसौदे में शिक्षा के लिए दो अनुच्छेद समर्पित हैं, जिनमें वित्त और विशिष्ट नीतियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह समावेश पर राष्ट्रीय नीतियों के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

आंतरिक पलायन

अनुमान है कि 763 मिलियन लोग उस क्षेत्र के बाहर रहते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। विभिन्न प्रकार के संभावित आंदोलनों, चाहे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच हों या उनके भीतर, ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर तथा मौसमी या किसी निश्चित अवधि के लिए जनसंख्या पलायन करती है जो शिक्षा प्रणालियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां पैदा करती हैं।

“ अनुमान है कि 763 मिलियन लोग उस क्षेत्र के बाहर रहते हैं जहां उनका जन्म हुआ था ”

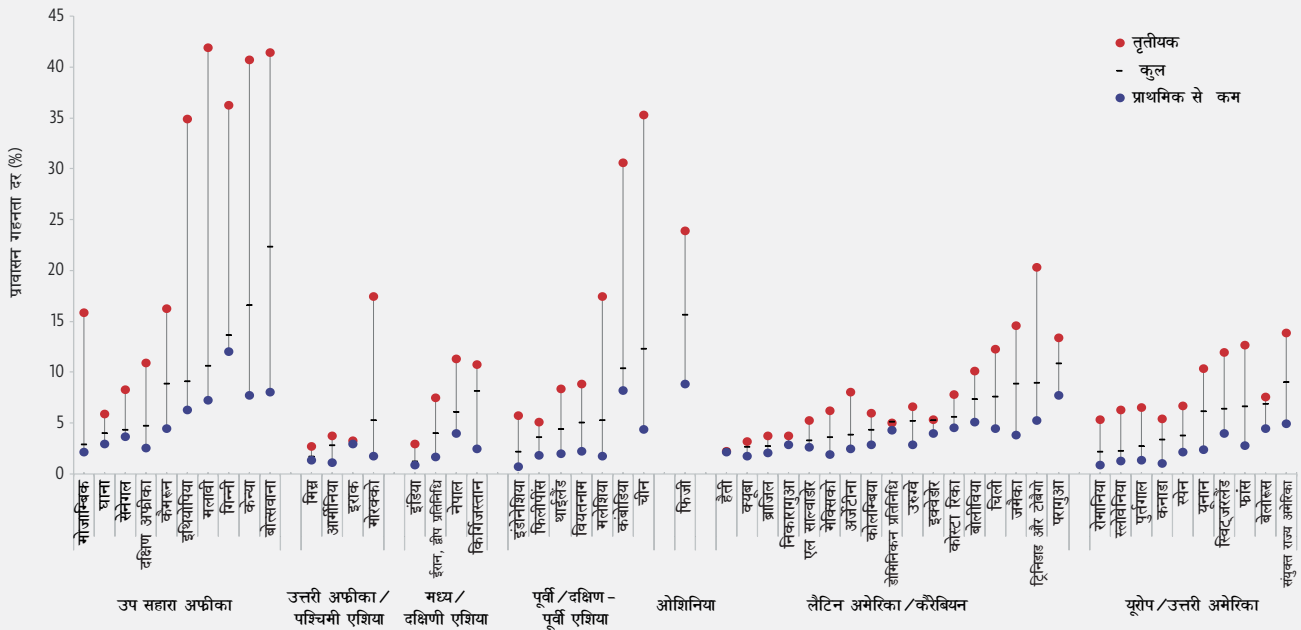
जबकि उच्च आय वाले देशों में 19वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में हुए आर्थिक विकास के साथ, बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन कर गए थे, आज सबसे बड़ा आंतरिक जन आंदोलन मध्य आय वाले देशों, विशेष रूप से चीन और भारत में होता है। उप-सहारा अफ्रीका में, ग्रामीण इलाकों से शहर की ओर होने वाले पलायन ने शहरी विकास योजना को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

पलायन दर आयु के अनुसार बदलती है लेकिन यह लोगों में 20 वर्ष की आयु में अपने चरम पर होती है। शिक्षा की दृष्टि से, आंतरिक पलायन प्राथमिक स्कूल आयु के बच्चों में अपेक्षाकृत कम और माध्यमिक स्कूल आयु के युवाओं को थोड़ा अधिक प्रभावित करता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं का पलायन करना एक प्रमुख कारण है। थाईलैंड में, 21% युवाओं ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए पलायन किया है।

अधिक शिक्षित लोगों की उनकी शिक्षा पर अधिक आय प्राप्त करने की संभावना के कारण कहीं और स्थानांतरित होने की संभावना अधिक रहती है (चित्र 1)। शिक्षा के परिणामस्वरूप प्राथमिकताएं और आकांक्षाएं लोगों को संभावित आय अर्जित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। 53 देशों में, प्राथमिक शिक्षा वाले लोगों में पलायन की संभावना दोगुनी हो गई, माध्यमिक शिक्षा वाले लोगों में तीन गुनी हो गई और उच्च स्तरीय शिक्षा वाले लोगों में चार गुनी हो गई।

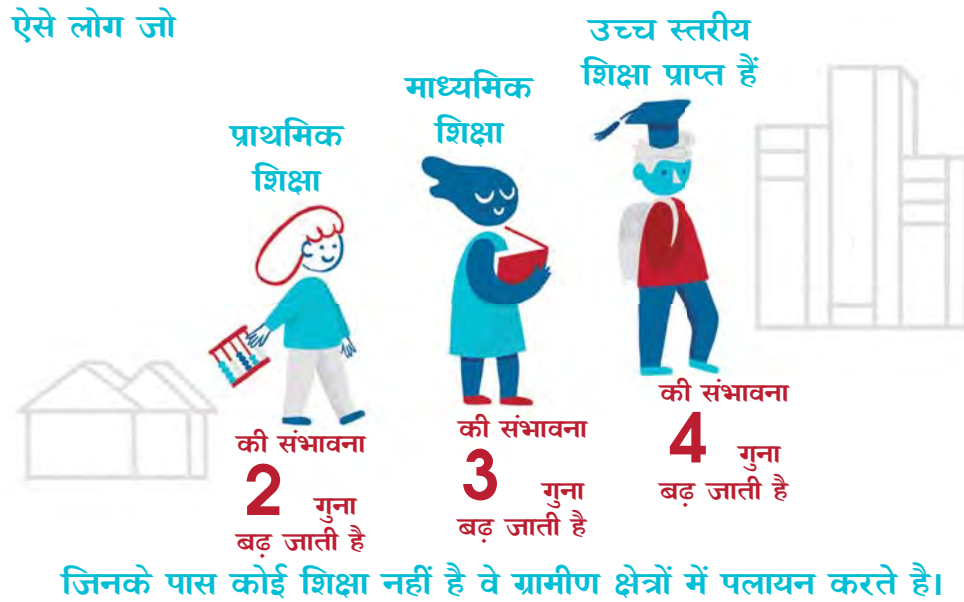
चित्र 1: अधिक शिक्षित होने पर पलायन की संभावना अधिक रहती है।

शिक्षा द्वारा पलायन की अधिकता दर, चयनित देश, पांच वर्ष की अवधि, 1999-2010



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig2_3

स्रोत: बर्नार्ड और अन्य (2018)



पलायन कुछ लोगों की शिक्षा के स्तर में सुधार करता है लेकिन सभी का नहीं

गांवों से शहर की ओर पलायन उन देशों में शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ा सकता है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच कम है। इंडोनेशिया में चयनित ग्रामीण जिलों में पैदा हुआ एक समूह, जो शहर को पलायन कर गया था, ने पलायन न करने वाले लोगों की तुलना में तीन वर्ष अधिक शिक्षा प्राप्त की थी।

फिर भी प्रवासी बच्चे अपने साथियों के समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ब्राजील में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2000/01 में पैदा हुए किशोरों में से, जो माध्यमिक स्कूल के दौरान पलायन कर गए थे, की पलायन न करने वालों किशोरों की तुलना में प्रगति दर खराब थी। आंतरिक पलायन से प्रभावित बच्चों के शैक्षिक अवसरों को कई कारणों, जैसे गरीबी की अनिश्चित कानूनी स्थिति, पर्याप्त ध्यान न दिए जाने, या पूर्वाग्रह और रूढ़िवादों से समझौता करना पड़ता है।

आंतरिक पलायन से शिक्षा की उपलब्धता प्रभावित होती है

कई देशों में, अस्थिर शहरीकरण और ग्रामीण शहरी असंतुलन के भय ने नीतियों को पलायन को रोकने के लिए प्रेरित किया है, जो कुछ मामलों में प्रवासियों की शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है। वियतनाम की हो-खाऊ प्रणाली ने पलायन करने वालों की सार्वजनिक शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया, और गरीब ग्रामीण शहरी प्रवासी पब्लिक स्कूलों से वंचित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। हाल के सुधारों का उद्देश्य प्रतिबंधों को खत्म करना है, लेकिन पिछली नीतियों की विरासत अभी भी अस्थायी दर्जे वाले प्रवासियों को नुकसान पहुंचा रही है।

चीन की हुकोऊ पंजीकरण प्रणाली, जो जन्म के समय दर्ज स्थान को सेवाओं से जोड़ती है, ने पब्लिक स्कूलों से ग्रामीण प्रवासियों के बच्चों को छोड़ दिया। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। सरकार को 2006 में प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की आवश्यकता थी। 2008 में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होने वाले बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल शुल्क समाप्त कर दिया गया और 2014 में सेवाओं तक पहुंच से पंजीकृत निवास को रद्द करना शुरू कर दिया। 2016 से, यह सभी बड़े शहरों से प्रतिबंधों में छूट देने के लिए कह रहा है।

हालांकि, प्रवासियों के लिए शिक्षा में बाधाएं बनी रहती हैं। पेपरवर्क और अन्य दारिद्र्य संबंधी आवश्यकताएं पहुंच को सीमित कर सकती हैं। बीजिंग में, प्रवासियों को पब्लिक स्कूल में नामांकन के लिए पांच प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। शिक्षकों का प्रवासी युवाओं के प्रति रवैया भेदभावपूर्ण हो सकता है। अनधिकृत प्रवासी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन कम मिलता है

और उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, तथा माता-पिता अक्सर इन स्कूलों में शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं।

पीछे रह जाने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

पलायन माता-पिता में से किसी एक या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पीछे रह गए लाखों बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करता है। कंबोडिया में, पीछे रह गए बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक थी।

चीन परिवार विकास रिपोर्ट 2015 ने पीछे रह जाने वाले ग्रामीण बच्चों का अनुमान 35% लगाया। पीछे रह गए बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर पलायन के प्रभाव संबंधी प्रमाण मिले-जुले हैं। कुछ अध्ययन प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन अन्य अध्ययन पीछे रह गए बच्चों को अपने साथियों के मुकाबले कम ग्रेड पाने और अधिक मानसिक समस्याएं दर्शाते हैं।

2016 से, चीन ने पिछड़े बच्चों की देखभाल में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां स्थापित की हैं, जिसमें स्थानीय सरकारों से माता-पिता को पिछड़े बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। बोर्डिंग स्कूल एक महत्वपूर्ण रणनीति हैं, लेकिन उनमें प्रायः स्टाफ और सुविधाएं पूरी नहीं होतीं। बाल कल्याण में सुधार के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

बोर्डिंग स्कूलों और छात्रों की संख्या घट रही है, हालांकि कुछ देशों में ऐसे स्कूल मौजूद हैं। युगांडा में, बोर्डिंग स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत 13 साल की उम्र तक लगभग 15% हो जाता है, जो ऊपरी माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्षों में 40% तक बढ़ जाता है।

मौसमी मजदूरी के कारण पलायन शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करता है

मौसमी पलायन, जो गरीबों के जीवन का सहारा है, शिक्षा को बाधित कर सकता है और बच्चों को बाल मजदूरी और कार्यस्थल के खतरों में खुला छोड़ सकता है। भारत में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि सात शहरों में लगभग 80% अस्थायी प्रवासी बच्चों को कार्यस्थल के पास शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, और 40% बच्चे मजदूरी में लगे थे, दुर्व्यवहार और शोषण का सामना कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा हाल में की गई पहलों का लक्ष्य दाखिले में छूट देना, मोबाइल शिक्षा प्रदान करके तथा पलायन होने वाले और उन्हें प्राप्त करने वाले राज्यों के बीच समन्वय में सुधार करके प्रवासी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, लेकिन इसे लागू करने में अनेक चुनौतियां हैं। ईंटों के भट्टों के कार्यस्थल पर वर्ष 2010-2011 में राजस्थान राज्य में शुरू किए गए एक प्रायोगिक कार्यक्रम में घटिया शिक्षा और सीखने की स्थितियों तथा छात्रों के काम करने के कारण शिक्षक और छात्रों की अनुपस्थिति काफी अधिक देखी गई।

घरेलू बाल मजदूर बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं

“ 2012 में, नियोक्ता के घर में 5 से 17 साल के लगभग 17.2 मिलियन बच्चे वेतन पर या उसके बिना घरेलू काम कर रहे थे

2012 में, नियोक्ता के घर में 5 से 17 साल के लगभग 17.2 मिलियन बच्चे वेतन पर या उसके बिना घरेलू काम कर रहे थे। इनमें दो-तिहाई लड़कियां थीं। उदाहरण के लिए, लीमा, पेरू में युवतियां ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने और शिक्षा को जारी रखने के तरीके के रूप में घरेलू कार्य करती हैं, लेकिन उनका कार्यभार अक्सर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बाधा बन जाता है।

” कई अफ्रीकी देशों में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना एक आम रणनीति है। सेनेगल वासियों के लगभग 10% बच्चों को प्रोत्साहित किया गया था। जबकि लड़कों को शिक्षा पर अधिक जोर देने वाले परिवारों में भेजे जाने की संभावना अधिक रहती थी, उन्होंने अपने भाई-बहनों की तुलना में अधिक शिक्षा प्राप्त की। लड़कियों को घरेलू कामों में मदद करने के लिए भेजे जाने की संभावना लगभग चार गुना अधिक थी लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे जाने की संभावना कम थी।

खानाबदोशों और गडरियों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं

घूमना खानाबदोशों और गडरियों के जीवन का अभिन्न भाग है, और इसमें हस्तक्षेप करके उनकी जरूरतों को पहचानना चाहिए। मौसम के अनुसार पलायन करने से स्कूलों में उनकी हाजिरी कम हो जाती है, और छात्रों को अपने संगी-साथियों की तुलना में शिक्षा हासिल करने और गिनती सीखने में मुश्किल होती है। मंगोलिया में, पैसे की कमी के कारण सोउम

बोर्डिंग स्कूल कमजोर हो गए जो खानाबदोशों की आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खानाबदोशों और गैर-खानाबदोशों बच्चों के बीच शिक्षा प्राप्त करने में व्यापक असमानता पाई गई।

कई देशों में खानाबदोशों और गडरियों की आबादी के लिए सरकारी विभाग, आयोग या परिषदें समर्पित हैं जैसे सूडान में खानाबदोशों के लिए शिक्षा विभाग। ये मौसम और गतिशीलता के अनुसार शिक्षा को समायोजित करने का प्रयास करते हैं; उदाहरण के लिए आवासीय स्कूल और मोबाइल स्कूल।

उत्तरी नाइजीरिया में, कई *अल्माजीरी* ('इस्लामी ज्ञान के प्रवासी छात्र') खानाबदोश और गडरिए हैं। कानो राज्य में, समुदाय के साथ जुड़ने और गैर-धार्मिक विषयों के शिक्षकों का चयन करने में सहयोग करने के लिए 700 पारंपरिक शिक्षकों को लक्षित करने वाला एक कार्यक्रम शुरू किया गया।

स्कूलों का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें छात्र किसी भी समय निकल सकते हैं या दाखिला ले सकते हैं, यह एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है लेकिन इसके लिए दक्ष और प्रभावी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता होगी। केन्या और सोमालिया सहित कुछ देशों ने शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए खानाबदोशों के साथ यात्रा करने के लिए और अधिक मोबाइल बनाया है।

खानाबदोशों की आबादी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके जीवन के तरीके को महत्व देना चाहिए। खानाबदोश जीवनशैली के लिए व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से गडरियों के लिए प्रासंगिक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2012 से जिबूती, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में चरागाहों में खानाबदोश समुदायों के क्षेत्रीय स्कूलों के साथ काम किया है, जिसमें पशुधन प्रबंधन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

स्वदेशी समूह शहरों में अपनी पहचान बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं

कई जगहों पर, स्वदेशी लोगों को स्कूली शिक्षा के द्वारा मजबूरन दूसरी संस्कृति को सीखना-समझना पड़ता है। यह विरासत गरीबी और शहरी क्षेत्रों को पलायन करने से और भी समस्याग्रस्त हो जाती है, जिससे प्रायः सांस्कृतिक क्षरण, भाषा हानि और भेदभाव होता है। शहरी स्वदेशी आबादी के लिए भाषा का नुकसान एक प्रमुख मुद्दा है। इक्वाडोर, मेक्सिको और पेरू के शहरों में युवा पीढ़ी द्वारा अपने ग्रामीण साथियों की तुलना में स्वदेशी भाषाओं को बोलने की संभावना काफी कम रहती है।

स्वदेशी अधिकारों पर विनियामक ढांचे में शहरों में रहने वाले स्वदेशी लोगों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कनाडा की स्वदेशी आबादी का 50% से अधिक शहरों में बसता है। शहरी आदिवासी आबादी का विश्लेषण उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा के महत्व को दर्शाता है और यह पाया गया कि संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम और प्रथाओं को शामिल करने से बचपन की शिक्षा के परिणामों में सुधार हुआ है।

गांवों और शहरों में शिक्षा योजनाकारों के लिए पलायन एक चुनौती है

ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी का कम होने का अर्थ है कि शिक्षा योजनाकारों को विशेष रूप से उच्च आय वाले देशों में प्रभावित समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुशल संसाधन आवंटन को संतुलित करना होगा। फिनलैंड ने 1990 से 2015 के बीच 80% स्कूलों अर्थात् कुल 1,600 से अधिक स्कूलों, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम थी, को बंद कर दिया या समेकित कर दिया - कई मध्यम आय वाले देशों में शहरीकरण और कम प्रजनन क्षमता ने समान चुनौतियां उत्पन्न कीं। 2000 से 2015 के बीच रूसी संघ में ग्रामीण स्कूलों की संख्या 45,000 से घटकर 26,000 रह गई। चीन में, 2000 से 2010 के बीच ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 52% की कमी आई।

दक्षता बढ़ाने के लिए स्कूलों को सुदृढ़ करने पर विचार करते हुए, सरकारों को स्कूलों द्वारा समुदायों में महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाने के साथ-साथ अन्य लाभों को भी पहचानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम (पीआईएसए) 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला है कि छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में अनुशासनहीनता, आलस्य और अनुपस्थिति की समस्या कम थी।

सफल सुदृढ़ता के लिए सभी प्रभावित पार्टियों के साथ परामर्श करने और लागत पर विचार करने की आवश्यकता होती है। लिथुआनियाई सरकार ने प्राथमिक उपाय के रूप में छोटे ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों को संरक्षित करने और सैकड़ों नई बसों के साथ सुरक्षित परिवहन प्रदान किया है।

कुछ देश जीवन्त रहने के लिए ग्रामीण स्कूलों को संसाधनों को साझा करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चिली में ग्रामीण शिक्षकों के लिए 374 सूक्ष्म केंद्र हैं जिनमें आम चुनौतियों को पूरा करने के लिए चर्चा की जाती है। 2011 से, चीन की सरकार ने छोटे ग्रामीण स्कूलों में सुविधाएं देने, और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्थानीय समुदायों और स्कूलों का व्यापक नवीनीकरण और उन्नयन किया है, तथा स्कूलों ने संसाधन साझा करने के लिए नेटवर्क स्थापित किए हैं।

गंदी बस्तियों में प्रवासियों के पास शैक्षणिक अवसर कम होते हैं

कम से कम 800 मिलियन लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। राष्ट्रीय परिभाषाएं या आकलन पद्धतियां इस संख्या को कम आंक सकती हैं। झोपड़पट्टियों में गांवों से शहर की ओर पलायन करने वाले लोग रहते हैं जिन्हें सार्वजनिक शिक्षा सहित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं। झोपड़पट्टी में रहने वालों को हटाने और पुनर्वास करने से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बढ़ जाती है और स्कूलों में हाज़िरी कम हो जाती है। 2016 में बांग्लादेश में, माध्यमिक स्कूल में किशोरों के स्कूल छोड़ने की दर अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में झोपड़पट्टी की ही तरह दोगुनी थी।

झोपड़पट्टी में शिक्षा डेटा संग्रह करना प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि शहरीकरण में आवास, पानी और स्वच्छता चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। झोपड़ी/गंदी बस्ती अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 30 से अधिक देशों में डेटा एकत्र करता है, लेकिन इसका शिक्षा डेटा सीमित है। गैर-पंजीकृत निजी स्कूल, जो पब्लिक स्कूलों की कमी के कारण अस्तित्व में आते हैं, की वजह से झोपड़ियों में शिक्षा गतिविधियों को कम करके आंका जा सकता है। कियेरा, केन्या में खुली मैपिंग परियोजना में ऐसे 330 स्कूल पाए गए, जबकि सरकारी अनुमान 100 था। अक्सर झोपड़ियां में एकमात्र विकल्प निजी स्कूल होते हैं जो बेहतर ढंग से नियंत्रित नहीं होते और उनमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। नैरोबी की झोपड़पट्टी में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल ने छात्रों की साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों में सुधार किया।

झोपड़पट्टी से संबंधित शहरीकरण की बहस में शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। झोपड़पट्टी के निवासियों की अवधि को सुरक्षित करना और उन्हें अधिकार देना शिक्षा प्रावधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के बुनियादी शिक्षा ढांचे में निवेश करने में इच्छुक नहीं होती है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। अर्जेंटीना में, भूमि पर मालिकाना अधिकार दीर्घावधि शिक्षा सुधार से जुड़ा था।

दाखिले की कड़ी शर्तें और दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएं प्रायः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में प्रवासी भागीदारी के लिए बाधा बन जाती हैं। यह कार्यक्रम उनकी शिक्षा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। केन्याई झोपड़पट्टी में, शहरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय पहचान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार पूर्व-चयनित 5% प्राप्तकर्ता, जो शरणार्थी थे, या बच्चों वाले परिवार केन्या राष्ट्रीयता प्रमाणित नहीं कर पाए।

अंतर्राष्ट्रीय पलायन

जब लोग बेहतर काम और जीवन के अवसरों के लिए पलायन करते हैं, तो उन्हें नई व्यवस्था में तालमेल बैठाना होता है, कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटना पड़ता है, और भाषाई बाधाओं और संभावित भेदभाव से निपटना पड़ता है। वे जिन देशों को पलायन करते हैं, वहां शिक्षा प्रणालियों को नए लोगों को समायोजित करने के लिए समायोजन लागत खर्च करनी पड़ती है।

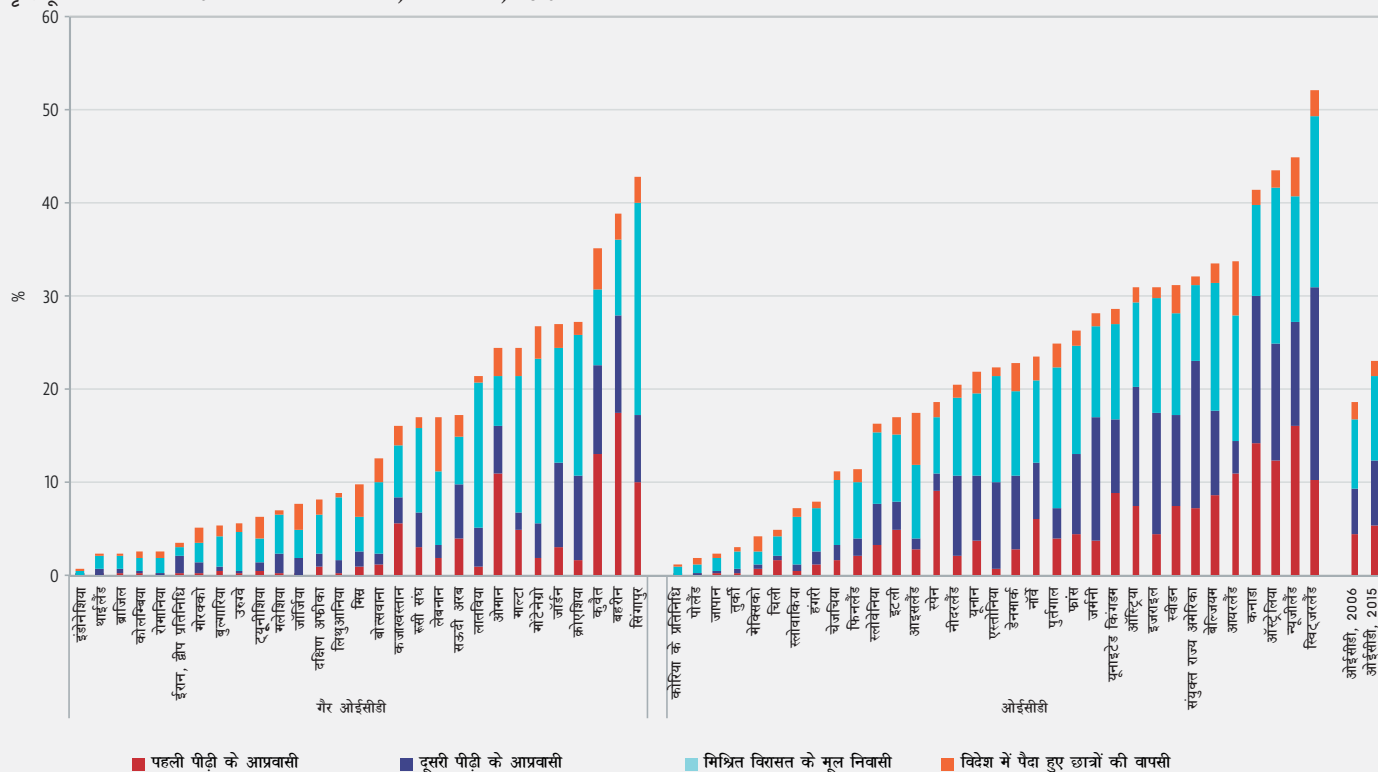
2017 में, 258 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, जो विश्व जनसंख्या का 3.4% था। इनमें से उच्च आय वाले देशों में लगभग 64% प्रवासी रहते थे, जहां जनसंख्या के भाग के रूप में आप्रवासियों का हिस्सा 2000 में 10% से बढ़कर 2017 में 14% हो गया। कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी राज्यों में आप्रवासी बहुमत में हैं।

कोस्टा रिका, कोट डी'आईवोयर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित मध्यम आय वाले देशों में आप्रवासन दर वैश्विक औसत से दो से तीन गुना अधिक है। इसके विपरीत, 5% से अधिक प्रवासन दर वाले देशों में अल्बानिया, जार्जिया, जमैका, किर्गिस्तान और निकारागुआ शामिल हैं। मेक्सिको का सबसे बड़ा प्रवासन कोरिडोर मेक्सिको है। अन्य में पूर्वी यूरोप में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी एशिया खाड़ी राज्य शामिल हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास (ओईसीडी) देशों के अधिकांश संगठनों में, 15 वर्षीय छात्रों में से कम से कम पांच छात्र आप्रवासी थे या 2015 में आप्रवासी पृष्ठभूमि थी (चित्र 2)। इस रिपोर्ट में दिए गए एक अनुमान से पता चलता है कि उच्च आय वाले देशों में 80% माध्यमिक स्कूलों में, कम से कम 5% छात्र आप्रवासी पृष्ठभूमि के हैं (52% में, कम से कम 15% आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले हैं)।

चित्र 2:

अधिकांश ओईसीडी देशों में, 15 वर्षीय पांच छात्रों में से कम से कम एक छात्र पहली - या दूसरी पीढ़ी का आप्रवासी था। पृष्ठभूमि के आधार पर 15 वर्षीय छात्रों का वितरण, चयनित देश, 2015



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig3_4

नोट: इस आंकड़ों में आंकड़े वाले पांच देश एवं सीमा क्षेत्र तथा आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले छात्रों की उच्च दर शामिल नहीं है: हांगकांग, चीन, लक्समबर्ग, मकाओ, चीन, कतर; और संयुक्त अरब अमीरात।

स्रोत: 2006 और 2015 पीआईएस और 2015 टीआईएसएस के आधार पर जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण

पलायन शिक्षा को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है

प्रवासी कोई यादृच्छिक आबादी नहीं हैं। गैर-प्रवासियों में एक अन्य अंतर यह है कि वे अधिक शिक्षित हैं, जो उन्हें बेहतर जानकारी एकत्र करने, आर्थिक अवसरों का उपयोग करने, कौशल को हस्तांतरित करने और वित्त प्रवासन का उपयोग करने में मदद करते हैं। 2000 में, उच्च स्तरीय शिक्षा वाले लोगों की वैश्विक प्रवासन दर 5.4% थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.8% और प्राथमिक शिक्षा के लिए 1.1% थी।

“

2000 में, उच्च स्तरीय शिक्षा वाले लोगों की वैश्विक प्रवासन दर 5.4% थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.8% और प्राथमिक शिक्षा के लिए 1.1% थी

”

प्रवासन के समय शैक्षिक योग्यता भी उन स्थितियों पर निर्भर करती है जिनके अंतर्गत प्रवासियों ने सीमा पार की है: उचित दस्तावेजों के बिना एल साल्वाडोर, हैती, मेक्सिको और निकारागुआ के अमेरिकी आप्रवासियों ने अस्थायी अनुबंधों की तुलना में औसतन अधिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि यह शिक्षा कानूनी रूप से बने निवासियों से कम थी।

शैक्षिक योग्यता और उपलब्धि पर प्रवासन के प्रभाव को समझने के लिए की गई दो तुलना महत्वपूर्ण हैं। पहली, उन लोगों के बीच है जो पलायन करते हैं या नहीं करते हैं, हालांकि ये समूह पलायन करने के निर्णय लेने से भिन्न होते हैं (उदाहरण के लिए यदि प्रवासी अधिक समय तक रुके होते तो वे अधिक शिक्षित हो सकते थे)। दूसरा आप्रवासियों और मूल निवासियों के बीच है, जो पलायन दर्जे से भी अधिक भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में, चुनिंदा आप्रवासन नीतियों का यह अर्थ हो सकता है कि आप्रवासी मूल निवासी से अधिक शिक्षित हैं; अन्य मामलों में, आप्रवासी गरीब इलाकों में रहते हैं जहां निचले स्तर के स्कूल अच्छे नहीं होते, जो उनके बच्चों द्वारा कम शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण है।

पलायन पीछे छूट गए बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है।

प्रवासी प्रायः बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। फिलीपींस में, अनुमानित 1.5 मिलियन से 3 मिलियन बच्चों के कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी माता-पिता हैं। शिक्षा के लिए भेजा गया धन महत्वपूर्ण हो सकता है।

विश्व स्तर पर, परिवारों को 2017 में अंतरराष्ट्रीय भेजे गए धन के रूप में 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, जिसमें कम और मध्यम आय वाले देशों को 466 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे जा रहे थे - ये सरकारी विकास सहायता की मात्रा से तीन गुना थे। भारत और चीन को सबसे बड़ी राशि मिली जबकि किर्गिस्तान और टोंगा का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत बढ़ा।

सिद्धांत रूप में, भेजे गए धन का शिक्षा पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आय के विविध स्रोत बीमा प्रभाव प्रदान करते हैं: परिवारों द्वारा शिक्षा व्यय में कटौती करने की संभावना कम हो सकती है। फिर भी, हालांकि अतिरिक्त आय से घरेलू खर्च में वृद्धि होती है, शिक्षा अन्य व्यय के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, बच्चों को प्रवासी के श्रम को प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है, और माता-पिता के इनपुट की कमी शिक्षा को बाधित कर सकती है। भेजा गया धन भी 'पलायन की संस्कृति' बना सकता है, जिसमें विदेश में निम्न या अर्द्ध कुशल श्रम पर उच्च प्रतिलाभ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित कर सकता है।

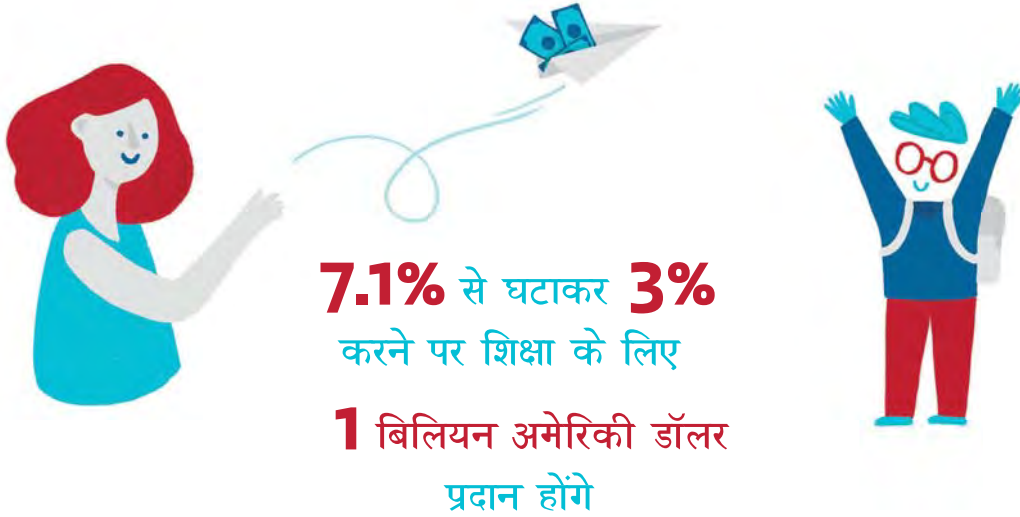
व्यावहारिक तौर पर, उप-सहारा अफ्रीका और मध्य, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व एशिया में 18 देशों में अध्ययन से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजे गए धन से घरेलू शिक्षा खर्च में 35% की वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका (53%) में भी इसका प्रभाव व्यापक था।

एसडीजी लक्ष्य 10.ग में भेजे गए धन की लेनदेन लागत को औसतन 3% कम करने के लिए कहा गया है। वर्तमान औसत 7.1% है। पारंपरिक बैंक सबसे महंगे चैनल हैं, जो 11% शुल्क लेते हैं, और अफ्रीका में कुछ मध्यस्थ 20% से अधिक शुल्क लेते हैं। शिक्षा पर कुल घरेलू खर्च का हिस्सा 4% मानते हुए, प्रेषण लागत को 3% तक कम करने से परिवारों को प्रति वर्ष शिक्षा पर अतिरिक्त 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की अनुमति मिल सकती है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षा परिणामों पर घर भेजे गए धन का समग्र प्रभाव सकारात्मक होता है।

फिलीपींस में, अंतरराष्ट्रीय स्तर से घर भेजे गए पैसे में 10% की वृद्धि ने स्कूल की उपस्थिति 10% से अधिक बढ़ा दी और इससे बाल मजदूरी में प्रति सप्ताह तीन घंटे से अधिक की कमी हुई। इसका प्रभाव लिंग आधार पर भिन्न हो सकता है। जार्डन में, घर भेजे गए धन से केवल पुरुषों की अनिवार्य शिक्षा उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

धन घर भेजने के लिए प्रवासियों द्वारा देय लागत को



सकारात्मक निष्कर्ष को विशेष रूप से चुनिंदा प्रवासन कोरिडोर या संदर्भ में कम दाखिले की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। कुछ कम कौशल वाले प्रवासन कोरिडोर में, परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव का पता चला है। ग्वाटेमाला में दाखिले की संभावना में व्यापक कमी अंतरराष्ट्रीय स्तर से भेजे गए धन से जुड़ी थीं, हालांकि घर पर धन भेजने के परिणामस्वरूप दाखिला लेने वालों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। ग्रामीण मैक्सिको में, घर पर धन भेजने के कारण पीछे रह गए छात्रों के शिक्षा परिणाम अच्छे नहीं रहे थे।

प्रवासी गंतव्य देशों में शिक्षा मूल्य का भुगतान करते हैं

गंतव्य देशों में, आप्रवासी अक्सर शिक्षा पहले ही छोड़ देते हैं। यूरोपीय संघ में, 2017 की शुरुआत में 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 10% मूल निवासी और विदेशों में जन्मे 19% लोगों ने स्कूल पहले ही छोड़ दिया। स्कूल छोड़ना आने वाले की आयु पर निर्भर हो सकता है; इसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या छात्र प्रारंभिक, मध्य या अनिवार्य शिक्षा के अंत में मेजबान प्रणाली में दाखिला लेते हैं। अमेरिका में, 7 साल की उम्र में आने वाले 40% मैक्सिकन प्रवासियों ने 14 वर्ष की उम्र में आने वाले 70% लोगों की तुलना में माध्यमिक स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की थी।

हालांकि, आप्रवासियों की शिक्षा की स्थिति मूल निवासी और पीछे छूटने वालों की तुलना में अधिक तेजी से सुधरती है। जर्मनी में, मूल निवासी, जिनके माता-पिता की औसत शिक्षा कम थी, की शिक्षा उनके अप्रवासी साथियों की तुलना में बहुत मंद गति से बढ़ी। 10 लैटिन अमेरिकी और कैरीबियाई देशों में से 8 देशों में, पलायन न करने वाले माता-पिता के बच्चों की तुलना में आप्रवासियों के बच्चों ने औसतन 1.4 साल अधिक शिक्षा प्राप्त की।

शिक्षा प्राप्ति में अंतराल पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। 2015 पीआईएसए के अनुसार, पहली पीढ़ी के 49% और दूसरी पीढ़ी के 15% वर्षीय आप्रवासियों ने 61% मूल निवासी की तुलना में पढ़ने, गणित और विज्ञान में कम से कम स्तर 2 की दक्षता प्राप्त की। कनाडा, जर्मनी और इटली में, मूल निवासी दूसरी पीढ़ी के आप्रवासियों की तुलना में विशेष रूप से उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

छह देशों में दूसरी पीढ़ी के तुर्की आप्रवासियों की तुलना करने से पता चला है कि जर्मनी में केवल 5%, जबकि फ्रांस में 37% लोगों ने उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल की है। बाद में संस्थागत कारणों, जैसे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शीघ्र उपलब्ध होने, माध्यमिक शिक्षा में देर से दाखिला लेने और कम क्षमता वाले चरणों के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुंचने ने इस अंतर को समझाने में मदद की।

निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति ओईसीडी में आप्रवासी शिक्षा के अंतर का लगभग 20% स्पष्ट करती है; फ्रांस और ग्रीस सहित कुछ देशों में, यह आधे से ज्यादा समझा जा सकता है। ओईसीडी देशों में आप्रवासी छात्रों द्वारा मूल निवासी छात्रों की तुलना में ग्रेड के दोहराने की संभावना दो गुणा रहती है।

पलायन और नागरिकता नीतियां स्कूली शिक्षा में बाधा डालती हैं

शिक्षा का अधिकार और सामान्य गैर-भेदभाव वाले सिद्धांत बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मेलन में अंतर-निहित हैं। एक आप्रवासी-विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संधि यह पुष्टि करती है कि प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ शिक्षा क्षेत्र में नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, हालांकि चार देशों में से केवल एक देश, जहां से पलायन हो रहा है, ने ही इसे अब तक मंजूरी दी है। व्यावहारिक रूप से, प्रतिबंधित आप्रवासन नीतियां, असंगत कानून और मेजबान देश की सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकता इस अधिकार की पूर्ति को रोक सकती हैं।

चीन और ग्रीस सहित कुछ संविधान नागरिकों के शिक्षा के अधिकार को सीमित करते हैं। अन्य राष्ट्रीय कानून शिक्षा के सवैधानिक अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। साइप्रस और स्लोवाकिया में, स्कूलों को आप्रवासन प्राधिकरणों को वैध दस्तावेजीकरण के बिना परिवारों का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए बाध्य किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में, आप्रवासी अधिनियम 2002 दस्तावेज न रखने वाले प्रवासियों को स्कूल में दाखिला लेने से रोक लगाता है।

विदेश में जन्म लेने वाली लोगों के शिक्षा अधिकारों से संबंधित कानून से यह संभावना बढ़ जाती है कि शिक्षा का अधिकार पूरा किया जाएगा। अर्जेंटीना में, राष्ट्रीय शिक्षा कानून 2006 सभी निवासियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। स्लोवेनियाई प्राथमिक स्कूल अधिनियम स्पष्ट रूप से राज्यविहीन लोगों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

एक समग्र कानूनी ढांचा जरूरी नहीं कि क्षेत्रीय या स्थानीय भेदभाव प्रथाओं को रोकता हो। स्कूल जन्म प्रमाण-पत्र, पूर्व शिक्षा प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय पहचान-पत्र या दाखिले के लिए आवास प्रमाण-पत्र की मांग कर सकते हैं। चिली में, जहां हैतीयन प्रवासियों की संख्या 2010 में 5000 से भी कम थी, 2017 में बढ़कर 105,000 हो गई। नीति में यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए; व्यावहारिक रूप से, शिक्षा प्रावधान स्थानीय सरकारी अधिकारियों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। उज्बेकिस्तान में स्कूल के अधिकारियों को प्रायः दाखिले से पहले राष्ट्रीय भाषा में निवास, पासपोर्ट या सुविधाएं लेने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है।

सरकारी स्पष्टीकरण स्कूल में दाखिला देने वालों को यह आश्वस्त कर सकता है कि कानून के अंतर्गत पूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, और एक ठोस राष्ट्रीय कानूनी ढांचा व्यक्तियों की शिकायतें सुनने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। 2014 में, इटली और तुर्की ने स्पष्ट किया कि दाखिले के लिए दस्तावेज का होना अनिवार्य नहीं था। फ्रांस में, माता-पिता दाखिले में भेदभाव बरतने के निर्णयों में सुधार करने के लिए लोकपाल या अदालतों से अपील कर सकते हैं।

फिर भी, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां 2014 में 11 मिलियन अनधिकृत आप्रवासी थे, वहां निर्वासन का खतरा बच्चों को स्कूल से दूर रख सकता है: फरवरी 2017 में, एक आप्रवासन छापे के बाद लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको, स्कूल जिले में अनुपस्थिति की दर 60% बढ़ गई। 2012 बाल्यावस्था आगमन आस्थगित कार्रवाई (डीएसीए) कार्यक्रम ने 1.3 मिलियन गैर-दस्तावेज युवाओं को लक्षित किया जो बच्चों के रूप में पहुंचे थे, जिसमें निर्वासन से सुरक्षा और कार्य परमिट के लिए पात्रता प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम ने माध्यमिक स्नातक दरों में अनुमानित 15% की वृद्धि की क्योंकि पात्र आप्रवासियों ने शर्तों को पूरा करने की मांग की है।

अकेले प्रवासित नाबालिगों की शिक्षा आवश्यकताएं प्रायः पूरी नहीं होती हैं, जो विशेष रूप से शोषण का शिकार हो जाते हैं। 2015-2016 में दुनिया भर में उनकी संख्या 66,000 से बढ़कर 2015-2016 में 300,000 हो गई। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, नाउरू और थाईलैंड सहित कई देशों में, आप्रवासी हिरासत में रखे गए बच्चों और युवाओं को प्रायः शिक्षा तक सीमित पहुंच होती है या बिल्कुल नहीं होती। 2011 और 2016 के बीच इटली में आने वाले 86,000 नाबालिगों में से लगभग 73% अकेले थे। उन्हें बचाने के उद्देश्य से 2015 और 2017 में कानून बनने के बावजूद, केवल एक अल्पसंख्यक नियमित रूप से स्कूल गया।

दस्तावेज की कमी दुनिया भर में 10 मिलियन राज्यविहीन लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, जिनमें से कुछ प्रवासियों के वंशज हैं। कोटे डी'आईवोयर में, 700,000 राज्यविहीन लोगों को, शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। डोमिनिकन गणराज्य में, जहां हजारों हैतीयन प्रवासियों से राष्ट्रीयता छीन ली गई है, 2012 में हैती में पैदा हुए 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों की प्राथमिक स्कूल उपस्थिति दर 52% थी, जबकि अन्य देशों में पैदा हुए आप्रवासियों की उपस्थिति दर 82% थी।

शिक्षा नीतियां प्रवासियों का स्कूल में दाखिले का समर्थन कर सकती हैं

शुरुआती बाल्यावस्था कार्यक्रम, भाषा समर्थन कार्यक्रम, और डेटा एकत्र करने, चयन और पृथक्करण से संबंधित नीतियां शिक्षा उपलब्धता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में आप्रवासी भागीदारी एक आवश्यक आधार है। औसतन, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भाग लेने वाले 15 वर्षीय आप्रवासियों के पढ़ने का स्कोर उस राशि से अधिक था जो एक वर्ष तक स्कूल जाने से संबंधित था। बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में शामिल होना मुश्किल हो सकता है: संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 वर्ष से कम और 4 वर्ष से कम बिना दस्तावेज वाले बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय दाखिला लेना, दस्तावेज रखने वाले आप्रवासियों और मूल निवासी दोनों से पिछड़ गया था।

भाषा प्रवीणता की कमी शिक्षा के लिए हानि है, क्योंकि यह सामाजिकरण, संबंध बनाने और अपनेपन की भावना को रोकती है और इससे भेदभाव का जोखिम बढ़ता है। 2012 में, 53% कम साक्षरता वाले पहली पीढ़ी के आप्रवासी छात्र, 23 उच्च आय वाले देशों में स्कूल के बाहर अतिरिक्त साक्षरता पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे थे।

बेल्जियम, फ्रांस और लिथुआनिया में तैयारी कक्षाओं की अवधि एक वर्ष से लेकर ग्रीस में चार साल तक भिन्न-भिन्न होती है। जर्मनी की 'स्वागत कक्षाएं' आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए अलग-अलग गहन भाषा निर्देश प्रदान करती हैं। स्पेन में, क्षेत्र तीन मॉडलों में से एक का पालन करते हैं - अस्थायी कक्षाएं, जिनमें छात्र दिन के हिस्से में भाग लेते हैं, विदेशी भाषा कक्षाएं, और अंतर-सांस्कृतिक कक्षाएं जिनमें परिवारों और स्कूलों के बीच संबंध बनाने के लिए भाषा के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकारों को दीर्घावधि के लिए अलग से स्कूली शिक्षा प्रदान करने से बचने की जरूरत है क्योंकि इससे घाटा और नुकसान बढ़ सकता है।

प्रारंभिक क्षमता-आधारित चयन आप्रवासन छात्रों को नुकसान पहुंचाता है, अवसरों के साथ समझौता करता है तथा इससे असमानता पैदा होती है और सामाजिक पृष्ठभूमि और छात्र परिणामों के बीच मजबूत रिश्ता नहीं बनता। इटली में, 33% पेशेवर स्कूल और 13% तकनीकी स्कूल स्नातकों की तुलना में, 59% आप्रवासी सामान्य माध्यमिक स्नातकों ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था।

आप्रवासी छात्रों के उपनगरीय क्षेत्रों और कम शैक्षणिक मानकों और प्रदर्शन स्तर वाले स्कूलों में पढ़ने की अधिक संभावना होती है। पृथक्ता इस आधार पर होती है कि देशी छात्र समृद्ध पड़ोस में चले जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में देशी भाषा न बोलने वालों के द्वारा, वंचित देशी भाषा बोलने वालों के साथ स्कूल जाने की संभावना अधिक थी। आप्रवासियों का हिस्सा वंचित मूल निवासी के शिक्षा परिणामों में भी बाधा डाल सकता है। नॉर्वे में, स्कूल में आप्रवासियों के हिस्से में 10 प्रतिशत की अंक वृद्धि उनके स्कूल छोड़ने की 3 प्रतिशत की अंक वृद्धि से जुड़ी हुई थी।

देश अलग-अलग से निपटने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। इटली में, 2010 में जारी एक परिपत्र ने कक्षा में अधिकतम 30% पहली पीढ़ी के आप्रवासियों को निर्धारित कर दिया। व्यावहारिक रूप में, 17% प्राथमिक कक्षाओं की सीमा पार हो गई। फ्रांस और जर्मनी में स्कूली शिक्षा में अलग-अलग को सीमित करने संबंधी नीतियों और सुधारों के बावजूद, माता-पिता निर्धारित किए गए स्कूलों को झूठ बोलते हैं, और स्कूलों को धार्मिक या विदेशी भाषा निर्देशों के माता-पिता के विकल्पों के आधार पर अलग-अलग कक्षाएं प्रदान करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। बर्लिन के चार जिलों में 108 प्राथमिक विद्यालयों के आकर्षण क्षेत्रों के विश्लेषण से पता चला कि पांच स्कूलों में से एक में, दाखिला दिए गए आप्रवासी पृष्ठभूमि छात्रों की संख्या क्षेत्र में रहने वाले की संख्या से दोगुना थी।

कुछ सरकारें बहुसंख्यक आप्रवासी छात्रों वाले स्कूलों का समर्थन करती हैं

जिन स्कूलों में अधिक आप्रवासी या शरणार्थी छात्र होते हैं, उन्हें अधिक धन मिलने की संभावना रहती है। फॉर्मूला-आधारित वित्त-पोषण का उद्देश्य हानि से जुड़े कारणों का उल्लेख करके स्कूलों को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करके इक्विटी को बढ़ाना है। कुछ कार्यक्रमों में प्रवासियों को स्कूल वित्त-पोषण में एक स्पष्ट कारक के रूप में शामिल किया जाता है। लिथुआनिया में, स्कूल के बजट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अतिरिक्त 20% अनुदान मिलता है और देश में अपने पहले स्कूल वर्ष में आप्रवासी छात्रों के लिए 30% अनुदान मिलता है।

ऐसी प्रथाएं अपवाद हैं, लेकिन प्रवासी और शरणार्थी छात्र अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। निर्देश की भाषा में दक्षता न होने या आसपास सामाजिक-आर्थिक स्थितियां अनुकूल न होने पर वित्त-पोषण मिल सकता है। आप्रवासियों में आम तौर पर ये दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। इंग्लैंड में नए राष्ट्रीय वित्त-पोषण फॉर्मूले (यूनाइटेड किंगडम) में प्रवासियों के लिए विशिष्ट वित्त-पोषण समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के नुकसान को 'वचित', 'निम्न पूर्व प्राप्ति' और 'अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी' की भरपाई करने के लिए धन आवंटित किया जाता है।

प्रवासी और शरणार्थी छात्रों की सहायता के लिए प्रायः स्कूलों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो मूल वित्त-पोषण फार्मूला से भिन्न होते हैं। 2008-2011 में डेनमार्क की सरकार ने आप्रवासी परिवारों और स्कूलों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों और गृह सलाहकारों जैसी गतिविधियों और संसाधनों के लिए लगभग 3 मिलियन अमरीकी डॉलर राशि निर्धारित की है।

कुछ देश वित्त-पोषण फार्मूले के अलावा भाषा कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अमेरिकी अंग्रेजी भाषा अधिग्रहण कार्यक्रम अंग्रेजी सीखने वालों की संख्या के आधार पर राज्य फार्मूला अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष 740 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करता है। भाषा निर्देश लागू करने के लिए स्कूल इस वित्त-पोषण की ओर आकर्षित होते हैं। शिक्षकों को भी अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, जो आप्रवासी छात्रों और परिवारों से जुड़ने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

प्रवासी और शरणार्थी छात्रों से जुड़ी निर्धारित सहायता स्कूल और प्रशासन की ढांचागत चुनौतियों को नजरअंदाज कर सकती है। कम शिक्षा प्राप्त आप्रवासियों और शरणार्थियों को पहले से ही स्कूल में कर्मचारियों की कम संख्या के कारण पड़ोस में समूह में रहना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए नियमित स्कूल बजट से प्रोत्साहन प्रदान करना मुश्किल होता है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक निर्णय कार्यक्रमों के लिए अस्थायी वित्त-पोषण या अतिरिक्त बजट सहायता प्रदान कर सकता है।

साक्षरता और भाषा कार्यक्रम वयस्क आप्रवासियों और शरणार्थियों को शामिल करने का एक आधार-स्तंभ हैं

आप्रवासी और शरणार्थी साक्षरता कौशल व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। 2016 में जर्मनी में शरण लेने वालों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें 15% अशिक्षित थे, 34% लैटिन लिपि में साक्षर थे और 51% एक अन्य लिपि में साक्षर थे। वयस्क साक्षरता आप्रवासियों और शरणार्थियों के स्वागत और सम्मान की भावना और दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने उनकी बातचीत करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। मेज़बान देश की भाषा में दक्षता हासिल करने से नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं, उच्च कमाई होती है और अपने स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर ढंग से होती है। फिर भी, व्यापक सार्वजनिक साक्षरता कार्यक्रमों में वयस्क आप्रवासियों और शरणार्थियों पर अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना नहीं होती।

आप्रवासी और शरणार्थी विविधता को पहचानने के लिए कार्यक्रम लचीले होने चाहिए और उनकी तीव्रता, विषय-वस्तु और समय-सारिणी अलग-अलग होनी चाहिए। सीखने वाले जो अपनी पहली भाषा में अशिक्षित होते हैं, विशेष चुनौतियों का सामना करते हैं। एक अनुमान से पता चला है कि बिना किसी या मामूली औपचारिक शिक्षा वाले लोगों को दूसरी भाषा पढ़ने में बुनियादी स्तर का ज्ञान प्राप्त करने में आठ गुना अधिक समय लग सकता है। फिनलैंड में, धीमा सीखने का अर्थ है कि प्रदान किया गया प्रशिक्षण अशिक्षित वयस्कों के लिए बहुत छोटा हो सकता है।

ऐसे शिक्षार्थियों की सहायता के लिए, शिक्षकों को उन सामग्रियों का उपयोग करने में कौशल की आवश्यकता होती है जिन्हें आप्रवासियों को दैनिक जीवन में एक चुनौती के रूप में सामना करना पड़ता है। वियना के अल्फाजेंटूम फर माइग्रेंटइननेन कार्यक्रम में, सीखने वाले अपने कार्यस्थल या घर से सामग्री प्रदान करते हैं जिन्हें वे समझना चाहते हैं।

वयस्क आप्रवासियों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षण और सीखना प्रारंभिक साक्षरता अधिग्रहण का समर्थन करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। नॉर्वे में, वयस्क शिक्षा केंद्रों ने शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच समझ की कठिनाई को दूर करने के लिए प्रारंभिक साक्षरता कक्षाओं में सहायक के रूप में सबसे शिक्षित आप्रवासी शिक्षार्थियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

धन की कमी कार्यक्रम के संचालन को सीमित कर सकती है, विशेषकर जहां सरकारी संसाधन और सहायता यूनाइटेड किंगडम में नीति के अनुरूप नहीं होती है। गरीबी, सुरक्षा की चिंता और सांस्कृतिक रूप से उचित कार्यक्रम का अभाव व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को कक्षाओं में भाग लेने के लिए हतोत्साहित कर सकता है। जातीय भाषाई क्षेत्रों में नए आप्रवासियों की बढ़ी संख्या भाषा सीखने की समस्या को कम कर सकती है। और पलायन की अस्थायी प्रकृति किसी नई भाषा को सीखने की इच्छा को कम कर सकती है।

भाषा कार्यक्रम सहज एवं सरल, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और संसाधन संपन्न होने चाहिए। योजना और निर्देश में आप्रवासियों और शरणार्थियों को शामिल करने से ये मददगार हो सकते हैं। न्यूजीलैंड में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय, सरकार ने पाठ्यक्रमों की वांछनीय विशेषताओं और बाधाओं को दूर करने के लिए पूर्व और वर्तमान शरणार्थियों से परामर्श किया।

चूंकि रोजगार आने वाले आप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए प्राथमिकता है, अतः एकीकरण और भाषा सीखने को कार्यबल भागीदारी के साथ जोड़ा जा सकता है। कैबो वर्डे में रहने वाले अफ्रीकी समुदायों के आप्रवासियों को साक्षरता और प्रशिक्षण प्रदान करने के अंतर्गत साक्षरता, पुर्तगाली भाषा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर कौशल और बर्दईगीरी सीखाना शामिल है। जर्मन सरकार के एकीकरण पाठ्यक्रम में जर्मन भाषा निर्देश के 600 घंटे शामिल हैं, और बी 1 प्रवीणता तक पहुंचने वाले शरणार्थी नौकरी से संबंधित भाषा प्रशिक्षण के लिए पात्र होते हैं।

प्रवासियों को वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता

कई पारंपरिक देशों और कम कौशल वाले प्रावासी समुदायों में वित्तीय साक्षरता कम होती है, जिससे आप्रवासियों और शरणार्थियों को धोखाधड़ी या वित्तीय शोषण का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से, मेजबान देशों में वित्तीय और कल्याण प्रणाली, के साथ-साथ धन जमा करने के चैनल, प्रारंभिक रूप में अस्पष्ट हो सकते हैं।

वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी इंटरनेशनल नेटवर्क जैसी वैश्विक पहलों में वित्तीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले व्यापक एजेडे के भाग के रूप में प्रवासियों पर ध्यान देना शामिल है। प्रवासियों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों में प्रायः अंतरराष्ट्रीय, सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के हितधारक शामिल होते हैं।

इंडोनेशिया ने 2013 में एक राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता रणनीति अपनाई। यह विश्व बैंक के साथ संयुक्त कार्यक्रम द्वारा उत्पन्न साक्षरता पर आधारित है, जिसमें प्रशिक्षण तब दिया जाता है जब संभावित प्रवासियों को बड़े वित्तीय निर्णय लेने पड़ते हैं। मोरक्को वित्तीय शिक्षा फाउंडेशन ने मोरक्को में प्रावासियों के लिए कार्यक्रम वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ भागीदारी की। रोमानिया में, अंतरराष्ट्रीय आप्रवासी संगठन ने मास्टरकार्ड फाउंडेशन के साथ आप्रवासियों और शरणार्थियों के एकीकरण का समर्थन करने के लिए एक संयुक्त पहल प्रारंभ की, जिसमें कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी गई। इसमें बच्चों, महिलाओं और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई।

अच्छी वित्तीय साक्षरता होने पर भी, प्रवासियों को वित्तीय शब्दावली और वित्तीय उत्पादों की विशेषताओं की जानकारी नहीं हो सकती है। उन्हें अपने देश और मेजबान समुदायों दोनों में वित्तीय संस्थानों के प्रति विश्वास की कमी हो सकती है। बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों और नए आने वाले शरणार्थियों को प्रायः डर सताता रहता है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए अनुरोध की गई जानकारी का उपयोग उन्हें पहचानने और संभावित रूप से निर्वासित करने के लिए किया जाएगा। वित्तीय उद्योग के पास प्रवासियों और उनके देश में उनके परिवारों के लिए प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील उत्पादों की कमी होती है।

प्रवासियों के आर्थिक कल्याण पर वित्तीय शिक्षा के प्रभाव के साक्ष्य मिले-जुले हैं। कतर में भारतीय प्रवासियों के एक अध्ययन में पाया गया कि वित्तीय निर्णय लेने में वित्तीय शिक्षा प्रभावी थी, भले ही इसका प्रभाव कम था। आस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड में एक अध्ययन में यह पाया गया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने औपचारिक बैंकिंग के उपयोग को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया था।

विस्थापन

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से विस्थापित लोगों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। विस्थापित लोग दुनिया के कुछ सबसे गरीब और अल्प सेवित क्षेत्रों से आते हैं, और उनकी समस्या और भी बढ़ जाती है जब उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

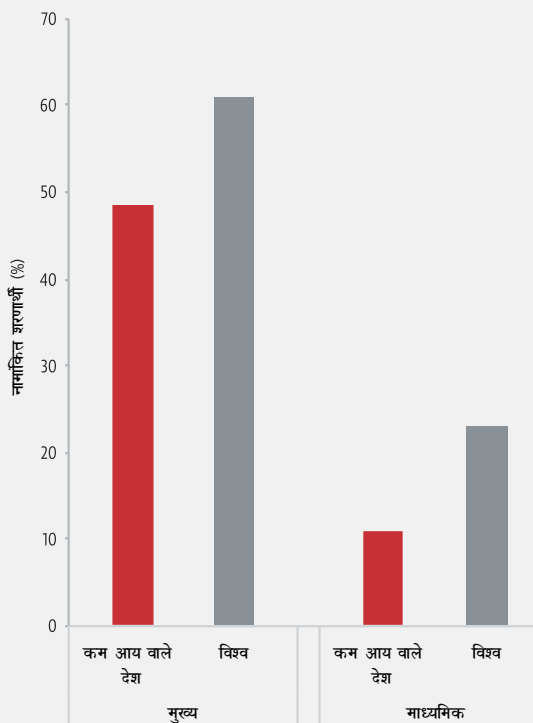
संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी (यूएनएचसीआर) कार्यालय की सुरक्षा के तहत 19.9 मिलियन शरणार्थी हैं, जिनमें से लगभग 52% की आयु 18 वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की सुरक्षा के तहत पूर्वी क्षेत्र में 5.4 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थी हैं। लगभग 39% शरणार्थी अधिकतर उप-सहारा अफ्रीका में प्रबंधित, स्व-स्थापित या ट्रांजिट कैंपों या सामूहिक केंद्रों में रहते हैं। शेष में से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवास में रहते हैं।

“जबरदस्ती विस्थापित लोगों की समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं”

इसके अलावा, संघर्ष के कारण 40 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) हो गए हैं, इनकी सबसे बड़ी संख्या सीरिया अरब गणराज्य में है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अतिरिक्त 19 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, और इनकी सबसे बड़ी आबादी चीन की मेजबानी में है।

चित्र 3:

कम आय वाले देशों में केवल 11% शरणार्थी किशोर माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेते हैं शिक्षा, 2017 के स्तर तक दाखिला लेने वाले 5 से 17 वर्ष की आयु के शरणार्थियों का प्रतिशत



जीईएम स्टॉर्ट लिंक: http://bit.ly/fig4_2
 स्रोत: यूएनएचसीआर (2018)

विस्थापितों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध न होना

विस्थापितों की शिक्षा स्थिति निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यूएनएचसीआर का अनुमान है कि 2017 के शरणार्थी नामांकन अनुपात के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 61% और माध्यमिक विद्यालय में 23% शरणार्थी हैं। कम आमदनी वाले देशों में, अनुपात प्राथमिक स्कूल में 50% से कम और माध्यमिक (चित्र 3) में 11% थे। कुल मिलाकर, 2017 में स्कूल छोड़ने वाले 5 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 4 मिलियन शरणार्थी थे।

देशों के भीतर शरणार्थी दाखिला अनुपात काफी भिन्न हो सकते हैं। 2016 में, इथियोपिया में जिला द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार शरणार्थियों के लिए माध्यमिक सकल नामांकन अनुपात समारा में 1% से लेकर जिजिगा में 47% तक था। पाकिस्तान में, 2011 की अफगान शरणार्थियों (29%) की प्राथमिक शुद्ध नामांकन दर राष्ट्रीय स्तर (71%) से कम थी, जबकि अफगान शरणार्थी लड़कियों (18%) की दर लड़कों (39%) की तुलना में आधी से कम थी, लेकिन अफगानिस्तान में लड़कियों की प्राथमिक उपस्थिति दर आधे से भी कम थी। शरणार्थी प्रायः मेजबान देशों के अल्पसेवित क्षेत्रों में आते हैं। दक्षिण सूडान से युगांडा में शरणार्थियों ने पश्चिम नाइल उप-क्षेत्र में बस गए, जहां माध्यमिक शुद्ध उपस्थिति दर 2016 में राष्ट्रीय दर से आधी थी।

शरणार्थी शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहां डेटा उपलब्ध है, वहां तस्वीर साफ नहीं है। केन्या में दादाब शरणार्थी शिविर में, प्राथमिक स्कूल के 8% शिक्षक प्रमाणित राष्ट्रीय शिक्षक थे, और 10 शरणार्थी शिक्षकों में से 6 अप्रशिक्षित थे।

आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की शिक्षा की निगरानी करना मुश्किल है

कई संघर्ष-प्रभावित देशों में, आंतरिक विस्थापन पहले से ही शिक्षा प्रणालियों से जुड़ा रहा है। उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में, नवीनतम शिक्षा आवश्यकता के मूल्यांकन से पता चला है कि 260 स्कूल साइटों में से 28% स्कूल गोलियों, गोलों या शर्पनेल से क्षतिग्रस्त हो गए थे, 20% स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया, 32% स्कूलों में लूटपाट की गई थी और 29% स्कूल सशस्त्र समूहों या सेना के करीब स्थित थे।

यूएनएचसीआर ने जनवरी 2018 तक यूक्रेन में 1.8 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित किए जाने की सूचना दी थी। इनीप्रो, खार्किव, कीव और जापोरिझ्निया में, जिसमें सबसे अधिक आईडीपी हैं, शिक्षा संस्थानों को कक्षा की जगहों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए, सरकार ने अतिरिक्त स्कूल स्थान बनाए हैं, आईडी क्षेत्रों के लिए संघर्ष क्षेत्रों से राज्य विश्वविद्यालयों को स्थानांतरित किया है, दारखिला प्रक्रिया को सरल बनाया है, टयूशन को कवर किया है, ऋण और पाठ्यपुस्तक सहित प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

प्राकृतिक आपदाएं भी विशेष रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शिक्षा को बाधित करती हैं। फिलीपींस में सालाना औसतन 20 तूफान आते हैं और यहां ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्वलन का सबसे अधिक जोखिम रहता है। देश ने आपदा जोखिम में कमी लाने के उपाय किए हैं, और निर्देशात्मक संसाधनों से लैस तूफान प्रतिरोधी स्कूलों की उपलब्धता ने शिक्षा में औसतन 0.3 साल की वृद्धि की है।

विस्थापितों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में शामिल करने की आवश्यकता

संकट से निपटने के लिए, अधिकांश सरकारों की यह तुरंत प्रतिक्रिया होती है कि विस्थापित आबादी को समानांतर प्रणाली में शिक्षा प्रदान की जाए। हालांकि, इस पर आम सहमति हुई है कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। विस्थापन प्रायः लंबे समय तक चलता है। समांतर प्रणालियों में आमतौर पर योग्य शिक्षकों की कमी होती है। परीक्षा प्रमाणित नहीं होती। अल्प सूचना पर वित्त-पोषण के स्रोतों में कटौती की जा रही है।

2012-2016 यूएनएचसीआर वैश्विक शिक्षा कार्यनीति में पहली बार देशों से यह आग्रह किया गया है कि शरणार्थी बच्चों को उनकी शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता-प्राप्त और प्रमाणित शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शरणार्थियों को पूरी तरह से शामिल करना है ताकि वे मेजबान देश के बच्चों के साथ उसी कक्षा में अध्ययन कर सकें, यदि आवश्यक हो तो उन्हें उपयुक्त आयु के अनुसार ग्रेड स्तर पर स्कूल में दाखिल करने के लिए तैयार करें। लेकिन शरणार्थी

“

शरणार्थी की संख्या विस्थापन संदर्भों, भौगोलिकता, इतिहास, संसाधन उपलब्धता और प्रणाली क्षमता के प्रभाव के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

को शामिल करने की डिग्री विस्थापन संदर्भों में भिन्न होती है। भूगोल, इतिहास, संसाधन उपलब्धता और प्रणाली क्षमता शामिल करने की प्रकृति को प्रभावित करती है।

कुछ मामलों में, शामिल किए जाने की प्रक्रिया धीमी रही है। तुर्की, जिसमें 3.5 मिलियन शरणार्थी हैं, पहले मान्यता-प्राप्त गैर-सार्वजनिक स्कूलों को अस्थायी शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता देता है, तत्पश्चात् उन्हें ट्रांजिशनल स्कूलों के रूप में वर्गीकृत

किया जाता है, और 2020 तक सभी सीरियाई बच्चों को पब्लिक स्कूलों में शामिल किया जाएगा। अन्य मामलों में, सरकारी प्रतिबद्धता अस्थिर रही है। ईरान के इस्लामी गणराज्य में, अफगान शरणार्थियों को शामिल करने की नीति को पिछले चार दशकों में अनेक बार बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

कई मामलों में, प्रतिबद्धता के बावजूद शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। शरणार्थी मेजबान देश के पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और शिक्षा की भाषा साझा कर सकते हैं, लेकिन केन्या में शिविरों के रूप में भौगोलिक पृथक्कता के कारण उन्हें केवल आंशिक रूप से, या लेबनान और जॉर्डन में क्षमता की बाधा के रूप में डबल-शिफ्ट स्कूलों में शामिल किया गया है। ग्रीस जैसे अधिक संसाधनों वाले देशों को भी राष्ट्रीय प्रणाली के माध्यम से शरणार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

कई संदर्भों में, शरणार्थी शिक्षा अभी भी अलग-अलग प्रदान की जाती है। फिलीस्तीनी शिक्षा प्रणाली एक अद्वितीय मामला है। तंजानिया के संयुक्त गणराज्य में बुरुंडियन शरणार्थियों और थाईलैंड में म्यांमार के करेन शरणार्थियों ने अलग, गैर-औपचारिक समुदाय-आधारित या निजी स्कूलों में जाते हैं।

शामिल करने में आने वाली कई बाधाओं को दूर करने की जरूरत है

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में शरणार्थियों को शामिल करने से संबंधित कठिनाइयों को उन संदर्भों में सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जाता है जहां क्षमता कमजोर होती है और समन्वय और नियोजन की आवश्यकता अधिक होती है। योजनाओं में दस्तावेजों

“

अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव, भाषा समस्या, छूट गई पढ़ाई और छिपी लागत पूरी तरह से शामिल होने में बाधा बन सकती है

”

की कमी से लेकर सीमित भाषा प्रवीणता, और शिक्षा में बाधा से लेकर गरीबी दूर करने जैसे मुद्दों का समाधान करने की जरूरत है।

यूनेस्को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग ने ट्रांजिशनल शिक्षा योजनाओं पर मार्गदर्शन की रूपरेखा बनाई है जो तत्काल जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है तथा इसमें शरणार्थी और आईडीपी शामिल होते हैं। चाड 2013 में ऐसी योजना विकसित करने वाला पहला देश था। 2018 में, सरकार ने 19 शिविरों में 108 स्कूलों और शरणार्थी साइटों को नियमित पब्लिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया।

शरणार्थियों के पास प्रायः दस्तावेज नहीं होते, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों तक पहुंच को मुश्किल बनाती है। जॉर्डन में, शरणार्थियों को स्कूल जाने के लिए 'सेवा कार्ड' की आवश्यकता होती थी, और इसे प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती थी। हालांकि, 2016 के अंत में, जॉर्डन ने पब्लिक स्कूलों को बिना सेवा कार्ड वाले बच्चों को दाखिला देने की अनुमति देना शुरू कर दिया था।

स्थानीय भाषा के ज्ञान की कमी एक और बाधा है। रुवांडा में बुरुंडियन शरणार्थियों ने एक छमाही गहन परिचय पाठ्यक्रम में भाग लिया और जब वे अंग्रेजी के सही स्तर तक पहुंच गए तब उन्होंने पब्लिक स्कूलों में दाखिला ले लिया। जर्मनी में प्रस्तावित तैयारी कक्षाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन उनकी लंबी अवधि शरणार्थियों को शिक्षा प्रणाली से बाहर कर सकती है। शरणार्थियों की भाषा को न केवल बोलचाल की भाषा में बल्कि गैर-मौखिक अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। वे केवल तभी सीख सकते हैं यदि वे मेजबान समुदायों के साथ बातचीत करते हैं।

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम-जैसे संपर्क बनाने, सुधार करने, वांछित स्तर प्राप्त करने और त्वरित शिक्षा से-विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रणाली में दाखिला लेने या फिर से दाखिला लेने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं। दादाब में नार्वेजियन शरणार्थी परिषद के त्वरित शिक्षण कार्यक्रम में केन्या के आठ साल के पाठ्यक्रम को चार साल तक सीमित किया गया है, जिसमें बहु दाखिला और निकासी प्रक्रिया शामिल है। इसने लड़कों की शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि की है, हालांकि लड़कियों के मामले में ऐसा कम हुआ है। आदर्श रूप में, ऐसे कार्यक्रम सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए और उन्हें शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

यहां तक कि जहां शिक्षा निःशुल्क है, वहां पाठ्यपुस्तकों और परिवहन जैसी लागतें अधिक हो सकती हैं। लेबनान में एक प्रायोगिक परियोजना द्वारा परिवहन के खर्च को उठाने के लिए नकद राशि प्रदान की और आय की क्षतिपूर्ति की, इससे बच्चों ने काम करने की बजाय स्कूल में भाग लिया। इससे प्रति सप्ताह 0.5 से 0.7 दिनों में उपस्थिति में लगभग 20% की वृद्धि हुई। तुर्की की सरकार ने शरणार्थियों को सशर्त नकद राशि दी है और 2018 तक इसका लाभ 368,000 सीरियाई बच्चों को मिला था।

शिक्षक सफल रूप से शामिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं

विस्थापन स्थलों में शिक्षक, विशेष रूप से योग्य शिक्षकों की कमी होती है। तुर्की में सभी सीरियाई छात्रों के दाखिले के लिए लगभग 80,000 और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जर्मनी में, अतिरिक्त 18,000 पढ़ाने वालों और 24,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। युगांडा को शरणार्थी शिक्षा के लिए 7,000 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की आवश्यकता है।

निष्पक्ष और योग्य शिक्षक उपलब्धता में पर्याप्त शिक्षक आपूर्ति, भर्ती, प्रतिधारण और प्रेरणा शामिल होती है। फिर भी अधिक बजट और अल्पकालिक वित्त-पोषण चक्रों से सरकारों और मानवतावादी भागीदारों को वेतन का खर्च उठाने में समस्या हो सकती है। प्रायः शरणार्थियों का स्वयंसेवक शिक्षकों के रूप में उपयोग करना, और उन्हें भुगतान करना आम है लेकिन शिक्षक वेतन में असमानता तनाव पैदा कर सकती है।

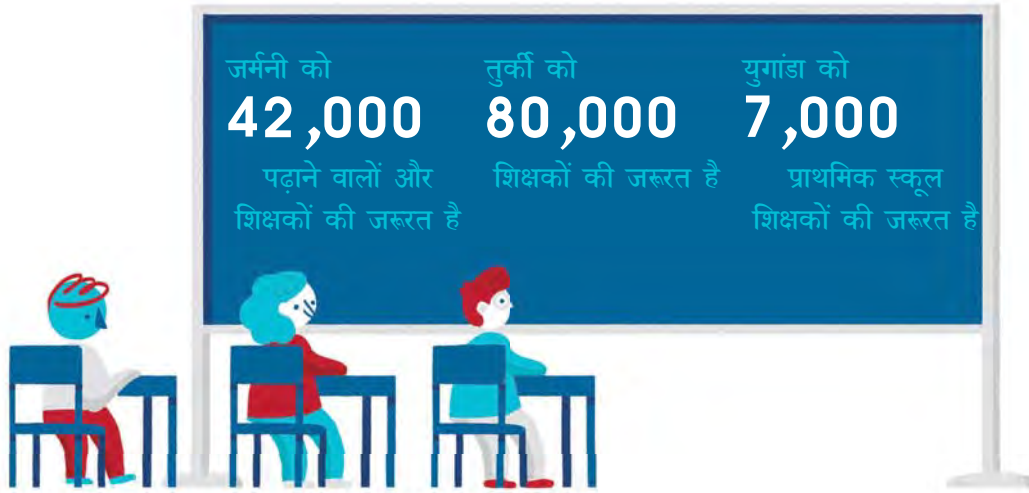
विस्थापन संदर्भों में शिक्षकों को भीड़भाड़ वाली कक्षाओं, अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों या बहुभाषी कक्षाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें प्रायः केवल मामूली सहायता ही मिलती है। लेबनान में, 55%

“

शिक्षक को विस्थापन के संदर्भ में भीड़, मिश्रित आयु या बहुभाषी कक्षाओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें प्रायः मामूली सहायता ही मिलती है

”

शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर आने के कारण शिक्षक की कमी को पूरा करना:



शिक्षकों और कर्मचारियों ने पिछले दो वर्षों में पेशेवर विकास में भाग लिया था, हालांकि शरणार्थी बच्चों की उपस्थिति ने उनके दैनिक शिक्षण को प्रभावित किया था। काकुमा शिविर, केन्या में शिक्षकों की सहायता करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण में औपचारिक शिक्षण डिप्लोमा और अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण-पत्र कार्यक्रम, तथा आपात स्थिति में शिक्षा के लिए अंतर-एजेंसी नेटवर्क द्वारा समस्याग्रस्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए विकसित गैर-प्रमाणित पाठ्यक्रम शामिल है।

कार्य का अधिकार संबंधी पेशेवर नियमों के कारण शरणार्थी शिक्षकों को प्रायः राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बाहर रखा जाता है। कुछ देश काम पर लौटने की शर्त पर शरणार्थी शिक्षकों का समर्थन करते हैं। चाड ने सूडानी शिक्षकों को अपने स्कूलों में काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित किया है। जर्मनी में, पॉट्सडैम के शरणार्थी शिक्षक कार्यक्रम का उद्देश्य सीरियाई और अन्य शरणार्थी शिक्षकों को कक्षा में लौटने में सक्षम बनाना है।

उच्च आय वाले देशों में छात्रों में आघात के बाद तनाव विकार की व्याप्तता दर 10% से 25% तक है तथा निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में यह 75% तक पहुंच गई है। जहां बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वहां स्कूल ही एकमात्र जगह हो सकती है, जहां ऐसी सहायता उपलब्ध होती है। हालांकि, स्कूल-आधारित कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों की आवश्यकता होती है और यह शिक्षकों के कौशल से परे होती है। शिक्षक शिक्षार्थियों और स्थापित मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के द्वारा बातचीत के माध्यम से एक सुरक्षित और सहायक माहौल बनाकर मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। उन्हें कक्षा प्रबंधन और रेफरल प्रणाली पर पेशेवर विकास की आवश्यकता है।

शरणार्थियों को बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता होती है

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल (ईसीईसी) सहित उचित कार्यक्रमों, हिंसक संदर्भों में छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें अन्यथा स्थिरता, पोषण और समृद्ध वातावरण का अभाव रहता है। हालांकि, कई विस्थापन जगहों में, शुरुआती सीखने की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती।

ऊपरी मध्यम और उच्च आय वाले आठ देशों का अध्ययन करने से पता चला है कि सबसे कम उम्र के शरणार्थियों और शरण लेने वालों की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया 'असाधारण रूप से कमजोर' रही है, जो राष्ट्रीय नीति बनाने में प्राथमिकता की कमी और योजना और वितरण के लिए अलग जिम्मेदारी को दर्शाती है। 26 मानवतावादी और शरणार्थी प्रतिक्रिया योजनाओं की एक समीक्षा से पता चला है कि 5 वर्ष से कम आयु के लगभग आधे बच्चों के लिए सीखने या शिक्षा प्राप्त करने, और एक-तिहाई से भी कम प्राथमिक शिक्षा या ईसीईसी का इन योजनाओं में कोई उल्लेख नहीं था।

गैर-सरकारी संगठन आम तौर पर कमी को पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति ने बुरुंडी और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के शिविरों में कागोली बच्चों के लिए हीलिंग क्लासरूम प्री-स्कूल शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम 2014 में लेबनान के लिए बनाया गया था, जहां यह अब 3,200 प्री-स्कूल बच्चों की देखरेख करता है और 128 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। चार महीने के प्रायोगिक योजना के बाद, 3 साल के बच्चों ने मोटर कौशल, सामाजिक-भावनात्मक कौशल, कार्यकारी कार्य और प्रारंभिक साक्षरता और गिनती में सुधार दिखाया।

कुछ देशों ने कई स्थानीय और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। इथियोपिया की सरकार शिविरों में 80 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के पांच में से तीन शरणार्थी बच्चों और अदीस अबाबा में 150 निजी और सार्वजनिक किंडरगार्टन का समर्थन करती है। जर्मन सरकार ने शरणार्थी और आश्रय-साधक शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना अपनाई है, जिसमें उपनगरों के साथ साझेदारी की जा रही है और 2017-2020 में अपने ईसीईसी कार्यक्रमों और कर्मचारियों का विस्तार करने के लिए लगभग 400 मिलियन यूरो निवेश करने की योजना बना रही है।

विकलांग शरणार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष जोरविम होता है

अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रावधान शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं। अक्षमता का देखकर, चिकित्सा मूल्यांकन या स्वयंसेवी सूचना द्वारा मूल्यांकन किया जाता था, जिससे विस्थापित आबादी के बीच प्रकृति और अक्षमता की दर को बहुत कम आंका गया। हाल की पद्धति में व्यवस्थित, कार्यक्षमता-आधारित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है जैसे वाशिंगटन समूह द्वारा विकसित पद्धति।

“
विस्थापन स्थलों में बहुत कम विशिष्ट
स्कूल हैं और वे अच्छा-खासा शुल्क
लेते हैं

हानि और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार विकलांगता का अनुभव
व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। पाकिस्तान में अफगानों के बीच
एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को देखने संबंधी समस्या
थी, उनके स्कूल में भाग लेने की संभावना अधिक थी (52%);
जिन्हें स्वयं की देखभाल संबंधी समस्याएं थीं, उनके भाग लेने की
संभावना बहुत कम (7.5%) थी।

कम शारीरिक पहुंच-दूरी और सुविधाओं दोनों के संदर्भ में और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, दिव्यांग लोगों के लिए प्रमुख बाधाएं हैं, जैसा इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया गया है। विस्थापन स्थानों में शायद ही कोई विशेष स्कूल हो, और वे आम तौर पर शुल्क लेते हैं। दिव्यांगता सामाजिक कलंक या आपरावासन या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृति के डर से छुपाई जा सकती है या रिपोर्ट नहीं की जाती है। हालांकि, इस तरह की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। जॉर्डन में नए शरणार्थी शिविरों में ऐसे बुनियादी ढांचों को शामिल किया जा रहा है।

मेजबान देश और शरणार्थी समुदायों के साथ मिलकर मौजूदा संख्या की पहचान करना आवश्यक है। समन्वयक संगठन की एक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय यूगांडा दिव्यांग संघ का उद्देश्य विकास गतिविधियों में विकलांगों के साथ शरणार्थियों को शामिल करना है। युगांडा राष्ट्रीय बधिर एसोसिएशन दो शरणार्थी बस्तियों के पास बधिर बच्चों के लिए स्कूल चलाता है।

प्रौद्योगिकी विस्थापित लोगों की शिक्षा में सहायता कर सकती है

जबरन विस्थापन प्रायः शिक्षा प्रणालियों को छिन्न-भिन्न कर देता है। तकनीकी समाधान, उनकी क्षमता, गति, गतिशीलता और सहज आवागमन क्षमता, मानक शिक्षा संसाधनों की कमी की भरपाई में मदद के लिए कारगर हो सकते हैं। तत्काल नेटवर्क स्कूल कार्यक्रम नामक यूएनएचसीआर और वोडाफोन की एक संयुक्त पहल के द्वारा कांगो, केन्या, दक्षिण सूडान के लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य में 20 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 40,000 से अधिक छात्रों और 600 शिक्षकों को इंटरनेट, बिजली और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

ऐसे कार्यक्रमों की एक चुनौती यह है कि प्रदान किए गए संसाधन प्रायः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होते हैं। लेबनान में ताबशौरा (चाक) जैसे कुछ अपवाद हैं, जो 2015 के पाठ्यक्रम के साथ-साथ नर्सरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन संसाधन प्रदान करते हैं। अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में उपलब्ध, यह एक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो मूडल आधारित है।

प्रौद्योगिकी मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन भी प्रदान कर सकती है। एनजीओ लाइब्रेरीज विदाउट बार्डर्स और यूएनएचसीआर द्वारा विकसित पैकेज, आइडिया बॉक्स, में शिक्षा सामग्री सहित सूचनात्मक और सांस्कृतिक संसाधन शामिल हैं। कांगोली शरणार्थियों की मेजबानी में दो बुरुंडी शिविरों में गुणात्मक मूल्यांकन का पुनरुत्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अधिकांश कार्यक्रम शिक्षक की पेशेवर क्षमता के विकास का समर्थन करते हैं। नाइजीरिया में नोकिया के सहयोग से यूनेस्को शिक्षक शिक्षा परियोजना ने प्राथमिक शिक्षकों की योजनाएं बनाने, प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न पूछने, त्वरित प्रतिबिंबित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने तथा अंग्रेजी भाषा और साक्षरता कक्षाओं में छात्रों का आकलन करने में मदद की।

प्रौद्योगिकी पहल की अपनी चुनौतियां हैं। इसके लिए आम तौर पर काफी अधिक निवेश करना पड़ता है, और सभी के पास पर्याप्त बिजली और कनेक्टिविटी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीक औपचारिक स्कूली शिक्षा में

भागीदारी का स्थान नहीं ले सकती। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहल का बेहतर ढंग से समन्वय किया जाए और यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में शरणार्थियों को शामिल करने के अंतिम उद्देश्य को पूरा करें।

विभिन्न उच्च स्तरीय शिक्षा पहल शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करती हैं

उच्च स्तरीय शिक्षा के अवसर शरणार्थियों की रोजगार संभावनाओं को बढ़ाते हैं तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने और उसमें बने रहने में योगदान देते हैं। फिर भी शरणार्थियों की उच्च स्तरीय भागीदारी का अनुमान केवल 1%

“

उच्च स्तरीय

शिक्षा प्राप्त

करने वाले

शरणार्थी केवल

1% हैं

है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रायः यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती और इस पर संगठित रूप से तभी ध्यान दिया जाता है जब विस्थापन के लम्बा रहने की संभावना हो। शरणार्थियों के उच्च स्तरीय शिक्षा अधिकारों की प्रायः बिना किसी भेदभाव के प्रदान करने के रूप में व्याख्या की जाती है।

प्रौद्योगिकी आधारित पहल विस्थापित आबादी तक पहुंच सकती है। यूएनएचसीआर और जेनेवा विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई कनेक्टेड लर्निंग इन क्राइसिस कंसोर्टियम में आमने-सामने और ऑनलाइन शिक्षा को जोड़ा जाता है और 2010 से यह 6,500 छात्रों तक पहुंचाई गई है।

”

शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन अकादमिक शरणार्थी पहल निधि (डीएफआई) शामिल है, जिसने 1992 से यूएनएचसीआर के माध्यम से

शरणार्थियों को सहायता प्रदान की है। भौगोलिक कवरेज शरणार्थी आंदोलनों और शिक्षा आवश्यकताओं के आधार पर समायोजित की गई है। वर्तमान में, इथियोपिया, ईरान के इस्लामी गणराज्य, लेबनोन और तुर्की में इसके सबसे बड़े कार्यक्रम हैं।

अन्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम उच्च आय वाले देशों में अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। कनाडा की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस का छात्र शरणार्थी कार्यक्रम विश्वविद्यालय-आधारित उन समितियों को सहायता देता है जो अपने संस्थान में पुनर्वास और अध्ययन के लिए एक शरणार्थी प्रायोजित करने की इच्छा रखते हैं। 1978 के बाद से, इसके द्वारा 39 देशों से 1,800 शरणार्थियों को पूरे कनाडा में 80 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लाया गया है।

अकादमिकों को भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। स्कालर्स एट रिस्क द्वारा शिक्षा की आवश्यकता वाले शिक्षाविदों के लिए अस्थायी अनुसंधान और शिक्षण पदों की व्यवस्था की जाती है। यूनाइटेड किंगडम में काउंसिल फॉर एट-रिस्क अकादमिक (सीआरए) विशेषकर घर पर रहने वाले शिक्षाविदों के लिए तत्काल सहायता प्रदान करता है।

सहायता के लाभ व्यापक समुदाय तक पहुंचने चाहिए। डीएफआई छात्रवृत्ति मूल समुदायों को छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता से परे, इच्छुक लाभार्थियों के रूप में मान्यता देती है, और बहुत नहीं तो अधिकांश डीएफआई विद्वान अपने मूल देश लौट जाते हैं। शरणार्थी शिक्षाविदों की सहायता के लिए नेटवर्क उनके क्षमता निर्माण को भी बढ़ा सकता है। सीएआरए ने इराक, सीरियाई अरब गणराज्य और जिम्बाब्वे में अनुसंधान और शिक्षण क्षमता के पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

आईडीपी को शरणार्थियों की तरह शिक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

हालांकि आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह उल्लेख किया गया है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्षमता और राजनीति समस्या की पहचान और समाधान के लिए समन्वय करने, दोनों में बाधा उत्पन्न करती है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की शिक्षा की स्थिति पर कानूनी, शैक्षिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया प्रायः शरणार्थियों के लिए उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होती है।

कोलंबिया सरकार, जहां 2017 में 6.57 आईडीपी रहते हैं, ने कानूनी सुरक्षा ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है। 2002 में, संवैधानिक न्यायालय ने नगरपालिका शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के उपयोग के मामले में विस्थापित बच्चों का विशेष रूप से इलाज करने का निर्देश दिया। 2004 में, अदालत ने यह कहा कि शिक्षा के अधिकार सहित आईडीपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

“ आंतरिक रूप से विस्थापित शिक्षक प्रायः अपने गृह जिले की प्रशासनिक निगरानी में रहते हैं, जिससे वेतन प्राप्त करना लगभग असंभव होता है ”

विस्थापन का अर्थ है कि कई बच्चों और किशोरों की शिक्षा प्रणाली में बाधा आएगी और उन्हें शिक्षा प्रणाली में फिर से दाखिला लेने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान में, चिल्ड्रन इन क्राइसिस नामक एक एनजीओ, काबुल में और उसके आसपास अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले स्कूल छोड़ चुके आईडीपी छात्रों को ग्रेड 6 तक की शिक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक समुदाय आधारित त्वरित कार्यक्रम चलाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है।

आंतरिक रूप से विस्थापित शिक्षक प्रायः अपने गृह जिले की प्रशासनिक निगरानी में रहते हैं, जिससे सीरियाई अरब गणराज्य में वेतन प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। इराक में, 44 सल्लेदार 15 प्रशासनिक ढांचों को सेवाएं प्रदान करते हैं और लगभग 5,200 शिक्षकों को अनुदान या प्रोत्साहन सहायता देते हैं, हालांकि खराब समन्वय से सेवा में बाधा और शिक्षक श्रेणियों के बीच असमानता और भागीदारों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है।

प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा प्रणालियों को तैयार और उत्तरदायी होना आवश्यक है

शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं को जीवन हानि, बुनियादी ढांचे के नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपातकालीन व्यवस्था द्वारा बहाली करते समय शिक्षा सेवाएं कम से कम बाधित हों। 2017 में, आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति तथा आपदा जोखिम में कमी और शिक्षा क्षेत्र में लचीलेपन के लिए वैश्विक गठबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपने नवीनतम व्यापक स्कूल सुरक्षा ढांचे को लांच किया। इसके तीन स्तंभ सुरक्षित शिक्षा सुविधाएं, स्कूल आपदा प्रबंधन, और जोखिम न्यूनता एवं शिक्षा पुनरुत्थान हैं।

प्रशांत द्वीप से सटे कई राष्ट्र शिक्षा योजनाओं में जलवायु परिवर्तन जोखिम को भी ध्यान में रखते हैं। 2011 में, आपातकालीन स्थितियों में आपदा तैयारी और शिक्षा के लिए सोलोमन द्वीप नीति विवरण और दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों को आपातकाल के पहले, उसके दौरान और बाद में सुरक्षित शिक्षा माहौल मिलना जारी रहे, और सभी स्कूलों ने अस्थायी शिक्षा और शिक्षण स्थान की पहचान की थी।

कुछ दशकों में, जलवायु विस्थापन के मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 140 मिलियन लोग विस्थापित हो जाएंगे। इसके जोखिम को कम करने के लिए, कुछ देश पहले से ही नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं। किरिबाती सरकार की 'गरिमा के साथ प्रवास' नीति, दीर्घकालिक राष्ट्रव्यापी स्थानांतरण रणनीति का हिस्सा है, का उद्देश्य लोगों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें नर्सिंग जैसे व्यवसायों में विदेशों में सभ्य कार्य अवसर उपलब्ध कराना है।

विविधता

विविधता को महत्व देने वाली शिक्षा सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें समावेशी समाज बनाने में सक्षम बनाती है, जिसमें मतभेदों पर विचार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है तथा सभी को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्रवासियों और शरणार्थियों पर कभी-कभार उनके व्यक्तिगत गुणों की बजाय समूह के रूप में पहचान करके निर्णय लिए जाते हैं। विशेष रूप से जब वे मेजबान आबादी से काफी अलग दिखते हों, तो उन्हें 'अन्य' के रूप में देखा जा सकता है, तथा रूढ़िवाद और पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव किया जा सकता है, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान न करना भी शामिल होता है।

उनके खिलाफ नीतियों के बावजूद, कई शिक्षा प्रणालियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव मौजूद होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासी परिवारों के छात्रों के खिलाफ ढांचागत भेदभाव बरता जाता है जिसमें युवा बच्चों के लिए द्विभाषी कार्यक्रम न होना तथा साक्षरता परीक्षा घरेलू भाषाओं में न लेना शामिल होता है।

सार्वजनिक दृष्टिकोण भी आप्रवासियों की विचारधारा और कल्याण को आकार देते हैं। भेदभाव अवसाद, चिंता और आत्म-सम्मान से जुड़ा होता है। 2014 विश्व मूल्य सर्वेक्षण के अनुसार, आप्रवासियों के मेजबान देश में खुद को उनका मूल निवासी समझने की संभावना कम होती है।

शिक्षा आप्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है

शिक्षा स्तर आप्रवासियों के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। अधिक शिक्षित लोग जाति की परवाह नहीं करते, वे सांस्कृतिक विविधता को महत्व देते हैं और पलायन के आर्थिक प्रभाव को अधिक सकारात्मक रूप में देखते हैं। शोध से पता चला है कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोगों की तुलना में दो प्रतिशत अधिक सहनशील थे, जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लोगों की तुलना में दो प्रतिशत अधिक सहनशील थे। युवा लोग, विशेष रूप से अत्यधिक शिक्षित लोग भी आप्रवासन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

“

शिक्षा सही तस्वीर उजागर करके मीडिया द्वारा चित्रित नकारात्मक सोच को दूर करने तथा राजनीतिक समझ और सकारात्मक सोच पैदा करने में कारगर भूमिका निभा सकती है

”

मीडिया द्वारा आप्रवासियों और शरणार्थियों का नकारात्मक चित्रण भी पूर्वाग्रह को सुदृढ़ कर सकता है। पलायन और विस्थापन के मुद्दों की मीडिया कवरेज, उदाहरण के लिए कनाडा, चेक गणराज्य, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम में लगातार नकारात्मक और केंद्रित रही है, जहां मीडिया द्वारा आप्रवासियों और शरणार्थियों को प्रायः संस्कृति, सुरक्षा और हितों के खतरे के रूप में चित्रित किया जाता है। पलायन से संबंधित मीडिया कहानियां प्रायः रूढ़िवादी होती हैं, जिनमें आप्रवासी या शरणार्थी की आवाज को दबा दिया जाता है और उनके बारे में गलत शब्दावली का उपयोग किया जाता है। शिक्षा सही तस्वीर उजागर करके मीडिया द्वारा चित्रित नकारात्मक सोच को दूर करने तथा राजनीतिक समझ और सकारात्मक सोच पैदा करने में कारगर भूमिका निभा सकती है।

शिक्षा नीतियों और प्रणालियों का आधार समावेश करना होना चाहिए

देश शिक्षा प्रणालियों में विविधता से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं: जैसे विलय, बहुसांस्कृतिकवाद/एकीकरण और अंतर-सांस्कृतिकता/समावेशन। विलय प्रवासी पहचान के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके विपरीत अंतर-सांस्कृतिकता छात्रों को न केवल दूसरी संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करती है बल्कि असमानता को कायम रखने वाले मेजबान देशों में टांचागत समस्याओं के बारे में भी बताती है।

कुछ देशों में बहुसांस्कृतिक या आंतरिक-सांस्कृतिक शिक्षा पर विशिष्ट नीतियां हैं। आयरलैंड, जहां 2015 में 15 वर्ष से कम आयु के अप्रवासी बच्चे आबादी का 15% थे, ने आंतरिक-सांस्कृतिक शिक्षा कार्यनीति 2010-2015 विकसित की, जिसका उद्देश्य प्रदाता की क्षमता विकसित करना, भाषा दक्षता प्राप्त करने में सहायता करना, नागरिक समाज के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना और निगरानी में सुधार करना था। इसके अलावा, कानून ने बाधाओं को हटा दिया, शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया और स्कूलों को दाखिला नीतियों को प्रकाशित करने के लिए कहा। यूरोपीय संसद द्वारा कराए गए अध्ययन में पाया गया कि आयरलैंड और स्वीडन में आप्रवासी शिक्षा के लिए यूरोप की सबसे सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था थी।

राजनीतिक प्रभाव आंतरिक-सांस्कृतिक शिक्षा नीतियों को कमजोर कर सकते हैं। नीदरलैंड्स में, आप्रवासियों के प्रति बिगड़ते हालात ने एकीकरण नीति को बढ़ावा दिया है जो उच्च समाज के प्रति निष्ठा पर केंद्रित है, जिसमें सांस्कृतिक शिक्षा को नागरिकता शिक्षा के साथ बदल जा रहा है।

आप्रवासी छात्रों की भावनाओं के विकास में एक और आयाम प्रवासी स्कूल हैं जो मूल देश के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। सरकार द्वारा प्रबंधित या समन्वित स्कूल हो सकते हैं, जैसा कि पोलैंड के मामले में है; आप्रवासी समुदायों द्वारा स्थापित निजी स्कूल, जैसा कि सऊदी अरब में फिलिपिनो या जापान में ब्राजीलियाई लोगों के मामले में है; और अनौपचारिक स्कूल, जो घरेलू देश की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान देते हैं।

पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक अधिक समावेशी बन रहे हैं

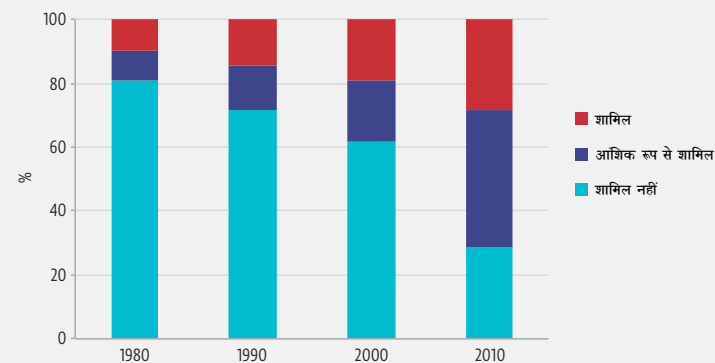
पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक पूर्वाग्रह को कम कर सकती हैं और प्रवासियों में अपनेपन की भावना विकसित कर सकती हैं। 2016 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और नागरिकता शिक्षा सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 22 देशों में से 12 देशों में जातीय समूहों के अधिकारों के समर्थन के लिए अन्य देशों के इतिहास के बारे में सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा था।

बढ़ती सामाजिक विविधता को दर्शाने के लिए और अधिक देश अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहे हैं। बहुसांस्कृतिकवाद पर नीति सूचकांक के लिए 21 उच्च आय वाले देशों में विश्लेषण किया गया, जिसमें केवल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 1980 में पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिकता पाई गई थी। 2010 तक, दो-तिहाई देशों में कुछ हद तक बहुसांस्कृतिकवाद एजेंडा शामिल था और चार अतिरिक्त देशों नामतः फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन में यह पूरी तरह से एकीकृत था (चित्र 4)।

2015 में, 38 में से मुख्यतः 27 उच्च आय वाले देशों ने अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा एक अकेले विषय के रूप में प्रदान की, इसे पाठ्यक्रम में एकीकृत किया, या दोनों प्रदान किए। बहुसांस्कृतिक और अंतर-सांस्कृतिक

चित्र 4:

अनेक देशों के पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिकता शामिल है
21 उच्च आय वाले देशों के पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिकता शामिल थी, 1980-2010



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig5_2

टिप्पणी: बहुसांस्कृतिकता की परिभाषा मुख्य रिपोर्ट की तालिका 5.1 में अंतर-सांस्कृतिकता की परिभाषा से काफी अधिक मिलती-जुलती है।

स्रोत: वेस्टलेक (2011)

मूल्यों को अलग-अलग विषयों में शामिल किया जा सकता है। इतिहास पाठ्यक्रम प्रायः जातीय केंद्रित होता है, जबकि अन्य विषय भिन्न होते हैं, जैसे जर्मनी में भूगोल और इंग्लैंड में नागरिकता (यूनाइटेड किंगडम)। कुछ आधुनिक पाठ्यपुस्तकों में प्रवास संबंधी विवादास्पद मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। मेक्सिको में, पाठ्यपुस्तकों में अनियंत्रित प्रवासियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों पर चर्चा शामिल नहीं होती है। हालांकि, कोट डी'आईवोयर में पाठ्यपुस्तकों में 2002 में राजनीतिक संकट के बाद प्रमुख शरणार्थियों और विस्थापन पर चर्चा की गई है।

पाठ्यचर्चा को स्थानीय रूप से अपनाया जा सकता है, जैसे अल्बर्टा, कनाडा में शिक्षण संसाधन आप्रवासी और शरणार्थी निर्देश और शिक्षा का समर्थन करते हैं, जिनमें विशिष्ट समुदायों, जैसे करेन, सोमालियों और दक्षिण सूडान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें स्कूल का सशक्त नेतृत्व भी मदद कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां स्कूल विविधता को महत्व देते हैं, वहां छात्रों द्वारा अंतर-सांस्कृतिक चर्चा में शामिल होने की संभावना अधिक रहती है।

शिक्षण में उन गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकता है जो विभिन्न दृष्टिकोणों में खुलेपन को बढ़ावा देती हैं, ताकि छात्र महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित कर सकें। अनुभव और सहकारी शिक्षा से अंतर-सांस्कृतिक संबंधों में सुधार करने, मतभेदों को दूर करने और पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिल सकती है।

प्रशिक्षण जो विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षकों को तैयार करता है, अधिकांश देशों में अनिवार्य नहीं है

शिक्षकों को विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लातविया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में साक्षात्कार लिए गए 52% शिक्षकों ने विविधता से निपटने के लिए प्रबंधन से पर्याप्त समर्थन न मिलने की बात कही। शिक्षक की शिक्षा में विविधता किस सीमा तक शामिल है, यह अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न होता है। नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में, शिक्षक उम्मीदवार विविध पृष्ठभूमि से छात्रों का समर्थन करने के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम चुनते हैं। यूरोप में आमतौर पर ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करना वैकल्पिक होता है।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में व्यावहारिक अध्यापन की तुलना में सामान्य ज्ञान पर जोर दिया जाता है। 49 देशों में 105 कार्यक्रमों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तैयार शिक्षकों में से केवल एक/पांच शिक्षकों को ही अंतर-सांस्कृतिक संघर्षों का अनुमान लगाने, उनका समाधान करने या आवश्यकता पड़ने पर छात्रों के लिए उपलब्ध मनोवैज्ञानिक उपचार और रेफरल विकल्पों की समझ थी। इस संबंध में सेवाकालीन शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता थी। 2013 ओईसीडी शिक्षण और अध्यापन अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि 34 शिक्षा प्रणालियों में से केवल 16% निम्न माध्यमिक शिक्षकों ने पिछले वर्ष में बहुसांस्कृतिक या बहुभाषी शिक्षा प्रशिक्षण में भाग लिया था।

आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों के प्रभाव पर कुछ अध्ययन किए गए हैं, और जो मौजूद हैं, वे पहले और बाद की पीढ़ी के आप्रवासियों या आप्रवासी एवं अल्पसंख्यक शिक्षकों के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि शिक्षकों के बीच विविधता आप्रवासी छात्र उपलब्धि, आत्म-सम्मान और सुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। हालांकि, यूरोप में छात्र निकाय संरचना में आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। इस पेशे में शामिल होने और भर्ती में भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रह वाली नीतियां इस कमी को आंशिक रूप से उजागर करती हैं।

हिंसक कट्टरता को रोकने में शिक्षा की अहम भूमिका है

राज्य और गैर-राज्य नागरिकों को लक्षित करने वाली हिंसक कट्टरता और आतंकवादी हमले निस्संदेह सीधे तौर पर प्रवासन और विस्थापन का कारण बनते हैं, लेकिन उच्च आय वाले देशों में आम जनता की राय इसके विपरीत आतंकवाद को प्रवासन से जोड़ती है। फिर भी, ऐसा कोई रिश्ता बहुत क्षुद्र होता है, विदेशियों द्वारा किए गए हमले नागरिकों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और कट्टरपंथीकरण का रास्ता अनेक रूप ले सकता है।

कट्टरता के उभरने को रोकना आतंकवाद से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कट्टरपंथी विकास चुनौतियों को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं या विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर को प्रभावित करते हैं और उपेक्षा का एक दुष्क्रम बनाते हुए उनका शोषण करते हैं।

“ विविधता, शांति और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देकर, शिक्षा कट्टरपंथी को रोकने का कार्य कर सकती है

विविधता, शांति और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देकर, शिक्षा कट्टरपंथी को रोकने का कार्य कर सकती है। हिंसक चरमपंथी शिक्षा को प्रायः एक खतरे के रूप में देखते हैं और स्कूलों पर नाइजीरिया में बोको हरम जैसे हमले करते हैं।

इसके विपरीत, शिक्षा से वंचित रखने से कट्टरपंथी का खतरा बढ़ सकता है। शिक्षा के लाभ से वंचित रखना भी उतना ही हानिकारक होता है। आठ अरब देशों में, बेरोजगारी ने अधिक शिक्षित लोगों में कट्टरपंथी की भावना पैदा की, जिनकी आर्थिक प्रगति उम्मीद से कम हुई थी।

कई देशों में पाठ्यक्रम में हिंसक कट्टरपंथी को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन शिक्षण सामग्री हमेशा इसके अनुरूप नहीं होती। दुनिया भर में, 10 प्रासंगिक पाठ्यपुस्तकों में से 1 में सशस्त्र संघर्ष को रोकने या संघर्ष समाधान या सुलह तंत्र पर चर्चा शामिल होती है - इसमें 1950 के दशक के बाद से थोड़ी वृद्धि हुई है।

शिक्षक सहिष्णु दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक तरीकों, जैसे सहकर्मी शिक्षा, अनुभव से प्राप्त शिक्षा, टीम का कार्य, भूमिका निभाना और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जो महत्वपूर्ण सोच और खुली चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं, सबसे प्रभावी होते हैं। लेकिन शिक्षकों को अपने छात्रों पर पुलिस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए या सुरक्षा के नाम पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित नहीं करनी चाहिए।

स्कूल हिंसक चरमपंथ को रोकने के लिए उपयुक्त स्थल हो सकते हैं जिसमें शिक्षा के बाहर हितधारकों को जोड़ा जा सकता है। इंडोनेशिया में कुछ कार्यक्रमों में विषयों को छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए पीड़ितों की आवाज का उपयोग किया जाता है। हिंसक चरमपंथ के खिलाफ शिक्षा जेंडर संवेदनशील होनी चाहिए जिसमें महिलाओं और लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए। कभी-कभी महिलाएं ऐसी शिक्षा पहलों का नेतृत्व करती हैं। उदारहण के लिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत में, एक महिला संगठन ने 35,000 महिलाओं और 2,000 युवाओं को मध्यस्थता और संघर्ष परिवर्तन कौशल सिखाया है।

अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है लेकिन उदारवादी समाज बनाने में इसकी भूमिका नकारात्मक होती है

पलायन और विस्थापन के मुद्दों के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना स्कूल की चारदीवारी के बाहर भी होता है। अनौपचारिक शिक्षा के कई रूप और उद्देश्य होते हैं। दुर्भाग्यवश, चूंकि सरकारें इसे प्रदान नहीं करतीं, अतः इस पर व्यवस्थित जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है।

पलायन पर अनौपचारिक शिक्षा में सामुदायिक केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुर्की में, एनजीओ युवा संघ एसोसिएशन सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से भाषा पाठ्यक्रम और कौशल कार्यशालाएं प्रदान करती है। सांस्कृतिक प्रदाता या दलाल अनुवाद सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और शिक्षा प्रणाली के संचालन में मदद कर सकते हैं। स्वीडन की लिंकोपिंग नगर पालिका ने सोमाली या अरबी भाषा के ज्ञान के साथ अपने एक साथ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 'लिंक पीपुल' के रूप में कार्य करने के लिए अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। साओ पाउलो, ब्राजील के अनुसार शहर विदेशी लोगों से घृणा के खिलाफ शिक्षा के प्रयासों को अपना सकते हैं, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए इसमें आप्रवासी समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए कला और खेल शक्तिशाली माध्यम हैं। नॉर्वे और स्पेन में सामुदायिक उत्सव अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए जगह प्रदान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कैजर चीफ फुटबॉल टीम ने देश में विदेशियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है।

छात्रों और पेशेवरों की सक्रियता

तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया में, युवा विदेशों में पढ़ते हैं और कुशल पेशेवर अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों की तलाश करते हैं। कुशल सक्रियता के व्यक्तियों, संस्थानों और देशों को कई प्रकार के लाभ, लागत और जोखिम होते हैं।

उच्च स्तरीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कई रूप लेता है

उच्च स्तरीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में वैश्विक शैक्षणिक वातावरण से निपटने के लिए अकादमिक प्रणालियों और संस्थानों - और यहां तक कि व्यक्तियों - द्वारा लागू नीतियां और प्रथाएं भी शामिल होती हैं। इसमें छात्रों और संकाय के आंदोलन के साथ-साथ पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और संस्थानों शामिल होते हैं जो घर और विदेशों में शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से आधे अंग्रेजी बोलने वाले पांच देशों में जाते हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रांस और जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शेयर क्रमशः 8% और 6% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि वे अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम पढ़ाते हैं। 2016 में चीन, भारत और कोरिया गणराज्य से विदेश जाने की दर 25% थी। 2016 में यूरोप से जाने वाले लोगों की दर कुल 23% थी जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन 0.9 मिलियन बाहर जाने वाले यूरोपीय छात्रों में से 76% क्षेत्र के भीतर ही रहते हैं।

“

सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से आधे, अंग्रेजी बोलने वाले पांच देशों में जाते हैं जबकी एशिया के तीन राष्ट्रों से विदेश जाने की दर 25% थी

”

छात्र देश या विदेशों में शिक्षा के लिए जाने-माने घरेलू विश्वविद्यालयों, भुगतान करने की क्षमता और सापेक्ष शिक्षा गुणवत्ता के आधार पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं। छात्रों की काम करने की क्षमता संबंधी नीतियां भी इसमें कारगर भूमिका निभाती हैं। 2011-2014 में, नीति में स्नातकोत्तर कार्य वीजा को सीमित करने के बाद, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय छात्र संख्या लगभग 50% गिर गई (इस दौरान

ऑस्ट्रेलिया में उनकी संख्या 70% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 37% बढ़ गई। चीन और जर्मनी सहित कुछ देश स्थानीय कौशल कमी को पूरा करने के लिए अपने श्रम बाजारों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

विश्वविद्यालयों के लिए, राजस्व जुटाना अंतर्राष्ट्रीय छात्र भर्ती का एक मुख्य कारक है। 2016 में, अंतरराष्ट्रीय छात्रों से अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को अनुमानित 39.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ। कई एशियाई देशों में जन्म दर घटने और बढ़ती उम्र की आबादी के कारण, जैसे कि जापान, उच्च स्तरीय शिक्षा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने संस्थान के दरवाजे खोले हुए हैं।

मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से हैं जो गतिशीलता कार्यक्रमों का उपयोग सांस्कृतिक कूटनीति और विकास सहायता के रूप में करते हैं। छात्रों को विदेश भेजने वाले ब्राजील और सऊदी अरब सहित कुछ देश विकास रणनीति के रूप में विदेशों में अध्ययन सब्सिडी देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिर संकाय अभिजात वर्ग के विश्वविद्यालयों द्वारा मांगे जाने वाले शिक्षाविदों, स्थानीय या 'अस्थायी शिक्षाविदों' के पदों को भरने के लिए शिक्षाविदों की सेवाएं उन देशों में अपने करियर जारी रखने के लिए ले सकते हैं जहां उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। संस्थागत गतिशीलता पारंपरिक छात्र अस्थिरता को कम कर सकती है लेकिन अलग-अलग शिक्षा आवश्यकताओं के साथ और अधिक छात्रों की सेवा कर सकती है। व्यापक खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम विशेष रूप से विकासशील दुनिया में शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाते हैं।

शाखा परिसर और क्षेत्रीय शिक्षा केंद्र सहित अपतटीय, सीमा पार और सीमाहीन कार्यक्रम, घर पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करते हैं।

मानकों को अनुकूल बनाने और शैक्षिक योग्यता को मान्यता देने से उच्च स्तरीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में आसानी होती है

छात्र को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, संस्थान जटिल संबंध बना सकते हैं और समझौते कर सकते हैं, उदाहरण के लिए दोहरा और संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, क्रेडिट स्थानान्तरण, कार्यनीतिक साझेदारी और भागीदारी। देश द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर मानकों और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को तेजी से सुसंगत बनाने का प्रयास करते हैं।

सामान्य डिग्री मानकों, गुणवत्ता आश्वासन, योग्यता मान्यता तंत्र और अकादमिक गतिशीलता विनिमय कार्यक्रमों को लागू करने से यूरोप और साझेदार देश 2010 में यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र (ईएचईए) स्थापित करने में सक्षम हो गए। यह 1999 में शुरू हुई बोलोग्ना प्रक्रिया की समाप्ति थी, जिसमें यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद और उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां, छात्र, कर्मचारी और नियोक्ता, और वर्तमान में 48 देश शामिल हैं। लिस्बन मान्यता सम्मेलन ईएचईए देशों के बीच शिक्षा योग्यता की मान्यता को नियंत्रित करता है और इसे 53 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अन्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों (एसियान) और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय सहित इन पहलुओं का अनुकरण करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उच्च शिक्षा पर तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों में उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने पर सहमति हुई। ऐसी पहलों को कार्य रूप देने के लिए, यूनेस्को ने 2019 में अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा योग्यता को मान्यता देने पर वैश्विक सम्मेलन का एक मसौदा तैयार किया है।

यूरोप में छात्र विनिमय कार्यक्रम दक्षिण-पूर्वी एशिया को सीख प्रदान करते हैं

क्षेत्रीय स्तर पर छात्र विनिमय कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने से अल्पकालिक छात्र गतिशीलता के अवसरों काफी बढ़ जाते हैं। 1987 में स्थापित इरास्मस कार्यक्रम के तहत, जिसका 2014 में इरास्मस+ के रूप में विस्तार हुआ था, में भाग लेने वाले छात्र दूसरे यूरोपीय देश में 3 से 12 महीने का अध्ययन करते हैं, और घरेलू संस्थान इस अवधि को उनकी डिग्री में शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की अंतर-सांस्कृतिक जागरूकता, कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाना और यूरोप में सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना है।

10 में से 9 प्रतिभागियों ने बताया कि इससे उनकी सोच में लचीलापन, खुलापन आया है और सहिष्णुता में वृद्धि हुई है। इस बात का प्रमाण है कि यूरोपीय छात्र की गतिशीलता से उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि हुई है। व्यापक डेटा आधारित मूल्यांकन, जो छात्र की सक्रियता के निर्धारक तत्वों को नियंत्रित करता है, समानता के संबंध में उनकी और अधिक सूक्ष्म तस्वीर प्रस्तुत करता है। 2015/16 में ब्रिटेन के कम कुशल माता-पिता के 2.8% छात्रों की तुलना में पेशेवर माता-पिता के 4.4% छात्रों ने इरास्मस+ में भाग लिया। समय के साथ यह अंतर बढ़ गया है।

2015 में, आसियान और यूरोपीय संघ ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा प्रणालियों को सुसंगत बनाने के लिए एसियान क्षेत्र (शेयर) कार्यक्रम में उच्च शिक्षा के लिए यूरोपीय संघ सहायता की शुरुआत की। शेयर ने अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों के परिणामस्वरूप गतिशीलता में बाधाओं की पहचान की है। यूरोप के विपरीत, एसियान देशों के बीच ऋण हस्तांतरण प्रणाली व्यापक रूप से भिन्न है।

पेशेवर शिक्षा को मान्यता देने से अंतरराष्ट्रीय श्रम सक्रियता बढ़ती है

पेशेवर शिक्षा को मान्यता देने से कुशल श्रम प्रवासन के लाभ बढ़ते हैं और सुविधाजनक बनते हैं। ओईसीडी देशों में, उच्च शिक्षा वाले एक-तिहाई से अधिक आप्रवासी एक-चौथाई मूल निवासियों की तुलना में अपनी नौकरियों के लिए अपेक्षित योग्यता से अधिक योग्यता रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेरोजगार आप्रवासी कॉलेज के स्नातकों की आय में कमी से वार्षिक 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व की हानि हो सकती है।

लेकिन प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मान्यता प्रणाली प्रायः अविकसित या खंडित होती है। प्रक्रिया जटिल, समय लगने वाली और महंगी होती है, इसलिए इसमें केवल कुछ अल्पसंख्यक ही आवेदन कर सकते हैं। प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, मूल्यांकन एजेंसियां, लाइसेंसिंग निकाय और अकादमिक संस्थान आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बना सकते हैं। सरकारें सुनिश्चित कर सकती हैं कि एजेंसियां निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करें और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करें। मान्यता के लिए कानूनी अधिकार स्थापित करने से डेनमार्क की तरह दाखिले और दक्षता में बढ़ोतरी हो सकती है। जर्मनी में 2012 के एक कानून ने विदेशी नागरिकों को निवास की स्थिति या नागरिकता के बावजूद मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

जब उनकी योग्यता को मान्यता नहीं मिलती है, तो कई प्रवासी गंतव्य देशों में रिक्तियों के बावजूद विनियमन व्यवसायों जैसे शिक्षण और नर्सिंग में कानूनी रूप से प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसमें आंशिक मान्यता मदद कर सकती है। आवेदकों को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, किसी अवधि के लिए पर्यवेक्षण के तहत काम करना होता है या कुछ कार्यों को करने से बचना होता है। यूरोपीय संघ व्यावसायिक योग्यता निर्देश यूरोपीय संघ में प्रेक्टिस करने के लिए अनुमोदित योग्यता वाले पेशेवरों के कुछ समूहों को अनुमति देता है। ऐसी स्वचालित मान्यता की स्थापना और रखरखाव के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिबद्धता और संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह के समझौते कम हैं।

शिक्षक के प्रवासन से लाभ और जोखिम दोनों होते हैं

शिक्षकों को कम वेतन, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, काम करने की खराब स्थितियों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पलायन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन शिक्षण राष्ट्रीय विनियमन आवश्यकताओं के अधीन प्रायः एक विनियमित पेशा है जो प्रवासियों को चुनौती देता है।

चूंकि शिक्षक योग्यता के नियम प्रायः भाषा कौशल से संबंधित होते हैं, अतः भाषाई और सांस्कृतिक समानता वाले देशों के बीच इनका व्यापक आदान-प्रदान होता है। उच्च वेतन से आकर्षित होकर मिस्र और अन्य अरब देशों के शिक्षकों ने खाड़ी सहयोग परिषद राज्यों में शिक्षा प्रणालियों को बढ़ाने में मदद की। अब देश अरबी को अंग्रेजी भाषा के साथ निर्देश की भाषा के रूप में बदल रहे हैं, और अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक मिस्र और जॉर्डन के शिक्षकों की जगह ले रहे हैं।

शिक्षक के प्रवासन से मूल देशों में शिक्षक की कमी पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम जमैका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से शिक्षकों की भर्ती करता है। बदले में, उसे अपने शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, दक्षिण अफ्रीका विदेश से, विशेषकर जिम्बाब्वे से शिक्षकों की भर्ती करता है। कैरीबियाई देशों ने हाल के दशकों में उच्च शिक्षक के प्रवासन का भी अनुभव किया है, जो ब्रिटेन और अमेरिकी के सक्रिय भर्ती प्रयासों के कारण हुआ है।

शिक्षकों को भेजने वाले देश का नुकसान काफी अधिक हो सकता है, चाहे शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा या समग्र शिक्षा प्रणाली में निवेश हो। इस समस्या ने अंतरराष्ट्रीय पहलों को प्रेरित किया है जो राष्ट्रमंडल शिक्षक भर्ती प्रोटोकॉल जैसे देशों के हितों को पहचानती हैं। हालांकि, गैर-बाध्यकारी आचरण संहिता के रूप में, प्रोटोकॉल प्रवास करने वाले व्यक्तिगत शिक्षकों पर प्रतिबंध नहीं लगाता।

अंतरराष्ट्रीय शिक्षक भर्ती एक आकर्षक व्यवसाय है जो वाणिज्यिक एजेंसियों को आकर्षित करता है। वे शायद ही कभी नियंत्रित होते हैं और उच्च नियुक्ति पर शुल्क ले सकते हैं या बहुत अधिक जानकारी प्रदान नहीं करते, जिससे भेजने वाले और प्राप्त करने देशों में पंजीकरण की भर्ती करने वालों के लिए आदेश जारी किया जा सकता है।

प्रतिभा पलायन गरीब देशों के लिए हानिकारक हो सकता है

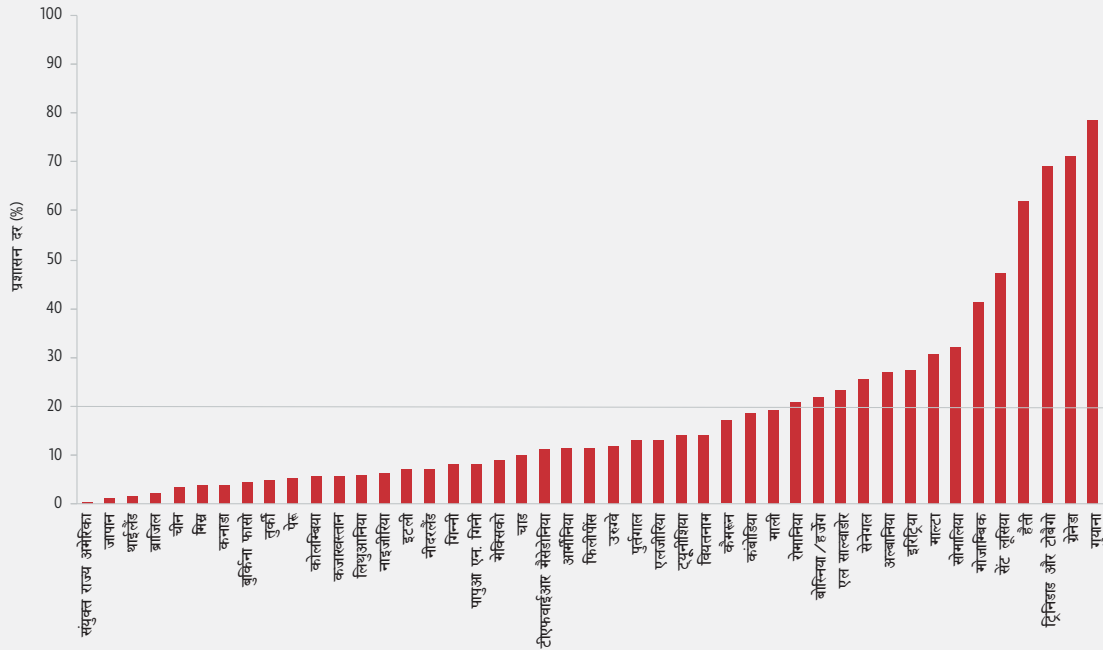
2010 में, 174 देशों में से एक-तिमाही से अधिक में अत्यधिक कुशलता की प्रवास दर 20% से ऊपर है, जिसमें यूरोप में कैरीबियन, अल्बानिया और माल्टा में ग्रेनेडा और गुयाना और उप-सहारा अफ्रीका में एरिट्रिया और सोमालिया शामिल हैं (चित्र 5)। कौशल की कमी को पूरा करने के लिए समृद्ध देश कुशल श्रमिकों के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

समृद्ध देश कुशल श्रमिकों के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे यह चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि प्रवासन से कौशल के नुकसान के कारण भेजने वाले देशों में विकास बाधित हो सकता है। हालांकि, पैसे घर भेजने के अलावा, कुशल प्रवासन की संभावनाएं भेजने वाले देश में शिक्षा में निवेश को भी बढ़ा सकती हैं। इस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि 14% की शुद्ध उच्च कुशल प्रवासन दर व्यक्ति द्वारा धन जमा करने का उच्चतम सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। मूल और गंतव्य देशों की विशेषताओं के साथ-साथ कम कुशल प्रवासन दरों का लेखा-जोखा रखने के बाद, प्रवासन संभावनाएं 174 देशों में से 90 में शुद्ध प्रतिभा लाभ उत्पन्न करती हैं, जबकि शुद्ध प्रभाव कम होता है।

कुछ देशों, विशेष रूप से एशिया में, अधिक नागरिकों को मूल्यवान कौशल के साथ लौटते हुए देखा जा रहा है। फिलीपींस ने वापस आने वालों के लिए नीतियां निर्धारित की हैं और घरेलू श्रम बाजारों को सुदृढ़ किया है ताकि प्रवास पर निर्णय आवश्यकता की बजाय पसंद के अनुसार लिया जा सके।

चित्र 5:

कई देशों में, पांच अत्यधिक कुशल लोगों में से एक से अधिक पलायन करते हैं
कुशल प्रवासन दर, चयनित देश, 2010



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig6_1
स्रोत: डस्टर और डॉक्यूयर (2018)।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए एक साधन है

दो समस्याएं प्रवासियों और शरणार्थियों के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) कार्यक्रमों को प्रभावित करती हैं।

सबसे पहले, कई बाधाएं टीवीईटी के माध्यम से कौशल विकास के लिए प्रवासी और शरणार्थी मांग को कम करती हैं। शुरुआती बेरोजगारी और अनिश्चित रोजगार प्रवासियों को दूसरे कार्य करने के लिए बाध्य करता है, जिसके कारण उनके अपने कौशल में निवेश करने की संभावना कम हो जाती है। बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों और शरणार्थियों के पास कार्य करने का वैध अधिकार नहीं होता, जैसा कि आयरलैंड और लिथुआनिया में है, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण में भागीदारी को हतोत्साहित किया जाता है। बहु प्रदाता और प्रवेश स्थल टीवीईटी प्रणाली में जाने को मुश्किल बना सकते हैं। फिर भी टीवीईटी प्रदाता और सार्वजनिक रोजगार सेवाएं प्रवासियों को काम अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक नियोक्ताओं के साथ जोड़ सकती हैं। जर्मनी में 'स्वागत सलाहकार' छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को नए प्रवासियों में से कुशल श्रमिकों की भर्ती का समर्थन करती हैं; 2016 में, 3,441 शरणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

दूसरा, शरणार्थियों की पूर्व शिक्षा को मान्यता न देने से उन्हें सभ्य कार्य प्राप्त करने या आगे शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपनी योग्यता से समझौता करना पड़ता है। प्रवासियों और शरणार्थियों द्वारा अपने साथ शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र ले जाने की संभावना नहीं होती, और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों में अधिक परिवर्तनशीलता के कारण टीवीईटी डिग्री को अकादमिक डिग्री की तुलना में ले जाना कम आसान होता है। 2013 में, नॉर्वे ने सत्यापन दस्तावेजीकरण के बिना व्यक्तियों के लिए पहचान प्रक्रिया शुरू की। आधे से अधिक शरणार्थियों, जिनके कौशल 2013 में पहचाने गए थे, को या तो संबंधित नौकरी मिल गई या उन्होंने आगे शिक्षा में दाखिला ले लिया। अंतर सरकारी सहयोग से पहचान, सत्यापन और मान्यता भी सुगम हो सकती है। सीरियाई अरब गणराज्य और मिस्र, इराक, जॉर्डन और लेबनान के बीच राष्ट्रीय मान्यता समझौते मौजूद हैं।

मीना (11 वर्ष, ग्रेड 5, बोएउंग काचंग द्वीप,
कोह कोंग प्रांत, कंबोडिया)

आभार: शल्लेन्द्र यशवंत / बच्चे बचाओ



एसडीजी 4 में निगरानी प्रगति

शिक्षा पर एसडीजी 4 का समर्थन करने वाला निगरानी ढांचा महत्वाकांक्षी है, भले ही शिक्षा विकास में सबसे कठिन प्रश्नों को छोड़ दिया जाए। इसकी एक प्रमुख रचनात्मक भूमिका है, जो ध्यान दिए जाने वाले गंभीर मुद्दों पर विचार करती है और उसे किस देश की निगरानी में निवेश करना चाहिए। साथ ही, देशों में डेटा तुलनात्मकता को मजबूत करने के लिए संकेतकों, मानकों और उपकरणों को विकसित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके

“

2018 में पहली बार चार संकेतकों की सूचना दी जाएगी, जिससे एसडीजी संकेतकों की कुल संख्या जिनकी संख्या 43 में से 33 हो जाएगी।

लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, देशों, निधि प्रदाताओं और विशेषज्ञों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है।

एसडीजी 4 के लिए 11 वैश्विक संकेतक हैं। यूनेस्को सांख्यिकीय संस्थान (यूआईएस) आठ संकेतकों के लिए एकमात्र संरक्षक एजेंसी है तथा यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर संकेतक के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के साथ सहयोग करता है। प्रारंभिक बचपन के विकास पर एक संकेतक के लिए संरक्षक एजेंसी यूनिसेफ है और छात्रवृत्ति की सहायता के लिए ओईसीडी है। अतिरिक्त 32 विषयगत संकेतकों से एसडीजी 4 निगरानी ढांचे में 43 संकेतक हो गए हैं।

”

यूआईएस एसडीजी 4 - शिक्षा 2030 (टीसीजी) के लिए संकेतकों पर तकनीकी सहयोग समूह के माध्यम से सदस्य राज्यों और एजेंसियों के साथ वैश्विक और विषयगत संकेतकों में विकास का समन्वय करता है, जो इसे यूनेस्को के साथ आयोजित करता है। 2018 में पहली बार चार संकेतकों की सूचना दी जाएगी (वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों में भागीदारी, व्यापक यौन शिक्षा, स्कूल आधारित हिंसा और स्कूलों पर हमले), जिनकी संख्या 43 संकेतकों में से कुल 33 हो जाएगी। कार्य जारी है या यह निर्देश की भाषा, संसाधनों का वितरण और शिक्षक पेशेवर विकास पर शुरू होने वाला है।

यूआईएस द्वारा आयोजित शिक्षा निगरानी के लिए वैश्विक गठबंधन, अधिक जटिल शिक्षण परिणाम संकेतकों पर काम करता है, जो मुख्य रूप से पढ़ने और गणित, वयस्क साक्षरता और डिजिटल साक्षरता में न्यूनतम दक्षता पर कार्य करते हैं। यूआईएस पढ़ने और गणित की दक्षता में लिकिंग और बेंचमार्किंग के लिए तीन वैकल्पिक कार्यनीतियों पर कार्य कर रहा है। सबसे पहले, यह एक पहल का समर्थन करता है जो चयनित लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में छात्रों को सर्वेक्षण में अधिक बेहतर तुलना करने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन उपलब्ध कराएगा। दूसरा, इसने विभिन्न अनुमानों की सामग्री की रूपरेखा बनाई है, जिसके माध्यम से विशेषज्ञ रिपोर्टिंग पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षणों में वस्तुओं का कठिनाई स्तर निर्दिष्ट करेंगे। तीसरा, यह सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके दक्षता के पैमाने को जोड़ने का प्रयास जारी रखता है।

2000 - 2015 तक की समस्त अवधि के लिए शिक्षा का जायजा लेना

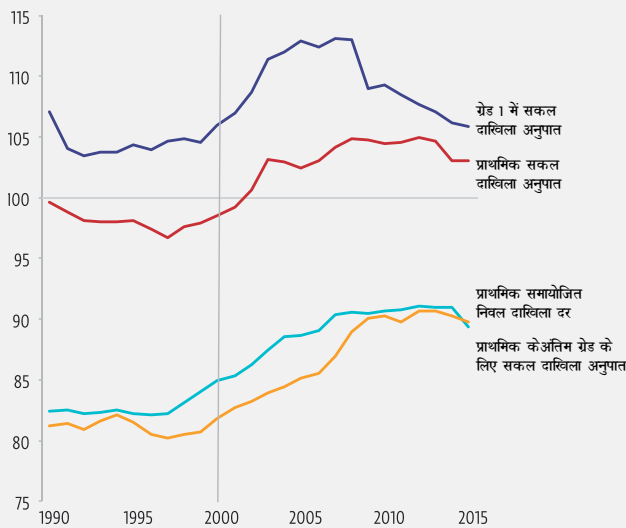
2015 सभी के लिए शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (ईएफए जीएमआर) ने ईएफए रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जो काफी हद तक 2012 के आंकड़ों पर आधारित था। 2015 के आंकड़ों के आधार पर एक अद्यतन मूल्यांकन किया गया है। यह निष्कर्ष को नहीं बदलता - ईएफए की अवधि के दौरान हालांकि प्रगति महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंततः यह लक्ष्य तक पहुंचने से काफी कम थी - लेकिन 2030 को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई है।

दो प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं। प्राथमिक समापन पर ईएफए लक्ष्य 2 के संबंध में, लगभग 1997 तक स्थिर भागीदारी और समापन दर के बाद, प्राथमिक सकल दाखिला अनुपात, शुद्ध दाखिला दर और सकल दाखिला अनुपात प्राथमिक ग्रेड में 2008 में बढ़ गई, और फिर रुक गई (चित्र 6क)। इसके विपरीत, लैंगिक समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में, हालांकि 2005 तक दाखिला में समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी 1990 और 2000 के दशक में प्रगति जारी रही, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 2009 में समानता हो गई और 2015 में युवा साक्षरता में लगभग समानता प्राप्त कर ली गई थी। वयस्क साक्षरता में असमानता बनी हुई है, 63% अशिक्षित महिलाएं हैं, और उच्च शिक्षा में इसके उलट हुआ है, पुरुषों के अब भाग लेने की संभावना कम है (चित्र 6ख)।

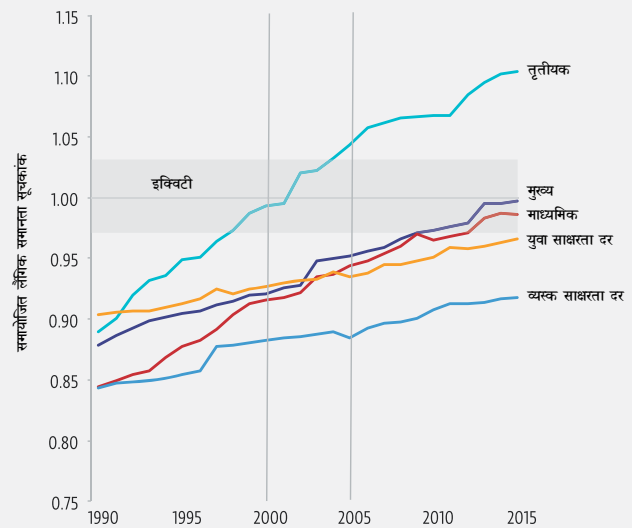
चित्र 6:

2000 से 2015 के बीच, दुनिया लैंगिक समानता की ओर तेजी से बढ़ी लेकिन सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पूर्णता की ओर नहीं

क. चयनित प्राथमिक शिक्षा उपलब्धता, भागीदारी और समापन संकेतक, 1990-2015



ख. चयनित सकल दाखिला अनुपात और साक्षरता दर, 1990-2015 के लिए समायोजित लैंगिक समानता सूचकांक



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig7_1

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

प्रवासियों और विस्थापित आबादी की शिक्षा की स्थिति की निगरानी करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

एसडीजी निगरानी ढांचे में नुकसान से जुड़े विभिन्न मानकों द्वारा अलग-अलग संकेतकों पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, आप्रवासियों और शरणार्थियों की शिक्षा की स्थिति पर व्यवस्थित डेटा स्पष्ट नहीं है। विश्व बैंक के माइक्रोडेटा कैटलॉग में, लगभग 2,500 घरेलू सर्वेक्षणों में से 2,000 से अधिक में शिक्षा पर जानकारी शामिल है, लेकिन उनमें से सात में से केवल एक में प्रवासन शामिल है, और इसके भी बहुत छोटे भाग में विस्थापन शामिल है।

“

प्रवासी परिवार घूमते रहते हैं और घरेलू सर्वेक्षण के लिए गणना करने वालों द्वारा दौरा करने पर उनके घर पर उपस्थित होने की संभावना कम होती है या भाषा बाधाओं या कानूनी समस्या के कारण उनके साथ बातचीत करना मुश्किल होता है।

प्रवासी परिवार घूमते रहते हैं और घरेलू सर्वेक्षण के लिए गणना करने वालों द्वारा दौरा करने पर उनके घर पर उपस्थित होने की संभावना कम होती है या भाषा बाधाओं या कानूनी समस्या के कारण उनके साथ बातचीत करना मुश्किल होता है। और चूंकि पलायन की स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए नमूने का कोई फ्रेम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह विशेष रूप से विस्थापित लोगों को प्रभावित करता है: शरणार्थी शिविरों में डेटा अधिक व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है, लेकिन इन शिविरों में 40% से कम शरणार्थी रहते हैं और आईडीपी शिविरों में तो इससे भी कम रहते हैं।

”

मानक, सामान्य प्रयोजन सर्वेक्षण में आप्रवासियों और शरणार्थियों को सुनिश्चित रूप से शामिल करने से नमूना लेने और डेटा संग्रह करने जैसे मुद्दों को हमेशा हल नहीं किया जा सकता है। मानक सर्वेक्षण पलायन की घटना के उतार-चढ़ाव को दर्ज नहीं करते हैं और समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कम हो सकते हैं। प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले समुदायों के साथ-साथ गैर-यादृच्छिक नमूना लेने का उपयोग करके डेटा का तुरंत संग्रह करने से जुड़े शोध-केंद्रित सर्वेक्षण सहित लचीला दृष्टिकोण अधिक प्रभावी हो सकता है। अंत में, सर्वेक्षण में शिक्षा-प्रवास गतिशीलता या मूल देश में प्राप्त शिक्षा योग्यता दर्ज नहीं की जाती।

मार्च 2016 में, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने शरणार्थी और आईडीपी सांख्यिकी पर एक विशेषज्ञ समूह का आयोजन किया। इसमें 40 सदस्य देशों और कम से कम 15 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इस समूह ने डेटा संग्रह में सुधार करने के लिए सिफारिशें कीं। यूनेस्को और यूएनएचसीआर शरणार्थी शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जो एक निःशुल्क, मुक्त स्रोत, वेब-आधारित उपकरण है, को विकसित कर रहे हैं ताकि देशों को शरणार्थी शिक्षा डेटा एकत्रित, संकलित, विश्लेषण और रिपोर्ट करने में सहायता मिल सके।



लक्ष्य 4.1

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

2010 और 2014 के बीच पैदा हुए बच्चों को एसडीजी पीढ़ी माना जा सकता है। 2015 में सबसे पुरानी उम्र 5 तक पहुंच गई और कई देशों में, 2015/16 - एसडीजी अवधि (2015-2030) की शुरुआत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने की उम्मीद थी। 2030 में सबसे कम उम्र 16 हो जाएगी, जो संभावित रूप से समय पर निम्न माध्यमिक शिक्षा पूरा करने

“

2030 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सभी बच्चों को 2018 तक प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेना आवश्यक है।

”

की सबसे कम उम्र है। एसडीजी पीढ़ी के लिए 2030 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मौजूदा समूह को समय पर प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेना आवश्यक है। 2016 में पहले प्राथमिक ग्रेड में वैश्विक समायोजित शुद्ध दाखिला दर 86% थी।

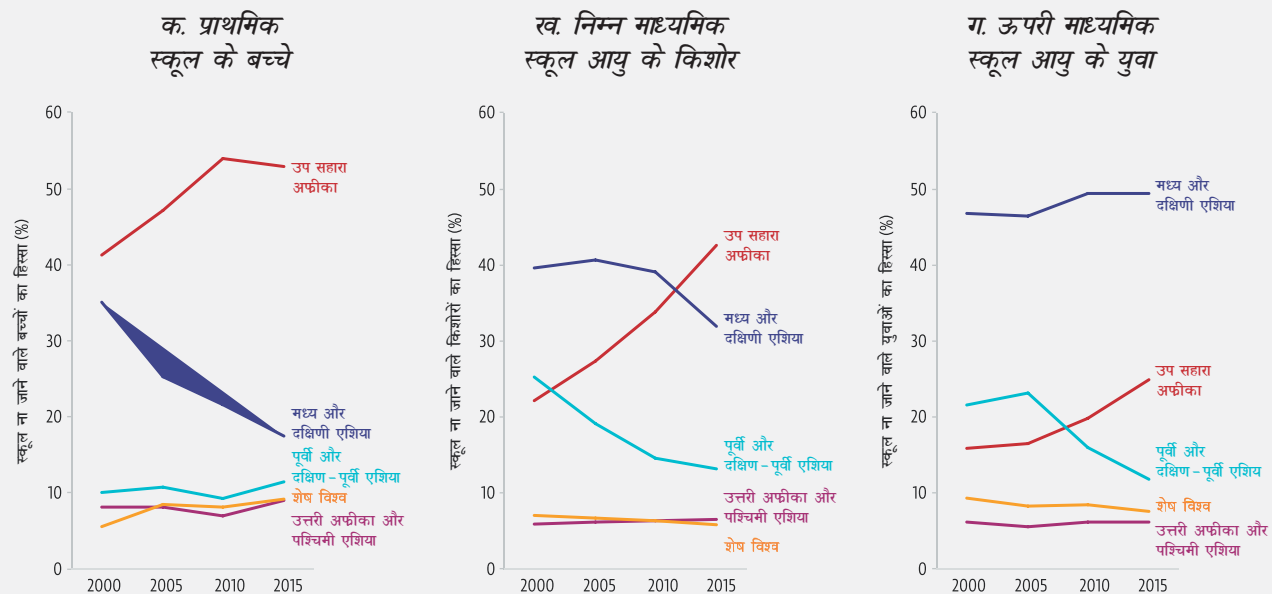
प्राथमिक स्कूल की आयु के लगभग 63 मिलियन बच्चे, या 9%, 2016 में स्कूल नहीं जाते थे, जबकि निम्न माध्यमिक स्कूल आयु (16%) के 61 मिलियन किशोर और ऊपरी माध्यमिक स्कूल की आयु (36%) के 139 मिलियन युवा स्कूल नहीं जाते थे। प्राथमिक दर 2008 के बाद से लगभग समान बनी हुई है। उप-सहारा अफ्रीका में प्राथमिक स्कूल की उम्र को छोड़कर स्कूल न जाने वालों की दर बढ़ रही है, अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से

पश्चिमी एशिया (चित्र 7) में संघर्ष के कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है।

प्रत्येक 5 वर्ष में ग्रेड 4 छात्रों का आकलन करने वाले अंतरराष्ट्रीय पठन साक्षरता अध्ययन में प्रगति नामक एक सर्वेक्षण अध्ययन निष्कर्षों पर वैश्विक संकेतक का मुख्य नया क्रॉस राष्ट्रीय सर्वेक्षण डेटा उपलब्ध कराता है। ईरान के इस्लामिक गणराज्य में, निम्न बैचमार्क को पूरा करने वाला प्रतिशत वर्ष 2001 में 56% से बढ़कर 2016 में 65% हो गया अर्थात् प्रति

चित्र 7:

उप-सहारा अफ्रीका में स्कूल न जाने वाले बच्चों की आबादी का वैश्विक हिस्सा बढ़ रहा है क्षेत्र द्वारा स्कूल न जाने वाली आबादी का वितरण, 2000-2015



जीईएम स्टार्ट लिंक: http://bit.ly/fig8_2

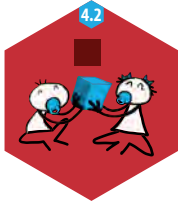
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

वर्ष एक प्रतिशत अंक से कम। कुछ देशों, जिनमें मोरक्को और ओमान शामिल हैं, ने 2030 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दर में सुधार किया है; दूसरे देशों, उदाहरण के लिए अजेरबैजान, सउदी अरब और दक्षिण अफ्रीका में न्यूनतम दक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों के शेर में वृद्धि नहीं हुई है, जिसका अर्थ है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा।

शिक्षा 2030 एजेंडा के लिए एक नई समापन दर अनुमान

2013-2017 के अनुसार घरेलू सर्वेक्षण डेटा के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा के लिए समापन दर 85, माध्यमिक शिक्षा के लिए 73 और ऊपरी माध्यमिक शिक्षा के लिए 49 है। तथापि, परिवार सर्वेक्षण और जनगणना आंकड़ों के लिए कम समय होगा और बहु स्रोत सटीक सूचना प्रदान नहीं करेंगे।

स्वास्थ्य निगरानी समुदाय के उदाहरण के बाद, जीईएम रिपोर्ट टीम ने समापन दरों का अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। पुराने समूहों की समापन दरों का अनुमान लगाने के लिए पिछली दरें देश में दर विस्तार के लिए दीर्घावधि दृष्टिकोण उपलब्ध करा सकती हैं। संकेतक के वर्तमान स्तर का अल्पावधि बाहरी गणना के अधिकांश वर्तमान डेटा का अनुमान लगाया जा सकता है।



शुरुआती बचपन

लक्ष्य 4.2

शुरुआती बचपन शिक्षा और देखभाल ज्ञान-संबंधी और सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह विशेष रूप से आपदा संकट में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

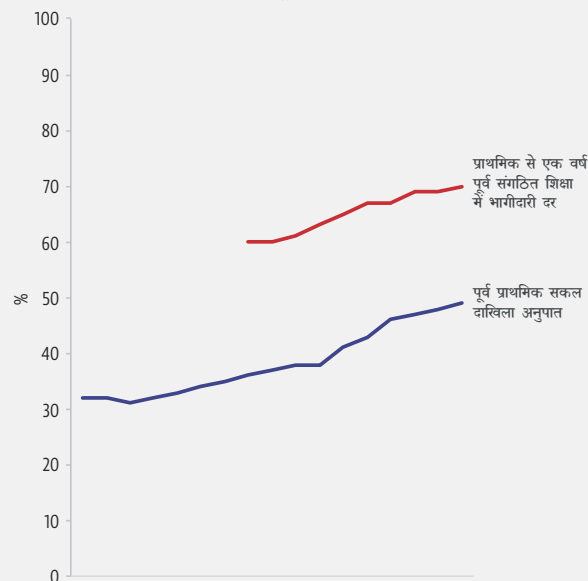
सरकारी प्राथमिक दाखिला आयु से पहले एक वर्ष अध्ययन में भाग लेने के वैश्विक संकेतक न्यून आय वाले देशों में लगभग 43 हैं जबकि उच्च आय वाले देशों में 90% हैं, और विश्व का औसत 70% है, जो धीमा किंतु धीरे-धीरे लगातार बढ़ता रुझान है। इसके विपरीत, प्राथमिक-पूर्व सकल नामांकन अनुपात में शिक्षा के स्तर को परिभाषित किया गया है, जो कुछ देशों में एक वर्ष से कम समय तक रहता है और वर्ष 2016 में यह अधिकतम चार देशों में 49% पहुंचा था (चित्र 8)।

प्रारंभिक बचपन के विकास पर अन्य वैश्विक संकेतक यूनिसेफ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास सूचकांक (ईसीडीआई) पर आधारित है, जिसकी गणना मुख्य रूप से यूनिसेफ बहु संकेतक समूह सर्वेक्षण (एमआईसीएस) डेटा का उपयोग करके की जाती है। हालांकि यूनिसेफ कमियों को दूर करने के लिए ईसीडीआई पद्धति की समीक्षा कर रहा है और इस प्रक्रिया के 2018 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। पांच वर्षों में एमआईसीएस के दो दौर में भाग लेने वाले देशों के नतीजे बताते हैं कि साक्षरता-अंक ज्ञान क्षेत्र में 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों का हिस्सा प्रति वर्ष एक प्रतिशत से भी कम अंक से बढ़ता है।

हालांकि, स्कूल के लिए 'तैयार' होना और 'विकास के मार्ग पर' होना भ्रामक अवधारणाएं हैं, जिन्हें दुनिया भर में अलग-अलग देखा जाता है। देशों को उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले उपायों का उपयोग करने के लिए और अधिक विवेकाधिकार की आवश्यकता हो सकती है जो संस्थागत ढांचों और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकूल हों।

चित्र 8:

दस में से सात बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा में दाखिला लेने से पहले प्रि-स्कूल में दाखिला लिया था
सरकारी प्राथमिक दाखिला आयु से पूर्व एक वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की भागीदारी दर तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्व सकल दाखिला अनुपात, 2000-2016

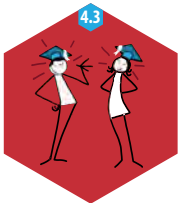


जीईएम स्टार्टलिंग: http://bit.ly/fig9_2

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

फिर भी स्कूल की तैयारी की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय प्रणाली कम ही देखने को मिलती है। आमतौर पर, देशों के पास प्रदाताओं (जैसे भारत की 2013 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति) में कर्मचारियों, प्रशिक्षण, सुविधाओं और पाठ्यक्रम मानकों की निगरानी करने या कार्यक्रम प्रभाव का मूल्यांकन करने (उदाहरण के लिए अमेरिकी हेड स्टार्ट प्री-स्कूल कार्यक्रम की राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली घटक) के लिए राष्ट्रीय ढांचे और प्रक्रियाएं होती हैं। बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए विश्व बैंक प्रणाली दृष्टिकोण के शुरुआती बाल्यावस्था के विकास मांड्यूल में, 37 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से केवल 8 ने सभी चार क्षेत्रों (संज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक विकास) में बच्चों पर डेटा एकत्र किया है।

दक्षिण अफ्रीका के 2014 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में छह प्रारंभिक शिक्षा और विकास क्षेत्रों के आधार पर अनौपचारिक, विश्लेषणात्मक और चल रहे मूल्यांकन पर विचार किया गया है, जिसमें अंक या प्रतिशत शामिल नहीं हैं बल्कि प्राथमिक स्वागत ग्रेड के लिए तैयारी रिकॉर्ड की गई है। 2014 से, मैसिडोनिया के पूर्व युगोस्लाव गणराज्य द्वारा ईसीईसी केंद्रों में दाखिल सभी बच्चों के बाल विकास पोर्टफोलियो रखा जा रहा है।



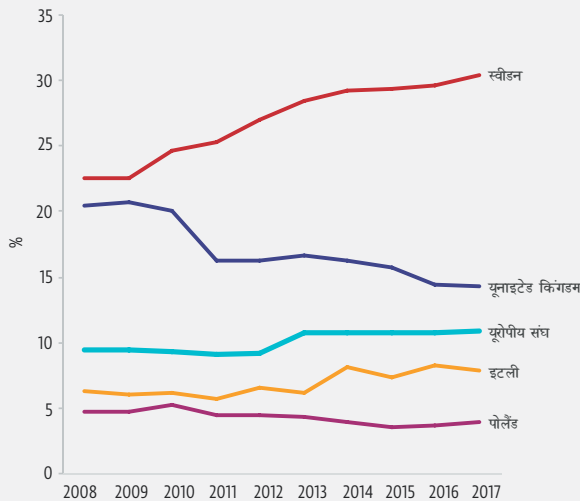
लक्ष्य 4.3

तकनीकी, व्यावसायिक, तृतीयक और वयस्क शिक्षा

सभी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अवसरों, चाहे काम से संबंधित हों अथवा नहीं, का लाभ उठाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा भागीदारी पर वैश्विक संकेतकों में सुधार किया गया है। विविधता और प्रदाताओं की संख्या मजदूर सर्वेक्षण को स्रोत के रूप में प्रशासनिक डेटा के अनुरूप बनाती है, फिर भी देशों के बीच इन सर्वेक्षणों में प्रश्न काफी भिन्न होते हैं, और कुछ प्रश्न नई संकेतक परिभाषा के अनुरूप होते हैं। देशों की संख्या का विस्तार करने के लिए प्रश्नों का मानकीकरण, तुलनात्मक डेटा के अनुसार रखना आसान नहीं होगा।

चित्र 9:

यूरोप में वयस्क शिक्षा में भागीदारी स्थिर बनी हुई है, लेकिन हर देश के रुझान अलग-अलग हैं
यूरोपीय संघ और चयनित देशों में पिछले चार सप्ताह के दौरान शिक्षा और प्रशिक्षण में वयस्क भागीदारी, 2008-2017



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig10_1
स्रोत: यूरोस्टैट (2018)।

यूरोपीय संघ मजदूर सर्वेक्षण में पिछले 4 सप्ताह (बनाम संकेतक के 12 महीने) में औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भागीदारी दर औसतन 11% पर स्थिर रहती है, हालांकि रुझान हर देश के अनुसार भिन्न होते हैं (चित्र 9)। मिस्र, जॉर्डन और ट्यूनीशिया में एकीकृत श्रम बाजार सर्वेक्षण नियोजित लोगों, आजीवन भागीदारी और कार्य से संबंधित टीवीईटी तक ही सीमित हैं। वे तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों के बीच 4% तक वार्षिक प्रशिक्षण भागीदारी दर का सुझाव देते हैं।

2016 में उच्च शिक्षा सकल दाखिला अनुपात 37% तक पहुंच गया, लेकिन उच्च शिक्षा की कुल लागत में निजी व्यय का हिस्सा बढ़ रहा है। छात्र ऋण, अनुदान, सब्सिडी और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता का अभिप्राय है कि यूरोप में आमतौर

“ श्रमिक बल सर्वेक्षण विविधता और प्रदायकों की संख्या को देखते हुए वयस्क शिक्षा का प्रशासनिक अनुमान लगाने के लिए एक विशिष्ट स्रोत है ”

पर उच्च शिक्षा सबसे सस्ती है और उप-सहारा अफ्रीका में महंगी है, जहां इसकी लागत अधिकांश देशों में औसत राष्ट्रीय आय के 60% से अधिक है और गिनी और युगांडा में लगभग 300% है।

अधिकांश शिक्षा प्रणालियों का लक्ष्य वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने का प्रभाव काफी भिन्न होता है। विश्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, सबसे गरीब समूहों को, सबसे अमीर समूहों की तुलना में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संभावना कम थी। विभिन्न दृष्टिकोणों सहित व्यापक नीति पैकेज, जैसे कि कोलम्बिया और वियतनाम में हैं, अकेले छात्रवृत्ति की तुलना में अधिक सफल हो सकते हैं।



लक्ष्य 4.4

कार्य कौशल

आईसीटी और डिजिटल साक्षरता पर वैश्विक और विषयगत संकेतकों का उद्देश्य साक्षरता और संख्या संबंधी ज्ञान से अधिक कौशल अर्जित करना है जो कार्य प्रधान इस दुनिया के लिए सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। संकेतकों की मांग है कि सरकारें स्कूलों के बाहर कौशल अर्जित करने पर विचार करें।

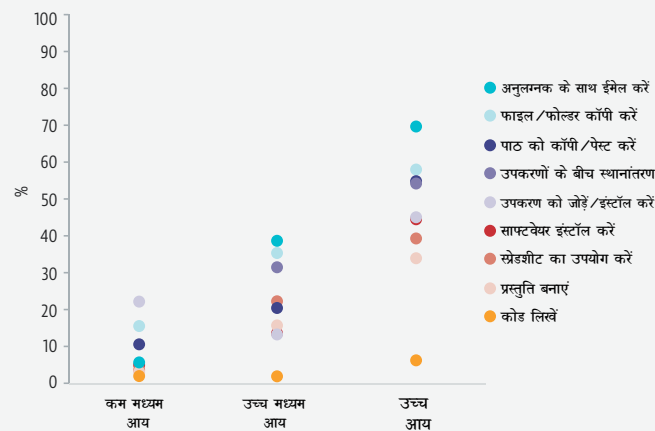
आईसीटी कौशल वाले युवाओं और वयस्कों के वैश्विक संकेतक, पिछले तीन महीनों में घरेलू सर्वेक्षण द्वारा स्वयं रिपोर्टिंग आधार पर चयनित गतिविधियों के अनुसार लिए गए हैं। नवीनतम आईटीयू डेटा से पता चलता है कि ईमेल पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाना और उसे संलग्न करना ही एकमात्र कौशल था जिसे सामान्य मध्यम आय वाले देशों में तीन लोगों में से एक द्वारा प्रयोग किया गया था; उच्च आय वाले देशों में संबंधित दरें 58% और 70% थीं (चित्र 10)। बाद में प्रोग्रामिंग भी मामूली गतिविधि बन गई।

डिजिटल साक्षरता कौशल पर विषयगत संकेतक, आईसीटी उपकरणों का काफी दक्षता से उपयोग करते हैं। डिजिटल साक्षरता के लिए एक नए वैश्विक ढांचे में यूरोपीय आयोग के डिगकॉम्प ढांचे का विस्तार किया गया है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सेटिंग्स को दर्शाने वाले जटिल सेट को शामिल किया गया है, उदाहरण के लिए कुशल किसानों को मोबाइल फोन सेवा का उपयोग करके खेती और व्यापार निर्णय लेने होते हैं, स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से उत्पादों को खरीदने और बेचने या लैपटॉप से जुड़े नमी सेंसर का उपयोग करके डेटा द्वारा संचालित सिंचाई प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है।

“ उच्च आय वाले देशों में दस में से तीन ई-मेल के साथ फाइलें संलग्न करना नहीं जानते ”

चित्र 10:

आईसीटी कौशल समान रूप से नहीं दिया जाता देश के आय समूह के आधार पर पिछले तीन महीनों में कंप्यूटर से संबंधित गतिविधि करने वाले वयस्कों का प्रतिशत, 2014-2017



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig11_1

नोट: मध्यम आय वाले देशों के लिए मेडियन कम देशों (5 निम्न मध्यम आय, 15 ऊपरी मध्यम आय) पर आधारित होती है और इनकी व्याख्या सावधानी के साथ की जानी चाहिए। स्रोत: आईटीयू डेटाबेस।

इन क्षमताओं को मापने के लिए सस्ते उपकरण की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। डिजिटल साक्षरता आकलन उद्देश्य, लक्ष्य समूह, वस्तुओं, वितरण, लागत और जिम्मेदार प्राधिकारी के अनुसार भिन्न होता है। एक फ्रांसीसी उदाहरण के अनुसार, नागरिकों को डिजिटल कौशल मूल्यांकन, शक्तियों और कमियों का विश्लेषण करने के लिए निःशुल्क पहुंच प्रदान करना तथा शिक्षा संसाधनों के लिए सिफारिशें करना भावी तरीका हो सकता है।

उद्यमशीलता क्षमताओं का आकलन करना लक्ष्य 4.4 फोकस है, जिसके लिए कोई संकेतक नहीं बनाया गया है, जिसे इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दृढ़ता और स्व-नियंत्रण सहित सामाजिक और भावनात्मक कौशल, उद्यमशीलता कौशल की विस्तृत श्रृंखला में से एक हैं, लेकिन उन्हें मापने के लिए संस्कृतियों में विविधता की व्याख्या करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ओईसीडी 10- और 15-वर्ष के बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक कौशल पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की रूपरेखा बना रहा है।



लक्ष्य 4.5

समानता

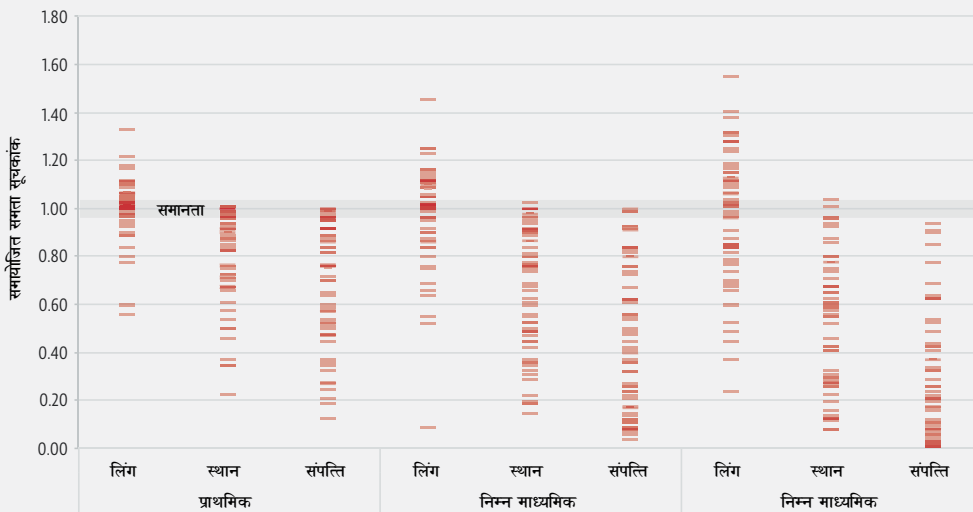
औसतन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में विश्व स्तर पर दाखिले में लिंग समानता होती है। हालांकि, अलग-अलग देश में औसत अंकों में हमेशा असमानताएं होती हैं। 2016 में, 54% देशों ने निम्न माध्यमिक शिक्षा नामांकन में और 22% देशों ने ऊपरी माध्यमिक में समानता प्राप्त की थी। इसके अलावा, समानता प्राप्त करने वाले सभी देश इसे बनाए नहीं रखते हैं।

स्थान और संपत्ति की दृष्टि से समापन दरों में काफी असमानता होती है। ग्रामीण छात्रों को आमतौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों (चित्र 11) में ऊपरी माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अपने शहरी सहयोगियों की तुलना में आधे मौके होते हैं।

कम तुलनात्मकता स्थान-आधारित असमानता का आकलन करती है: कृषि, जनसंख्या आकार, आबादी घनत्व, विशिष्ट प्रकृति का राष्ट्रीय मानदंड या उसके किसी भी संयोजन में लगे मजदूरों का हिस्सा पूरे देश में 'शहरी' और 'ग्रामीण' स्थान वर्गीकरण निर्धारित कर सकता है।

चित्र 11:

कई देश स्कूली शिक्षा के पूरा होने, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में स्थान और धन समानता प्राप्त नहीं कर पाते
शिक्षा स्तर द्वारा समापन दर का लिंग, स्थान और धन समायोजित समानता सूचकांक 2014-2017



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig12_1

स्रोत: घरेलू सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए यूआईएस और जीईएम रिपोर्ट टीम की गणना।

“ ग्रामीण छात्रों को आमतौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों (चित्र 11) में ऊपरी माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अपने शहरी सहयोगियों की तुलना में आधे मौके होते हैं। ”

एसडीजी की निगरानी के समर्थन में, क्विटो में 2016 संयुक्त राष्ट्र पर्यावास III सम्मेलन के बाद, वैश्विक स्तर पर, शहरों और बस्तियों की जन-आधारित परिभाषा 2019 में अनुमोदन के लिए विकसित की जा रही है। यह दूरस्थ संवेदी डेटा और जनगणना जानकारी सहित प्रशासनिक वर्गीकरण की तुलना करता है। यह दिलचस्प है कि राष्ट्रीय परिभाषाएं दर्शाती हैं कि अफ्रीका और एशिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि 2018 के अनुमान दर्शाते हैं कि 80% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। ग्रामीण शिक्षा परिणामों के वर्तमान अनुमानों में कई स्थानीय लोग शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में शहरी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का मुखौटा ओढ़े हुए हैं।



लक्ष्य 4.6

साक्षरता और संख्या ज्ञान

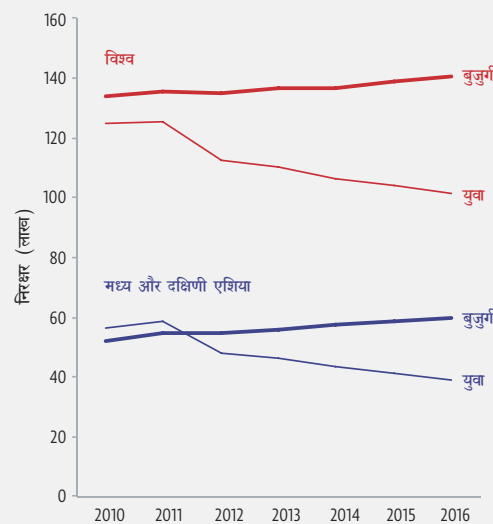
2016 में विश्व साक्षरता दर 86% तक पहुंच गई, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में यह न्यूनतम 65% तक है। हाल के वर्षों में युवा साक्षरता तेजी के साथ बढ़ी है जिससे 15 से 24 वर्ष के अशिक्षित युवाओं की कुल संख्या में काफी कमी आई है, ऐसा मुख्य रूप से एशिया में हुआ है। लेकिन 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है; अशिक्षित युवाओं (चित्र 12) की तुलना में अब अशिक्षित बुजुर्ग लगभग 40% अधिक हैं।

अलग रहने वाले अशिक्षित व्यक्ति, जो घरों में रहते हैं जहां कोई भी सदस्य पढ़ नहीं सकता, उनके एक या अधिक साक्षर परिवार वाले सदस्यों के साथ रहने वालों की तुलना में श्रम बाजार और जीवन के परिणामों की गुणवत्ता काफी खराब होती है।

ग्रामीण निवासियों में अलग रहने वालों में निरक्षरता अधिक होती है। अमीर देशों में, अलग रहने वाले अशिक्षित, शिक्षितों के साथ रहने वाले अशिक्षितों की तुलना में अधिक अशिक्षित होते हैं, जबकि गरीब देशों में यह रुझान उलटा है। इसका एक स्पष्टीकरण यह है कि गरीब देशों में सबसे अशिक्षित परिवार की अनेक पीढ़ियों के बीच रहते हैं और इसलिए उनके युवा, अधिक शिक्षित परिवार के सदस्यों के साथ रहने की संभावना अधिक होती है।

तदनुसार, साक्षर कार्यकलाप में अमीर देशों में एक या दो व्यक्तियों वाले घरों में रहने वाले पुराने बूढ़े लोगों पर और गरीब देशों में प्रायः ग्रामीण इलाकों में सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले युवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

चित्र 12: अशिक्षित युवाओं की तुलना में अशिक्षित बुजुर्ग लगभग 40% अधिक हैं अशिक्षित युवाओं और बुजुर्गों की संख्या, 2010-2016



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig13_1
 स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।



लक्ष्य 4.7

सतत् विकास और वैश्विक नागरिकता

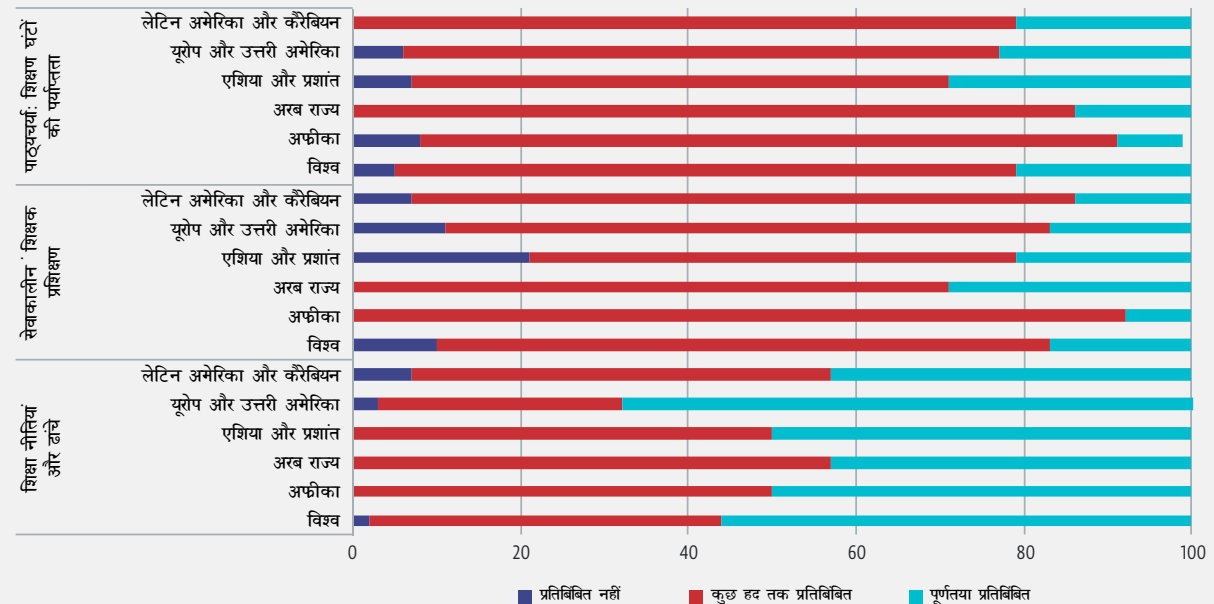
वैश्विक संकेतक पर रिपोर्टिंग 83 देशों पर आधारित है, जिन्होंने मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग और शांति शिक्षा के लिए शिक्षा से संबंधित 1974 यूनेस्को सिफारिश के कार्यान्वयन पर आयोजित छोटे परामर्श में भाग लिया था। 80% से अधिक देशों ने छात्र मूल्यांकन में सिफारिश के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करने, और उन्हें लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शामिल करने की सूचना दी। हालांकि, केवल 17% देशों ने सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया गया है (चित्र 13)।

आईईए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और नागरिकता अध्ययन 2016 में 24 अत्यधिक उच्च आय वाले देशों में ग्रेड 8 के छात्रों के ज्ञान, समझ, दृष्टिकोण, धारणाओं और गतिविधियों का विश्लेषण किया। लगभग 35% छात्रों ने चार स्तरों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन की प्रक्रियाओं और उन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनी और संस्थागत प्रणालियों के बीच संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि 13% ने निम्नतम स्तर या उससे कम अंक प्राप्त किए।

ग्यारह देशों ने 2009 और 2016 के सर्वेक्षण दौर के दौरान अपने अंकों में काफी सुधार किया, और किसी में भी अधिक गिरावट नहीं देखी गई। प्रतिभागियों द्वारा जातीय/नस्लीय समूहों के प्रति समान अधिकारों का समर्थन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में भी सुधार हुआ। नागरिकों और राजनीतिक मामलों में अधिक रुचि रखने वाली महिलाओं, छात्रों और नागरिक ज्ञान का उच्च स्तर रखने वाले लोगों ने अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्तिगत प्रभावित करने वाले लोग स्कूल प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, जैसे कि छात्र-शिक्षक संबंध, नागरिक शिक्षा और स्कूलों एवं कक्षा चर्चाओं में खुलेपन की गुणवत्ता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से लगातार जुड़े रहे।

चित्र 13:

केवल 17% देशों में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया गया है। उन देशों का प्रतिशत जिन्होंने 1974 की यूनेस्को सिफारिश के सिद्धांतों को अपनी शिक्षा नीति, शिक्षक शिक्षा और पाठ्यक्रम में शामिल किया है, 2012-2016



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig14_1

स्रोत: यूनेस्को (2018)।



लक्ष्य 4.क

शिक्षा सुविधाएं और सीखने का वातावरण

वैश्विक स्तर पर, 69% स्कूलों में पेयजल है, 66% में शौचालय हैं और 53% में बुनियादी सेवा स्तर पर स्वच्छता है या बेहतर स्वच्छता है (चित्र 14)। जॉर्डन में, 93% स्कूलों में पेयजल है, लेकिन 33% में बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था है। लेबनान में, लगभग 93% में बुनियादी स्वच्छता है, लेकिन 60% में मूल पेयजल व्यवस्था है। माध्यमिक स्कूलों की तुलना में प्राथमिक स्कूलों में निम्न सेवा गुणवत्ता है।

शिक्षा के माहौल में सुरक्षा और समावेश के कुछ पहलुओं की पूरी तरह से निगरानी की जाती है। डराने-धमकाने जैसी अवधारणाओं का विश्व की मानक परिभाषाओं में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और सर्वेक्षण व्यापक रूप से भिन्न होते

“ 2013 और 2017 के बीच, शिक्षा पर 12,700 से अधिक हमले हुए ”

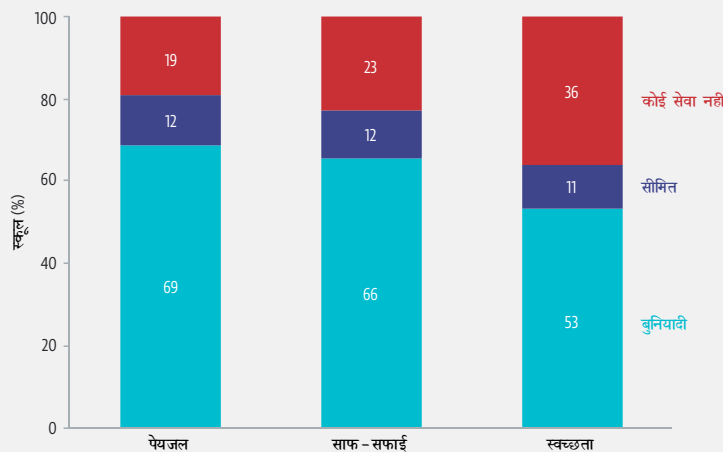
हैं। एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार 11 से 15 वर्ष के लगभग 40% लड़कों और 35% लड़कियों को डराया-धमकाया जाता है। स्कूलों में शारीरिक दंड पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या 2014 के अंत में 122 से बढ़कर 131 हो गई है।

शिक्षा को हमले से बचाने के लिए किए गए वैश्विक गठबंधन के अनुसार, 2013 और 2017 के बीच, शिक्षा पर 12,700 से अधिक हमले हुए, जिससे 21,000 से अधिक छात्रों और शिक्षकों को नुकसान हुआ। रिपोर्ट की गई घटनाओं में स्कूलों, छात्रों और शिक्षा कर्मियों पर शारीरिक हमले हुए या हमलों की धमकियां मिलीं; शिक्षा भवनों का

सैन्य उपयोग किया गया; सशस्त्र दलों द्वारा स्कूल या विश्वविद्यालय में बाल भर्ती की गई या आने-जाने के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया; और उच्च शिक्षा पर हमले किए गए। 28 देशों में कम से कम 20 हमले हुए; नाइजीरिया, फिलीपींस और यमन देशों में 1,000 से अधिक हमले हुए।

इनमें कुछ हमलों के आंकड़े नहीं हैं, जिनमें इक्वा-दुक्का बंदूकधारियों और आपराधिक गिरोहों द्वारा स्कूल में की गई गोलीबारी शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1999 के बाद से 193 स्कूलों में कम से कम 187,000 छात्रों ने स्कूल में गोलीबारी का सामना किया है।

चित्र 14: 10 स्कूलों में से 7 से कम में पेयजल बुनियादी सेवा स्तर पर है सेवा स्तर, 2016 द्वारा स्कूलों में पेयजल का वितरण, साफ-सफाई और स्वच्छता



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig15_1
 टिप्पणी: संख्याएं पूर्णांकित हैं, इसलिए इनका योग 100% नहीं भी हो सकता है।
 स्रोत: यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ (2018)।



लक्ष्य 4.ख

छात्रवृत्तियां

सहायता कार्यक्रमों द्वारा वित्त-पोषित छात्रवृत्ति 2010 से लगभग 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लागू छात्र लागत को छोड़कर) तक स्थिर रही है। हालांकि, यह संकेतक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या या सहायता कार्यक्रमों के बाहर वितरित छात्रवृत्ति के प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है।

जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी संख्या में छात्र अपने क्षेत्रों से बाहर चले जाते हैं, जबकि यूरोप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले अधिकांश छात्र इस क्षेत्र में ही रहते हैं, उनका आवागमन सक्रिय रूप से छात्र विनिमय कार्यक्रमों पर आधारित होती है। अध्ययन के स्तर से उनकी बाहर जाने की दर बढ़ जाती है, स्नातक की डिग्री के लिए 3%, मास्टर की डिग्री के लिए 6% और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए 10% (चित्र 15)।

“ यूरोपीय संघ उच्च शिक्षा नीति में कम से कम 20% स्नातकों को अपना अध्ययन विदेश में करने का लक्ष्य रखा गया है ”

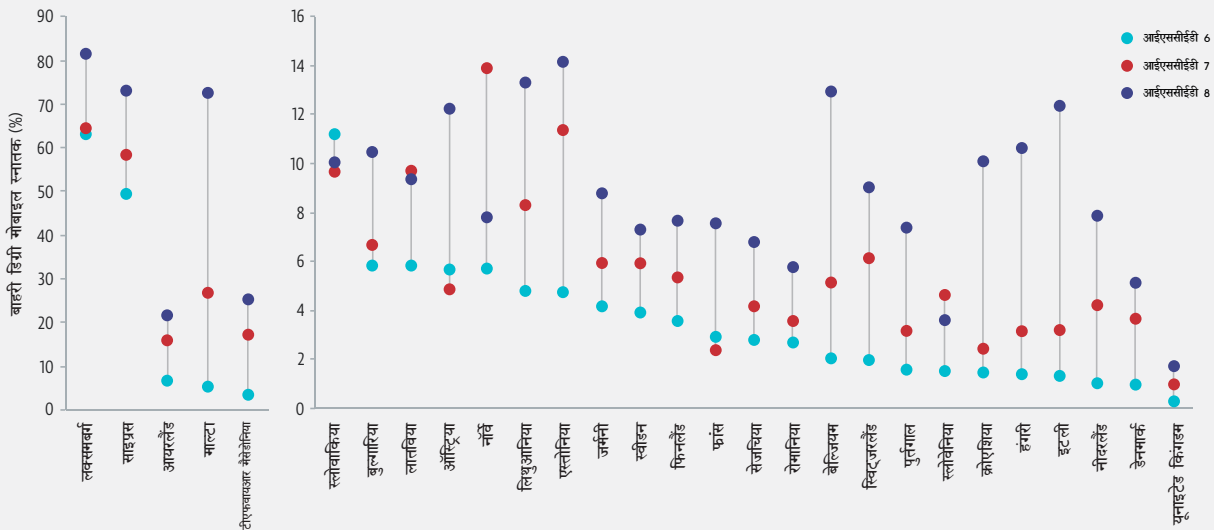
उच्च शिक्षा 2020 बेंचमार्क में ईयू शिक्षा मोबिलिटी से पता चलता है कि यूरोपीय संघ में कम से कम 20% उच्च शिक्षा स्नातकों ने कम से कम 3 महीने या यूरोपीय क्रेडिट अंतरण प्रणाली में 15 क्रेडिट के बराबर विदेश में अध्ययन किया होगा।

गृह संस्थान क्रेडिट के लिए अस्थायी मोबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए डेटा प्रदान कर सकते हैं; गंतव्य देशों को डिग्री मोबिलिटी के लिए डेटा प्रदान करना होगा। यूरोपीय संघ के देशों के लिए, रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन यूरोप के बाहर यूरोपीय संघ के छात्रों के लिए मुख्य गंतव्य देशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, इजराइल और न्यूजीलैंड आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। चीन, भारत, जापान, मेक्सिको और कोरिया गणराज्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका डेटा प्रदान नहीं करता। अधूरी कवरेज को देखते हुए, उपलब्ध अनुमान (वर्तमान में 20% से कम) संभावित रूप से बाहरी मोबिलिटी को कम आंकते हैं।

चित्र 15:

यूरोप में, अध्ययन के स्तर से छात्र के बाहर जाने की दर बढ़ जाती है

शिक्षा स्तर के अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण द्वारा विदेश में डिग्री प्राप्त करने की दर, चयनित यूरोपीय देश, 2013



जोईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig16_3

टिप्पणी: आईएससीईडी = अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानक वर्गीकरण, जिसमें स्नातक की डिग्री (आईएससीईडी 6); स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष (आईएससीईडी 7); और डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष (आईएससीईडी 8) शामिल है।

स्रोत: फलिसी एवं अन्य (2015)।



लक्ष्य 4.ग

शिक्षक

शिक्षक से संबंधित संकेतकों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक डेटा एकत्र करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अपेक्षाकृत कुछ देश, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा के लिए, शिक्षक की गणना की सबसे बुनियादी परिभाषा का उपयोग करते हुए तुलनात्मक डेटा रखते हैं, जिसमें प्रशासनिक पदों में शिक्षण के घंटों और शिक्षकों की संख्या को अनदेखा किया जाता है।

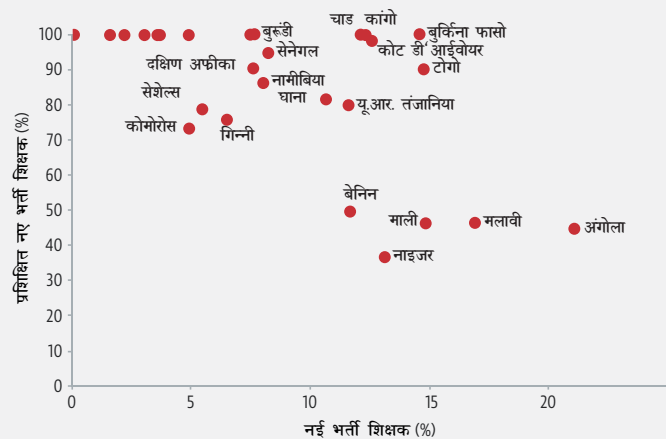
कम और निम्न मध्यम आय वाले देशों को प्रशिक्षित और योग्य प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है। कुछ उप-सहारा अफ्रीकी देशों में भर्ती दर उच्च है, जो शिक्षक की शिक्षा क्षमता सीमित होने पर दाखिला मानकों को संभावित रूप से कम कर देता है। अंगोला में, 2010 में पांच शिक्षकों में से एक से अधिक शिक्षक (21%) की नई भर्ती की गई थी, लेकिन आधे से कम (45%) प्रशिक्षित थे (चित्र 16)।

उच्च भर्ती दर सिर्फ शिक्षा विस्तार को ही नहीं दर्शाती है; वे रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। छोड़कर जाने का डेटा अस्थायी हो जाता है और इसकी व्याख्या करना मुश्किल होता है। सटीक अनुमानों के लिए कर्मियों के डेटा की आवश्यकता होती है जो पहचान संख्या निर्दिष्ट करते हैं, इसलिए व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है क्योंकि वे योग्यता, दाखिला, निकासी और पेशे में फिर से दाखिला लेते हैं। डेटा से छोड़कर जाने वालों और दाखिला लेने वालों, फिर से दाखिला लेने वालों का पता चलना चाहिए। छोड़कर जाने वालों की निगरानी करने और विविध प्रावधान वाली प्रणाली में सभी प्रकार के स्कूलों पर सूचना के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रायः उपलब्ध जानकारी केवल स्थानीय (जैसे ब्राजील) या केवल सार्वजनिक स्कूलों (जैसे यूगांडा) से संबंधित होती है।

चिली, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में किए गए अनुसंधान से उन शिक्षकों के छोड़कर जाने की घटनाएं अधिक हुई हैं जो कम अनुभवी, अधिक योग्य (और इसलिए कहीं और अधिक सेवा योग्य) थे, जिन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण या ग्रामीण स्कूलों में रखा गया था, जहां उन्हें कम भुगतान किया गया या अल्पकालिक अनुबंधों पर रखा गया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित समयावधि अध्ययनों को देखने से पता चलता है कि अधिकांश शिक्षक जो छोड़कर चले गए थे, उन्होंने ऐसा परिवार के कारणों से किया था और वे दो वर्ष के अंदर पेशे में लौट आए थे।

चित्र 16:

उच्च शिक्षा भर्ती दरों के साथ शिक्षक के शिक्षा मानकों को बनाए रखना मुश्किल है नई शिक्षक भर्ती की दर और प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा, चयनित उप-सहारा अफ्रीकी देश, 2010 - 2014



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig17_1

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

शिक्षा और अन्य एसडीजी

इस रिपोर्ट में यह जांच की गई कि शिक्षा कैसे व्यावसायिक क्षमता बढ़ाकर प्रतिष्ठित कार्य, साधन संपन्न शहरों और न्याय के विभिन्न तरीकों से संबंधित एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ा सकती है।

प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक विकास पर एसडीजी 8 प्राप्त करने के लिए कई देशों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता कम हैं। इथियोपिया में, 60% सार्वजनिक क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साक्षात्कार में कहा कि उन्हें संगत शिक्षा की कमी है। कुछ देश प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ा रहे हैं: चीन का उद्देश्य 2020 तक 230,000 नए सामाजिक कार्यकर्ता बनाना है। दक्षिण अफ्रीका में, 2010 से 2015 के बीच सामाजिक श्रमिकों की संख्या में 70% की वृद्धि हुई है।

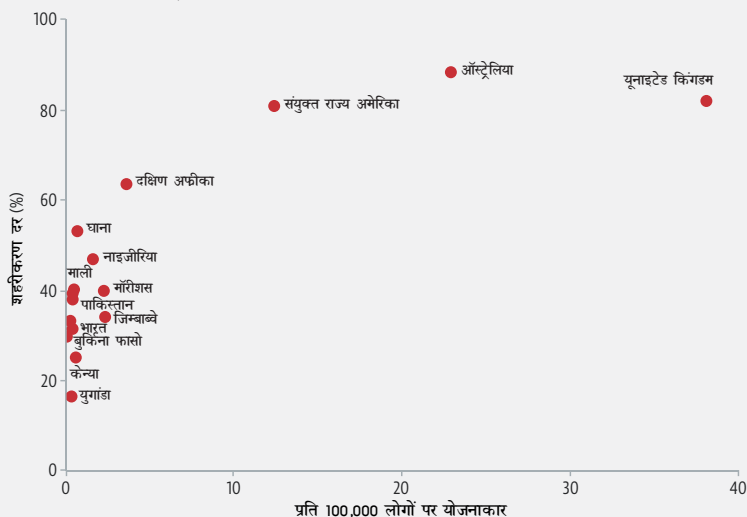
शहरों में रहने वाली आधे से अधिक आबादी, जिन्होंने साधन संपन्न शहरों और समुदायों पर एसडीजी 11 प्राप्त कर लिया है, के लिए शहरी योजनाकारों द्वारा अस्थायी बस्तियों में सुधार करना और भविष्य में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। कई देशों को नियोजन पेशेवरों (चित्र 17) की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है। 2031 तक भारत को 300,000 शहर एवं देश नियोजकों की जरूरत है; 2011 में, ये लगभग 4,500 थे। योजना कार्यक्रमों को शिक्षा सहित शारीरिक, पर्यावरण और सामाजिक नियोजन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। मलावी, मोजाम्बिक और नामीबिया सहित देशों में स्थानीय अधिकारियों को योजना क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है।

शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थानों पर एसडीजी 16 प्राप्त करने के लिए, कानून लागू करने वाले अधिकारियों की शिक्षा आवश्यकताओं और प्रशिक्षण को सुधारने की आवश्यकता है ताकि विश्वास कायम करने तथा पूर्वाग्रह और बल उपयोग कम करने में मदद मिल सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में 130 सप्ताह की तुलना में औसत पुलिस प्रशिक्षण 19 सप्ताह का दिया गया। अमेरिकी पुलिस विभागों में से केवल 1% को चार वर्ष की विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता होती है; विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त अधिकारियों द्वारा बल का उपयोग कम किए जाने की संभावना होती है। सिंगापुर सहित कुछ देशों ने पुलिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया है; इंडोनेशिया जैसे अन्य लोगों ने पुलिस पेशेवर क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग किया है।

दुनिया भर में अनुमानित 4 बिलियन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, इसका अर्थ है कि कानूनी क्षमता को बनाने की आवश्यकता है। न्यायिक शिक्षा प्रत्येक देश में अलग-अलग होती है। प्रशिक्षण आमतौर पर तीन से पांच वर्ष तक दिया जाता है, लेकिन उच्च आय वाले देशों में भी न्यायाधीश बनने के लिए कानून की डिग्री होना हमेशा कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती है। फ्रांस सहित कुछ देशों में न्यायाधीशों का चयन करने के बाद पर्याप्त प्रारंभिक पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। घाना और जॉर्डन जैसे देशों में न्यायाधीशों के लिए शिक्षा संस्थान विद्यमान हैं।

चित्र 17:

अफ्रीका और एशिया में बहुत कम शहरी योजनाकार हैं
चयनित देशों में प्रति 100,000 व्यक्ति शहरी योजनाकारों की संख्या और शहरीकरण दर



जीईएम स्टार्टलिंग: http://bit.ly/fig18_2

नोट: अनेक योजनाकारों के डेटा 2011 से लिए गए हैं जबकि शहरीकरण दर 2014 की है।

स्रोत: यूएनडीईएसए (2014); संयुक्त राष्ट्र - पर्यावास (2016ख)।

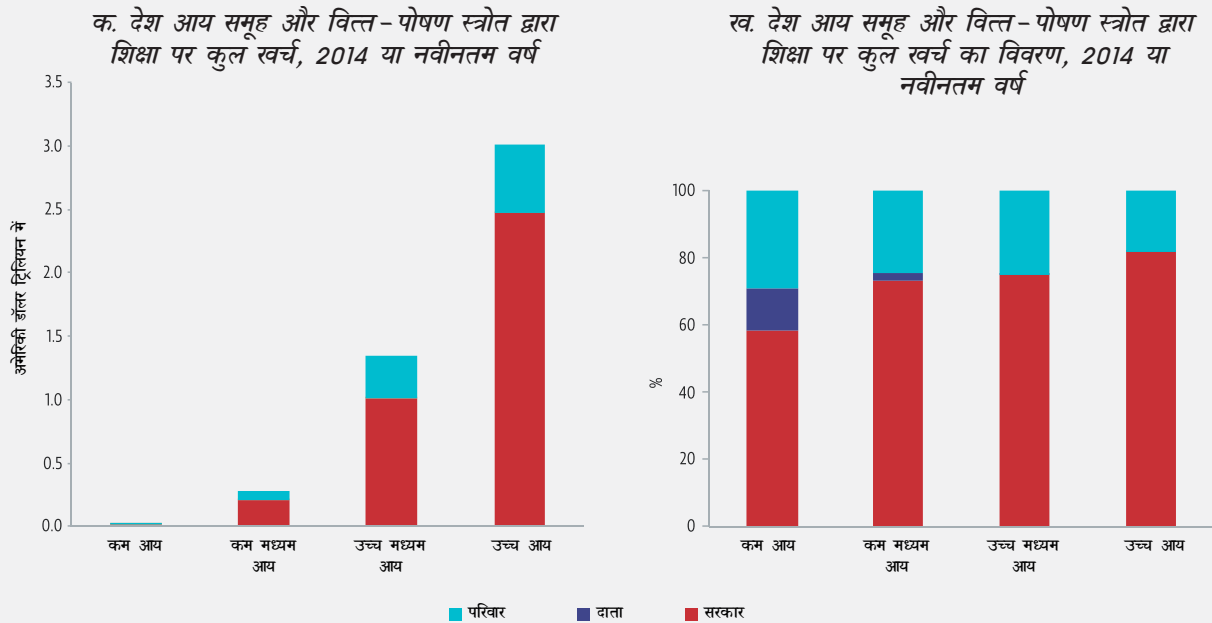
वित्त

शिक्षा वित्त-पोषण के तीन मुख्य स्रोत सरकार, दाता और परिवार हैं। इस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला है कि दुनिया भर में शिक्षा पर वार्षिक खर्च का अनुमान 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें से 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उच्च आय वाले देशों में खर्च किए जाते हैं (कुल खर्च का 65%) और कुल 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कुल खर्च का 0.5%) निम्न आय वाले देशों में खर्च किए जाते हैं, यद्यपि दोनों समूहों में स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु लगभग बराबर है। सरकार कुल व्यय का 21% खर्च करती है जबकि परिवार 12% खर्च करते हैं। कम आय वाले देशों में दाता कुल शिक्षा व्यय का 12% वहन करते हैं जबकि निम्न मध्यम आय वाले देशों में 2% वहन करते हैं (चित्र 18ख)।

“ दुनिया भर में शिक्षा पर वार्षिक खर्च का अनुमान 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें से 65% उच्च आय वाले देशों में खर्च किए जाते हैं ”

चित्र 18:

सरकार शिक्षा पर खर्च किए गए पांच डॉलर में से चार डॉलर का खर्च उठाती है 21 उच्च आय वाले देशों के पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिकवाद शामिल करना



जीईएम स्टार्टलिंग: http://bit.ly/fig19_1

नोट: विश्लेषण तीन मान्यताओं पर निर्भर करता है: (क) सार्वजनिक व्यय डेटा के बिना वाले देशों के लिए, राशि जीडीपी से ली की गई, जीडीपी के भाग के रूप में सार्वजनिक व्यय और संबंधित देश आय समूह में शिक्षा के लिए आवंटित सार्वजनिक व्यय का औसत हिस्सा; (ख) 60% सहायता व्यय को सार्वजनिक बजट (इसलिए सरकारी व्यय से घटाया गया) में दर्शाया गया माना जाता है, शेष 40% अन्य चैनलों के माध्यम से आवंटित किया जाता है; और (ग) उच्च आय वाले देशों में कुल आय व्यय में घरेलू हिस्सा 18%, मध्यम आय वाले देशों में 25% और कम आय वाले देशों में 33% होने का अनुमान है।

स्रोत: यूआईएस (सरकारी और घरेलू) और सीआरएस (दाता) डेटाबेस के आधार पर जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण।

सरकारी व्यय

वैश्विक स्तर पर, 2016 में औसत सार्वजनिक शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% था, जो क्षेत्र द्वारा शिक्षा 2030 कार्य फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट 4% के न्यूनतम बेंचमार्क से अधिक था; यह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 3.6% से लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई में 5.3% तक था। शिक्षा के लिए समर्पित कुल सार्वजनिक व्यय का औसत हिस्सा 14% था, जो 15% न्यूनतम बेंचमार्क से कम था। इसमें क्षेत्रीय दर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 11.3% से लेकर लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई में 19.1% थी। कुल मिलाकर, 143 देशों में से 39 देश कोई भी बेंचमार्क पूरा नहीं करते।

प्राथमिक शिक्षा के लिए समर्पित सार्वजनिक शिक्षा व्यय का औसत हिस्सा 35% है, जो कम आय वाले देशों में 47% से लेकर उच्च आय वाले देशों में 26% है। वैश्विक औसत के रूप में माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल शिक्षा खर्च का 35% आवंटित किया गया था; उच्च आय वाले देशों में यह सीमा 27% से उच्च आय वाले देशों में 37% थी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश प्राथमिक और माध्यमिक छात्र प्रत्येक पर समान राशि खर्च करते हैं। उप-सहारा अफ्रीका प्रत्येक प्राथमिक छात्र की तुलना में माध्यमिक छात्र पर 10 गुना अधिक खर्च करता है।

सार्वजनिक बहस में प्रायः मेजबान समुदाय हित पर आप्रवासन के नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक ओर, आप्रवासी लोगों के कामकाजी उम्र के मूल निवासी के समान होने की अधिक संभावना रहती है लेकिन आम तौर पर वे कम कर राजस्व अर्जित करते हैं क्योंकि वे कम कमाते हैं। दूसरी ओर, आप्रवासियों के सामाजिक लाभ पर निर्भर रहने और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। हालांकि, आप्रवासी बच्चों पर सार्वजनिक शिक्षा व्यय को सबसे अच्छा निवेश माना जाता है: वे आमतौर पर उनके जीवनकाल में उन्हें प्राप्त सुविधाओं से अधिक योगदान करते हैं। आप्रवासन के वित्तीय परिणाम अपेक्षाकृत मामूली हैं - जो आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का 1% हैं, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक।

सहायता व्यय

2016 में, शिक्षा के लिए सहायता 2002 में रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। 2015 की तुलना में, शिक्षा सहायता 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या वास्तविक आधार पर 13% बढ़कर 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। बुनियादी शिक्षा के लिए सहायता वृद्धि का दो-तिहाई बैठती है; माध्यमिक और माध्यमिक पश्चात् शिक्षा की सहायता कम दर पर बढ़ी, इसलिए कुल शिक्षा सहायता में बुनियादी शिक्षा का हिस्सा 45% पर अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।

बुनियादी शिक्षा के लिए सहायता वितरण अभी भी आवश्यकता वाले देशों को आवंटित नहीं किया गया है। कम आय वाले देशों को बुनियादी शिक्षा सहायता का हिस्सा 2002 में 36% से घटकर 2016 में 22% हो गया। 2016 में सबसे कम विकसित देशों का हिस्सा 34% था, जो 2004 के 47% से कम था।

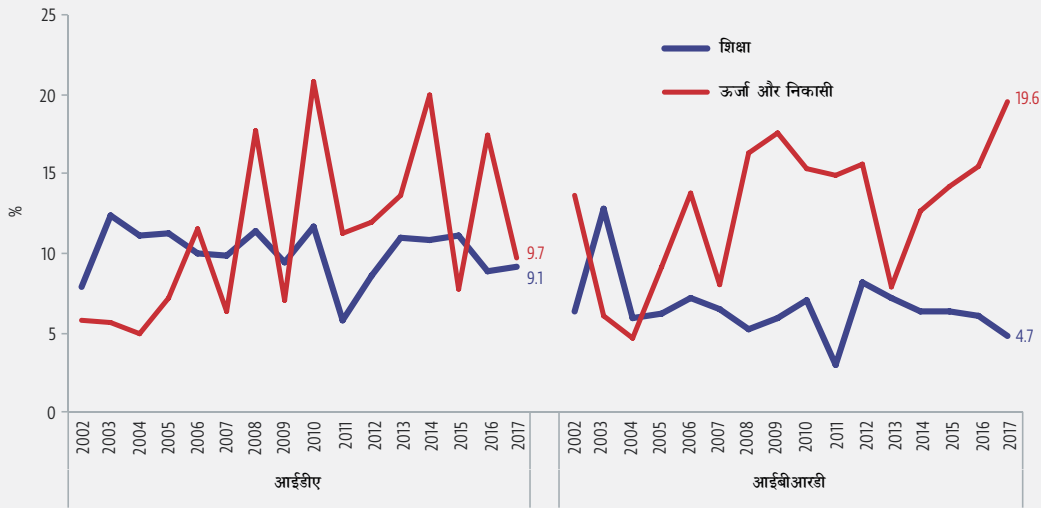
कम आय वाले देशों को बुनियादी शिक्षा सहायता का हिस्सा 2002 में 36% से घटकर 2016 में 22% हो गया।

निम्न मध्यम आय वाले देशों को भी वित्त-पोषण की कमी का सामना करना पड़ा है। इन देशों में शिक्षा के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक ऋण कम रहता है। उदाहरण के लिए, 2002 से 2017 के बीच शिक्षा का औसत हिस्सा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से रियायती ऋण के लिए 10.5% था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से गैर-रियायती ऋण के लिए यह केवल 6.4% था। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण में शिक्षा का हिस्सा 2012 में 8.2% से गिरकर 2017

में 4.7%, या ऊर्जा और निकासी क्षेत्र (चित्र 19) के लिए एक-चौथाई राशि हो गया। निम्न मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा के लिए विकास बैंक ऋण बढ़ाने के संबंध में शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त सुविधा स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वैश्विक शिक्षा अवसर वित्त-पोषण आयोग द्वारा विचार-विमर्श जारी है।

चित्र 19:

विश्व बैंक गैर-रियायती ऋण का न्यून और घटता हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है
कुल आईडीए और आईबीआरडी ऋण का हिस्सा, शिक्षा बनाम ऊर्जा एवं निकासी, 2002-2017



जीईएम स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig19_9

स्रोत: चयनित विश्व बैंक वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण।

पलायन को कम करने के लिए सहायता का एक साधन के रूप में उपयोग करना

यह विचारधारा कि बाह्य सहायता पलायन को कम कर सकती है को नीतिगत आधार पर कुछ समर्थन प्राप्त हुआ है। मूल देशों में निवल आय बढ़ने से प्रमुख प्रवासन प्रोत्साहन कम हो जाएगा। पलायन पर यूरोपीय एजेंडा और कुछ देशों की सहायता नीतियां इस विचार का समर्थन करती हैं।

210 मूल देशों से 22 दाता (और गंतव्य) देशों में हुए पलायन के एक अध्ययन से पता चलता है कि बड़ी संख्या में प्रवासियों को भेजने वाले देशों को बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता मिली है। हालांकि, संबंधों के कारण और प्रभाव को स्थापित करना मुश्किल है। यदि सहायता गरीब परिवारों तक पहुंचती है, तो यह उनकी प्रवास लागत का वित्तपोषण करने में मदद कर सकती है। सहायता दाता देशों और कम प्रवासियों की लेनदेन लागत पर भी जानकारी बढ़ा सकती है, जिससे प्रवासन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं को पलायन को नियंत्रित करने में सहायता क्या भूमिका निभा सकती है, की संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

“ अंतरराष्ट्रीय सहायता और पलायन के प्रवाह के बीच संबंध कायम करना मुश्किल होता है ”

विशेष रूप से, प्रवासन पर शिक्षा सहायता का प्रभाव, उसके छोटे आकार के कारण पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। भले ही शिक्षा के लिए सहायता, प्रवासन को कम करने में मदद करती है, फिर भी ऐसा शीघ्र करने की संभावना नहीं है। हालांकि, मूल और गंतव्य दोनों देशों के लिए प्रवासन में शिक्षा की महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका हो सकती है। उत्तरी अफ्रीका से ओईसीडी देशों में प्रवासन के रुझानों पर किए गए एक अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि मूल देशों में सहायता प्रदान करने से आय में वृद्धि निम्न शिक्षा वाले प्रवासियों के लिए आगे बढ़ने में सहायक साबित हुई थी। लेकिन यदि स्कूल और स्थानीय सार्वजनिक सेवाएं संतोषजनक हों तो पलायन को रोका जा सकता है। और कुल

मिलाकर, गंतव्य देश की जनसांख्यिकीय विशेषताएं - आबादी घनत्व, शहरी जनसंख्या वृद्धि, आयु निर्भरता अनुपात - और गंतव्य देशों में शिक्षा के लिए पुरस्कार, सहायता के स्तर की तुलना में प्रवासन दरों को निर्धारित करने में अधिक महत्वपूर्ण थी।

शिक्षा के लिए मानवीय सहायता की प्रभावशीलता में सुधार

मानवतावादी सहायता लगातार चौथे वर्ष 2017 में बढ़ी, वैश्विक मानवतावादी वित्त पोषण 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, कुल मानवतावादी सहायता में शिक्षा का हिस्सा कम से कम 4% के लक्ष्य से बहुत कम 2.1% था। अन्य क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा भी ऐतिहासिक रूप से वित्त पोषित आवश्यकताओं के सबसे कम श्रेयों में से एक है।

हालांकि, 2016 विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय शिक्षा की स्थापना के लिए आपातकाल में शिक्षा की एक नई वचनबद्धता 'शिक्षा इंतजार नहीं कर सकती (ईसीडब्ल्यू) निधि' को शामिल किया गया था।

यदि समन्वय प्रणाली की कई परतें हों तो दोनों लंबवत (वैश्विक से स्थानीय) और क्षैतिज (क्षेत्रों और कारक) दोनों, मानवतावादी सहायता को जटिल बनाती हैं और आपातकालीन स्थिति में शिक्षा के हिस्से को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र समेकित हस्तक्षेप दो तरीकों से आयोजित किए जाते हैं। मानवीय प्रतिक्रिया योजना (एचआरपी) आमतौर पर एक वर्ष से अधिक के लिए किसी देश की रणनीति प्रदान करते हैं। तत्काल अपील में तीन से छह माह में गंभीर जरूरतों को पूरा करने के लिए अचानक आपात स्थिति से निपटने का प्रस्ताव किया जाता है। एचआरपी में शिक्षा से संबंधित सामग्री सीमित है, और शिक्षा अक्सर अपीलों में प्रदर्शित नहीं होती है।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता व्यय के लिए कोई अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं है, जिससे शिक्षा खर्च की पूरी निगरानी करना मुश्किल हो रहा है। ओईसीडी विकास सहायता समिति क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली डेटाबेस क्षेत्र द्वारा डेटा को विभाजित नहीं करती है। मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वित्तीय निगरानी सेवा शिक्षा की निगरानी करती है, लेकिन 2017 में वित्त-पोषण का 42% बहुदेशीय श्रेणी में था, जिसे क्षेत्रों या गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में साझा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः गलत शिक्षा खर्च अनुमान प्राप्त हुए थे।

शिक्षा का अल्प पोषण कई क्षेत्रों में अपर्याप्तता के कारण होता है: राजनीतिक इच्छाशक्ति, लंबवत और क्षैतिज समन्वय, मानवतावादी कारक और सूचना या उत्तरदायित्व प्रणाली।

2015 के एक लागत अध्ययन ने 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्त-पोषण अंतर का अनुमान लगाया, जिसे अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कवर किया जाना चाहिए। यह प्रति बच्चे 113 अमेरिकी डॉलर है - अर्थात् वर्तमान प्रति छात्र खर्च में दस गुना वृद्धि। ईसीडब्ल्यू का लक्ष्य प्रति वर्ष 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है और 2021 तक 1.2 प्रतिशत अंकों से शिक्षा के हिस्से की मानवीय सहायता में वृद्धि करना है। इसके भागीदारों को विकास सहायता के भीतर मानवीय उद्देश्यों को प्राथमिकता देने या मानवतावादी सहायता के भीतर शिक्षा की प्राथमिकता में वृद्धि करने के लिए निधियां जुटाने के प्रयासों को साझा करने की आवश्यकता होगी।

संगठन जिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं, उनके अनुसार योजनाएं निर्धारित नहीं की जानी चाहिए (बल्कि, ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जो अच्छी गुणवत्ता वाली समग्र और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करते हैं)। वैश्विक शिक्षा समूह ने आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। एक प्रमुख नए कारक के रूप में, ईसीडब्ल्यू इन दिशानिर्देशों को भागीदारों की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम डिजाइन में उपयोग करने और उनकी क्षमता विकसित करने के लिए लागू कर सकता है।

मानवीय सहायता को मुख्य कारकों में और उनके बीच समन्वय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुआयामी मानवतावादी कार्यक्रमों में शिक्षा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट में, शिक्षा को राहत प्रतिक्रिया के पहले चरण से शामिल किया गया था, और शिक्षा सेवा वितरण बहुत जल्दी शुरू हुआ था। हालांकि, समन्वय की कमी का अर्थ है कि सीखने के केंद्र कभी-कभी खाली रहते थे, क्योंकि शिक्षा से अलग कार्यक्रमों की शिक्षा के समय में बाधा बनते थे।

संकट में बच्चों की सबसे बुनियादी शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के मानवीय सहायता में शिक्षा के हिस्से की आवश्यकता होगी...



मानवतावादी और विकास कारकों के बीच संयुक्त योजना की भी आवश्यकता है। जबकि बहुआयामी योजना ने रोहिंग्या मानवीय प्रतिक्रिया में शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद की, लेकिन उसने बांग्लादेशी शिक्षा प्रणाली में शामिल होना सुनिश्चित नहीं किया। दीर्घकालीन संकटों में बहु वर्षीय अपीलों को कम किया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा योजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से लचीलापन या संकट प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। यूगांडा में अल्पकालिक मानवतावादी शिक्षा योजना ढांचे को और अधिक ढांचागत विषयों के साथ जोड़ा जाना जरूरी है, जहां मई 2018 में घोषित सरकार की शरणार्थी और मेजबान सामुदायिक शिक्षा प्रतिक्रिया योजना, लगभग 675,000 शरणार्थी और मेजबान समुदाय के छात्रों के लिए प्रति वर्ष 395 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करती है।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम जैसे दाता मानवतावादी भागीदारों को अनुमानित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए बहुवर्षीय वित्त-पोषण ढांचे में स्थानांतरित कर रहे हैं, और ईसीडब्ल्यू के पास 'बहु-वर्षीय लचीलापन साधन है, जिसका उद्देश्य मानवतावादी विकास में अंतर को कम करना है। मानवीय सहायता में जवाबदेही को सुदृढ़ करने की जरूरत है। ईसीडब्ल्यू ने अपने कार्यनीतिक परिणामों के ढांचे में उच्च मानकों को स्थापित करके पारदर्शिता और परिणामों पर जोर दिया है, जिसमें न केवल इसके अंतिम परिणाम शामिल हैं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से, काम करने का तरीका और इसकी परिचालन दक्षता शामिल है।

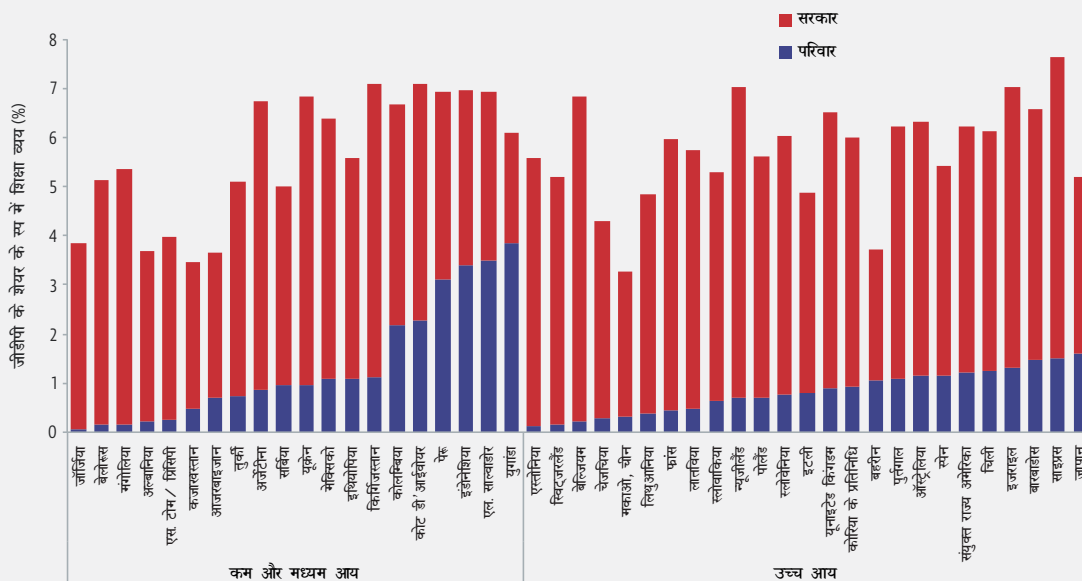
परिवार का खर्च

परिवार अंशदान पर डेटा न होने के कारण कुल शिक्षा व्यय का दीर्घकालिक विश्लेषण सीमित होता है। यूआईएस ने पहली बार 2017 में परिवारों का डेटा जारी किया, लेकिन उसकी कवरेज सीमित थी। कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कुल शिक्षा व्यय में परिवारों का हिस्सा बहुत अधिक हो सकता है, उदाहरण के लिए, एल साल्वाडोर (50%) और इंडोनेशिया (49%) (चित्र 20)।

आम तौर पर, परिवार व्यय डेटा कुछ अपवादों को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष नाटकीय रूप से नहीं बदलता है। चिली में, सरकारी शिक्षा वित्त-पोषण पर्याप्त न होने पर बड़े पैमाने पर छात्र विरोध ने सार्वजनिक नीति में बदलाव किए। परिणामस्वरूप, कुल शिक्षा खर्च का घरेलू हिस्सा 2005 से 2015 के बीच लगभग 50% से घटकर 20% रह गया।

चित्र 20:

कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में घरेलू शिक्षा खर्च काफी अधिक है
निधियों के स्रोत द्वारा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय तथा देश आय समूह, चयनित देश, 2013-2017



जीईएस स्टार्टलिक: http://bit.ly/fig19_13
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

सिफारिशें

यह रिपोर्ट सरकारों को प्रवासी और विस्थापित आबादी, और उनके बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं का समाधान करने का आह्वान करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वे मेजबान जनसंख्या का करते हैं।

प्रवासियों और विस्थापित लोगों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा करें

शिक्षा में भेदभाव न करने के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मान्यता दी गई है। जन्म प्रमाण-पत्र आवश्यकताओं जैसी भेदभाव वाली बाधाओं को राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। मौजूदा नियमों में व्यक्तिगत स्थानीय या स्कूल स्तर के अधिकारियों द्वारा व्याख्या में कोई खामी नहीं होनी चाहिए या खराब प्रभाषित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। सरकारों को पहचान-पत्र दस्तावेजों या निवास की स्थिति की अनिवार्यता के बिना प्रवासियों और शरणार्थियों को शिक्षा के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और अपवाद के बिना कानून लागू करना चाहिए।

शिक्षा के अधिकार का सम्मान कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया से परे होना चाहिए। राष्ट्रीय अधिकारियों को अपने अधिकारों और स्कूल पंजीकरण प्रक्रियाओं के प्रवासी और विस्थापित परिवारों को जानकारी देने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। योजना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्कूल अनौपचारिक बस्तियों और झोपड़ियों के निकट हैं और शहरी सुधार योजनाओं में उन्हें उपेक्षित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्रवासियों और विस्थापित लोगों को शामिल करें

कुछ शिक्षा प्रणालियां आप्रवासियों और शरणार्थियों को अस्थायी आबादी के रूप में देखते हैं, जो मूल निवासी से अलग हैं। यह गलत है; यह उनकी अकादमिक प्रगति, सामाजिकरण और भविष्य के अवसरों को बाधित करता है, और विविध, समेकित समाज की विविध प्रगति को कम करता है। सार्वजनिक नीति में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा के सभी स्तरों में शामिल किया जाना चाहिए।

आप्रवासियों को शामिल करने के कई आयाम हैं। जबकि शिक्षा की एक नई भाषा प्रारंभिक कक्षाओं की आवश्यकता होती है, छात्रों को अपने मूल सहकर्मियों से जितना कम हो, अलग रखा जाना चाहिए। शिक्षा प्रणालियों को कम उपलब्धियों वाले छात्रों को पृथक नहीं करना चाहिए, जिनमें आप्रवासियों की संख्या विभिन्न जगहों पर अधिक हो। कई देशों में आप्रवासी छात्रों की भौगोलिक बहुलता को देखते हुए, शिक्षा योजनाकारों को परिवहन सब्सिडी और यादृच्छिक स्कूल कार्यों जैसी विधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवासीय पृथकता के परिणामस्वरूप शिक्षा पृथकता न हो।

सरकारों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि शरणार्थियों की शिक्षा कम से कम बाधित हो। जबकि असाधारण परिस्थितियों - उदाहरण के लिए शरणार्थी समुदायों को अलग रखना या मेजबान प्रणाली की क्षमता बाधित होने से - पूर्ण समग्रता रूक सकती है, सरकारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन न करने या मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र न लेने वाले स्कूलों में बिताए गए समय को कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह शिक्षा मार्ग से समझौता किया जाता है।

प्रवासियों और विस्थापित लोगों की शिक्षा आवश्यकताओं को समझें और योजना बनाएं

अधिक आप्रवासी और शरणार्थी प्रवाह वाले देशों को प्रबंधन सूचना प्रणाली में इन आबादी के आंकड़ों के अनुसार योजना और बजट के लिए डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए स्कूल स्थल या कार्य के अवसर प्रदान करना शामिल करने का पहला कदम है।

स्कूल के वातावरण को छात्रों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नई भाषा को सीखने वाले लोगों को योग्य शिक्षकों के साथ कार्यक्रमों का तालमेल बनाने की आवश्यकता होती है। जिनकी शिक्षा बाधित हो गई थी, उन्हें त्वरित शिक्षा कार्यक्रमों से फायदा होगा, जिससे उन्हें उचित स्तर पर स्कूल में पढ़ाई शुरू करने और पुनः दाखिला लेने में मदद मिलेगी। शिक्षा में शरणार्थियों के शामिल होने की संभावना अधिक होगी यदि शरणार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक विस्तार हो, उदाहरण के लिए, छिपी स्कूल लागतों को कवर करने वाला सशर्त नकदी हस्तांतरण। आंतरिक प्रवासियों के मामले में, सरकारों को विशेष रूप से खानाबदोश या मौसमी श्रमिकों के बच्चों को लचीले स्कूल कैलेंडर, शिक्षा निगरानी प्रणाली और उनकी आजीविका के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

वयस्कों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को विकसित करने और कम कौशल वाले व्यवसायों या प्रशिक्षण की उच्च लागतों जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जो कौशल में उनके निवेश को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि वे अपनी आर्थिक परिस्थितियों का प्रबंधन कर सकें, अधिक से अधिक धन घर भेज सकें और धोखाधड़ी या वित्तीय शोषण से बच सकें। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जिन्हें स्थानीय सरकारी स्तर पर दिया जा सकता है, समाज में एकजुटता को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहायक की भूमिका निभा सकते हैं।

पूर्वाग्रहों की चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा में पलायन और विस्थापन के इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करें

समाज को एकजुट करने और लोगों को एक साथ रहने में मदद करने के लिए केवल सहिष्णुता की ही आवश्यकता नहीं होती। सरकारों को शिक्षा सामग्री की समीक्षा करनी चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम अपनाने चाहिए और ऐसी पाठ्यपुस्तकों पर पुनर्विचार करना चाहिए जो इतिहास और वर्तमान विविधता को सही ढंग से दर्शाएं। शिक्षा की पठन सामग्री में प्रावासियों द्वारा धन अर्जन करने और समृद्धि में दिए गए योगदान को प्रमुखता से दर्शाए जाने की जरूरत है। इसमें तनाव और संघर्ष के कारणों के साथ-साथ विस्थापित या हाशिए पर रहने वाले प्रावासियों की विरासत को भी उजागर किया जाना चाहिए। शैक्षणिक दृष्टिकोण ऐसे होने चाहिए जिनसे अनेक विचारधाराओं में खुलापन आए, जिनसे एक साथ रहने के मूल्यों को बढ़ावा मिले, और विविधता से होने वाले फायदों को दर्शाया जाना चाहिए। उन्हें पक्षपातपूर्ण रवैए को चुनौती देनी चाहिए और व्यापक सोच विकसित करनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को अन्य संस्कृतियों के साथ बातचीत करने और आप्रवासियों और शरणार्थियों के नकारात्मक मीडिया चित्रण का विरोध करने में किसी संदेह को दूर किया जा सके। सरकारों को अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा के सकारात्मक अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता है।

विविधता और कठिनाई से निपटने के लिए प्रवासियों और शरणार्थियों के शिक्षकों को तैयार करें

शिक्षकों को प्रवासन और विस्थापन को ध्यान में रखते हुए स्कूल के माहौल में बदलाव लाने के लिए एजेंट की भूमिका निभाने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।

प्रवासन की समस्या से निपटने वाले वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अस्थायी होने चाहिए और मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। सरकारों को शुरुआती और चल रही शिक्षक शिक्षा में निवेश करना चाहिए जिससे मूल क्षमताओं और विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़े, जिसका प्रभाव देशी छात्रों पर भी पड़े। प्रवासन और विस्थापन के बारे में सभी शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, न केवल उन्हीं लोगों की, जो विभिन्न कक्षाओं को पढ़ते हैं। इच्छुक और पेशेवर शिक्षकों और स्कूल के नेताओं को कक्षाओं, स्कूल के परिसर और समुदाय में रूढ़िवादी, पूर्वाग्रह और भेदभाव से निपटने तथा आप्रवासी और शरणार्थी छात्रों में आत्म-सम्मान और अपनेपन की भावना को सशक्त करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।

शिक्षकों को विस्थापित छात्रों और उनके माता-पिता द्वारा सामना की जा रही विशेष कठिनाइयों, और उनके समुदायों से पहुंच बनाने के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। हालांकि शिक्षक परामर्शदाता नहीं हैं, फिर भी उन्हें तनाव और उत्पीड़न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और विशेषज्ञों की आवश्यकता में उनको संदर्भित किया जा सकता है। यदि कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो शिक्षकों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ परिवारों को ऐसी सेवाओं की जरूरत होती है। शरणार्थियों और विस्थापित शिक्षक खुद अतिरिक्त तनाव में होते हैं। प्रबंधन नीतियों में कुछ शिक्षकों द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों को पहचाना जाना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए; मनोबल बनाए रखने के लिए शिक्षण पेशेवरों में समानता सुनिश्चित करनी चाहिए; और पेशेवर विकास में निवेश करना चाहिए।

प्रवासियों और विस्थापित लोगों की क्षमता को सुदृढ़ करें

प्रवासियों और शरणार्थियों के पास ऐसी क्षमता हो सकती है जो न केवल उन्हें और उनके परिवारों के जीवन को बदलने में मदद कर सकती है बल्कि मेजबान और मूल देशों, दोनों की अर्थव्यवस्था और समाज को भी बदलने में मदद कर सकते हैं, भले ही वापस आए या वे दूर से ही सहायता करें। इस क्षमता का उपयोग अकादमिक योग्यता और पेशेवर कौशल (शिक्षकों

सहित) और पूर्व शिक्षा, जो मान्य या प्रमाणित नहीं थी, को पहचानने के लिए सरल, सस्ते, अधिक पारदर्शी और लचीले तंत्र की आवश्यकता होती है।

देशों को परस्पर योग्यता को पहचानने के संबंध में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन प्रतिबद्धताओं के लिए वैश्विक समझौते का अनुपालन करना चाहिए, और उच्च शिक्षा योग्यता की मान्यता पर वैश्विक सम्मेलन के तहत वार्ता करके निष्कर्ष निकालना चाहिए ताकि इसे 2019 में अपनाया जा सके। आकलन एजेंसियां, लाइसेंसिंग निकाय और अकादमिक संस्थानों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सरकारों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते हुए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं में तालमेल स्थापित करना चाहिए। इसमें सामान्य डिग्री मानक, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली और अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम योग्यता को मान्यता प्रदान करने का समर्थन कर सकते हैं।

प्रवासियों और विस्थापित लोगों की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवतावादी और विकास सहायता द्वारा मदद करें

जबकि दो-तिहाई अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को उच्च आय वाले देशों में जाते हैं, 10 शरणार्थियों में से 9 शरणार्थी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता में शिक्षा के क्षेत्र में दस गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसका एक अधिक स्थायी समाधान यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय शरणार्थियों और मेजबान जनसंख्या को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का समर्थन करे तथा संकट के शुरुआती चरण से ही मानवतावादी और विकास सहायता प्रदान करके शरणार्थियों पर हुए वैश्विक समझौते और व्यापक शरणार्थी प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क प्रतिबद्धता को पूरा करे। शिक्षा में विशेषकर बचपन की शिक्षा और देखभाल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अन्य क्षेत्रों से जुड़े समाधानों के समग्र पैकेज का भी हिस्सा होना चाहिए, उदाहरण के लिए आवास, पोषण, पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा। दाताओं को अपने मानवीय हस्तक्षेपों में इन सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा निधियां उपलब्ध होने का इंतजार नहीं कर सकती, को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यकता-निर्धारण क्षमता विकसित करनी चाहिए, मानवतावादी विकास में अंतर को कम करने तथा कई वर्षों तक वित्त-पोषण करने का अनुमान लगाने के लिए योजना बनानी चाहिए।

पलायन, विस्थापन और शिक्षा: संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं

2019 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट सभी जनसंख्या आंदोलनों में प्रवासन और विस्थापन के शिक्षा प्रभाव: रोजगार और शिक्षा के लिए देश की सीमा के भीतर हों या उसके बाहर, स्वैच्छिक हो या बाध्य, की जांच करती है। यह सतत् विकास के लिए 2030 के एजेंडा में शिक्षा पर हुई प्रगति की भी समीक्षा करती है।

बढ़ती विविधता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में यह विश्लेषण किया गया है कि कैसे शिक्षा संपूर्ण समाज का निर्माण कर सकती है और लोगों को सहिष्णुता से आगे बढ़कर एक साथ रहने की सीख दे सकती है। समान शिक्षा प्रदान करने पर संबंध बनते हैं; ऊंच-नीच करने से प्रवासियों एवं शरणार्थियों तथा उनके मेजबान समुदायों के बीच खाई बढ़ती है।

प्रवासियों और शरणार्थियों पर किए गए दो नए वैश्विक समझौतों में शिक्षा की भूमिका को पहचाना गया है और कोई भी पीछे ने छूट जाए, इसके लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यह रिपोर्ट इन समझौतों के लिए एक महत्वपूर्ण टूलकिट है, जिसमें नीतिगत मुद्दों को शामिल किया गया है जो मौसमी प्रवासियों, ग्रामीण स्कूलों को सुदृढ़ बनाने, अंतर-सांस्कृतिक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में शरणार्थी को शामिल करने और पृथकता से निपटने, शिक्षा योग्यता को मान्यता देने, स्कूल वित्त-पोषण पर ध्यान देने, अधिक प्रभावी मानवतावादी शिक्षा सहायता प्रदान करने और आपातकाल, दीर्घकालिक और नए सामान्य संदर्भों में विविध कक्षाओं के लिए शिक्षक को तैयार करने से संबंधित हैं।

यह रिपोर्ट शिक्षा को देशों को प्रवासन और विस्थापन से निपटने के लिए एक साधन के रूप में देखती है और जिन लोगों को इनकी जरूरत है, उनके लिए यह एक अवसर है।

शिक्षा एक मानवाधिकार है तथा यह गरीबी हटाने, स्थिरता लाने और शांति कायम करने में अहम और परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है। लोग काम करने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे स्वेच्छा से हो या मजबूरी से, एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते हैं, लेकिन इससे उनके शिक्षा का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। 2019 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने की व्यापक संभावनाएं और अवसर हैं कि प्रवासियों और विस्थापित लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो।

एंटोनियो ग्युटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव

यह रिपोर्ट अतुलनीय अवसरों की तस्वीर पेश करते हुए प्रवासन और शिक्षा पर मौजूदा साक्ष्य को एक साथ प्रस्तुत करती है, और यह बताती है कि शैक्षिक नुकसान कहां और क्यों हो सकता है। और यह उस समय बताया जा रहा है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है और विश्व स्तर पर प्रवासन के लाभ को अधिकतम करता है।

विलियम लेसी स्विंग, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन
महानिदेशक संगठन (1 अक्टूबर 2008 से
30 सितंबर 2018)

यह रिपोर्ट शरणार्थियों पर हुए वैश्विक समझौते के शिक्षा आयामों तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों और शिक्षा क्षेत्र योजनाओं में शरणार्थियों को शामिल करने की अनिवार्यता की पुरजोर सिफारिश करती है।

फिलिप्पो ग्रांडी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त

